रजिस्ट्री सं० डी (डी) 73 REGISTERE No D(D)-73

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13, 1975/अग्रहायण 22, 1897
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13, 1975/AGRAHAYANA 22, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1975

का० आ० 5231.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 349-निधौली कलां निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री चन्द्र भान सिंह (निधौली कलां) ग्राम व डा० निधौली कलां जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री चन्द्र भान सिंह (निधौली कलां) को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/349/74(306)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1975

S.O. 5231.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Chandra Bhan Singh (Nidhauli Kalan), Village & P.O. Nidhauli Khan, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 349-Nidhauli Kalan assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Chandra Bhan Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/349/74(306)]

आदेश

का० आ० 5232.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 349-निधौली कलां निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

श्री राजवीर सिंह ग्राम व डाकघर त्रिलोकपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजवीर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/349/74(307)]

ORDER

S.O. 5232.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajvir Singh, Village and Post Office Tilokpur, District Etah, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 349-Nidhauli Kalan assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajvir Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/349/74(307)]

आदेश

का० आ० 5233.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टूंडला (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू, ग्राम नगरुआ, पो० आ० हिरनगऊ, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/354/74(308)]

ORDER

S.O. 5233.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu, Village Nagarua, Post Office Hiran Gau, District Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(308)]

आदेश

का० आ० 5234.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टूंडला (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबू राम, मकान नं० 21-गढ़ी पुरानी, पो० आ० हिम्मतपुर, फिरोजाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबू राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/354/74(309)]

ORDER

S.O. 5234.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Ram, House No. 21-Garhi Purani, Post Office Himmatpur, Firozabad, District Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC), assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Ram to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(309)]

आदेश

का० आ० 5235.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टूंडला (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रंजन लाल, 436-नई बस्ती, फिरोजाबाद जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रंजन लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/354/74(310)]

ORDER

S.O. 5235.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rajan Lal, 436-Nai Basti Firozabad Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rajjan Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(310)]

आदेश

का० आ० 5236.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टूंडला (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजा राम सिंह, ग्राम गुधाई थाना नरखी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजा राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/354/74(311)]

ORDER

S.O. 5236.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raja Ram Singh, Village Gondhai, Police Station Narkhi, District Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raja Ram Singh to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(311)]

आदेश

का० आ० 5237.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टूंडला (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह नागर, 13/183, नाला बुधान सैयद, थाना हरी पर्वत, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सिंह नागर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/354/74(312)]

ORDER

S.O. 5237.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Singh Nagar, 13/183, Nala Budhan Saiyad, Thana Hari Parbat, District Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC), assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Singh Nagar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament

or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(312)]

आदेश

का० आ० 5238.--यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टुंडला (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सूबेदार, ग्राम नगला अमान नैपई, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सूबेदार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/354/74(313)]

ORDER

S.O. 5238.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Subedar, Village Nagla Aman Naipai, District—Agra, Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla (SC) assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Subedar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(313)]

आदेश

का० आ० 5239.--यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 1974 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 354-टुंडला (अ०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हीरा लाल, 598, जलेसर रोड, फिरोजाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हीरा लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निर्रहित घोषित करता है।

[सं०उ०प्र०वि०स०/354/74(314)]

ए० एन० सैन, सचिव

ORDER

S.O. 5239.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hira Lal, 598—Jalesar Road, Firozabad, Agra—Uttar Pradesh, a contesting candidate for election to the U.P. Legislative Assembly from 354-Tundla(SC), assembly constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for such failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hira Lal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/354/74(314)]

A. N. SEN, Secy.

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1975

का० आ० 5240.--एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स उन्नाटी कारपोरेशन के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 501/70 दिनांक 11 नवम्बर 1970) के निरस्तीकरण की अधिसूचित करती है।

[संख्या 9/1201/70-एम० 2]

एम० सी० वर्मा, उप-सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 25th November, 1975.

S.O. 5240.—In pursuance of sub-section (3) of section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/S UNNATI CORPORATION under the said Act (Certificate of registration No. 501/70 dated the 11th November, 1970).

[F. No. 9/1201/70-M. II]

M. C. VARMA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1975

आयकर

का० आ० 5241.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वी० के० गुप्ता को जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के अधीन कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

2. अधिसूचना सं० 606 (फा०सं० 404/133/74-आई टी सी सी) तारीख 2 मई, 1974 द्वारा की गई श्री के०के० राय की नियुक्ति उस तारीख से रद्द की जाती है जिस तारीख को श्री वी०के० गुप्ता कर वसूली अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे ।

3. यह अधिसूचना तुरंत प्रवृत्त होगी ।

[सं० 1083 (फा०सं० 404/103/75-आई टी सी सी)]

वी० पी० मित्तल, उपसचिव ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

INCOME-TAX

New Delhi, the 17th September, 1975

S.O. 5241.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (44) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby authorises Shri V. K. Gupta, who is a Gazetted Officer of the Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery Officer under the said Act.

2. The appointment of Shri K.K. Raj made in Notification No. 606 (F. No. 404/133/74-ITCC) dated 2nd May, 1974 is cancelled with effect from the date Shri V. K. Gupta takes over as Tax Recovery Officer.

3. This Notification shall come into force with immediate effect.

[No. 1083 (F. No. 404/103/75-ITCC)]

V. P. MITTAL, Dy. Secy.

बीमा

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1975

का० आ० 5242.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि साधारण बीमा कारबार को और अधिक दक्षतापूर्वक चलाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) की धारा 16 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमाकर्ताओं के अधीन सेवा कर रहे अधिकारियों के वेतनमान और सेवा के अन्य निबन्धनों और शर्तों के सुव्यवस्थीकरण के लिए उपबन्ध करने हेतु निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस स्कीम का नाम साधारण बीमा (अधिकारियों के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण) स्कीम, 1975 है ।

(2) यह 1975 के सितम्बर के प्रथम दिन प्रवृत्त होगी ।

2. लागू होना.—इसमें सम्मिलित उपबन्ध निम्नलिखित सभी अधिकारियों को लागू होंगे, अर्थात्:—

(i) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी में या किसी विद्यमान बीमाकर्ता के अधीन, 31 दिसम्बर, 1972 को पूर्णकालिक अधिकारियों के रूप में पुष्ट हो गए थे;

(ii) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी में या किसी विद्यमान बीमाकर्ता के अधीन 31 दिसम्बर, 1972 को पूर्णकालिक अस्थायी अधिकारी थे और इस स्कीम के आरम्भ के पूर्व पुष्ट हो गए थे;

(iii) जो इस स्कीम के आरम्भ के पूर्व भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी में या निगम में आमेलित कर लिए गए हैं या जिनकी सेवाएं उनमें से किसी को अन्तरित कर दी गई हैं;

(iv) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी की या निगम की सेवा में 1 जनवरी, 1973 को या उसके पश्चात् सम्मिलित हुए थे और इस स्कीम के आरम्भ के पूर्व अधिकारी के रूप में पुष्ट हो गए थे;

(v) जो इस स्कीम के आरम्भ पर निगम के या कम्पनी के पूर्णकालिक अस्थायी अधिकारी या परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं,

किन्तु यह स्कीम निम्नलिखित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) जो भारतीय बीमा कम्पनियों में से किसी में या निगम में प्रतिनियुक्त हैं और जिन्होंने इस स्कीम के आरम्भ के पूर्व अपने मूल कार्यालय वापस लौटने का निश्चय किया था अथवा वापस लौटा दिए गए थे;

(ख) जिन्हें नियोजन की विनिर्दिष्ट संविदा के अधीन नियोजित किया जाए;

(ग) जो अंशकालिकतः नियोजित हैं;

(घ) इस स्कीम के आरम्भ के पूर्व जो सेवानिवृत्त हो गए थे, या पदत्याग कर चुके थे, या जिनकी सेवाएं पर्यवसित कर दी गई थीं ।

3. परिभाषाएं.—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) अभिप्रेत है;

(ख) "आधारी वेतन" से, यथास्थिति, प्रथम अनुसूची, या द्वितीय अनुसूची, या तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट आधारी वेतन अभिप्रेत है—

(ग) "बोर्ड" से निगम का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है—

(i) निगम के सम्बन्ध में, अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक; और

(ii) कम्पनी के सम्बन्ध में, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक;

(ङ) "कम्पनी" से, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, दि ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, या दि युनाइटेड इण्डिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, अभिप्रेत है;

(च) "निगम" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित भारत का साधारण बीमा निगम अभिप्रेत है;

(छ) "विद्यमान बीमाकर्ता" से भारतीय बीमा कम्पनी से भिन्न बीमाकर्ता अभिप्रेत है जिसके अधिकारी किसी ऐसी भारती

बीमा कम्पनी में अधिकारी बन गए हैं जिसमें उस बीमाकर्ता का उपक्रम या उपक्रम का वह भाग, जिससे कि वे अधिकारी सम्बन्धित हैं, अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन निहित हो गया है;

(ज) "विद्यमान वेतनमान" से, अधिकारी द्वारा नए वेतनमान के अधीन उसका वेतन नियत किए जाने के पूर्व, के वह वेतनमान अभिप्रेत है जिसमें वह वेतन ले रहा था;

(झ) "सकल उपलब्धियां" से अभिप्रेत है आधारी वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाटक भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता ;

(ञ) "नया वेतनमान" से प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुसूची में दिया गया वेतनमान अभिप्रेत है;

(ट) "नए निबन्धनों" से,—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी के सम्बन्ध में, प्रथम अनुसूची में उपवर्णित वेतनमान और अन्य भत्ते; अभिप्रेत है ;

(ii) (क) साधारण प्रबन्धक या सहायक साधारण प्रबन्धक या प्रबन्धक या उस प्रबन्धक या सहायक प्रबन्धक या प्रशासनिक अधिकारी, या सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वर्गीकृत अधिकारियों के सम्बन्ध में, द्वितीय अनुसूची में;

(ख) कनिष्ठ अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत अधिकारी के सम्बन्ध में, तृतीय अनुसूची में, यथावर्णित वेतनमान, महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते, अभिप्रेत हैं ।

(ठ) "अधिकारी" से इस स्कीम के आरम्भ के पूर्व भारत में नियुक्त किया गया और भारत में अथवा भारत के बाहर पर्यवेक्षीय, लिपिकीय या अधीनस्थ हैसियत से भिन्न हैसियत में सेवारत, और अनुसूचियों में निर्दिष्ट पदों में से किसी को धारण करने वाले के रूप में वर्गीकृत कर्मचारी अभिप्रेत है, किन्तु इसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई समिति द्वारा विकास कर्मचारिवृन्द के सदस्य के रूप में घोषित कर्मचारी सम्मिलित नहीं है;

(ड) "वर्तमान सकल उपलब्धियां" से, अधिकारी द्वारा वर्तमान वेतनमान में, पैरा 4 के उपपैरा (1) के अधीन उसके द्वारा किए गए विकल्प की तारीख पर, ली गई सकल उपलब्धियां अभिप्रेत हैं, जिनमें वेतन, गृह भाटक भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता, अर्हता वेतन, पहाड़ी आस्थान भत्ता, भोजन भत्ता, नकद में संदत्त भोजन भत्ता और विकास भत्ता सम्मिलित है तथा अन्य नियत नकद भत्ते जैसे कि वे 1 जनवरी, 1973 को देय हों, तथा कोई अन्य भत्ता, जो बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से अवधारित करे, भी आते हैं;

(ढ) "वर्तमान सकल वेतन" से, अधिकारी द्वारा विद्यमान वेतनमान में, पैरा 4 के उपपैरा (1) के अधीन उसके द्वारा किए गए विकल्प की तारीख पर, लिया गया सकल वेतन अभिप्रेत है, जिसमें आधारी वेतन, तदर्थ विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता, महंगाई भत्ता, या कोई अन्य भत्ता, जो महंगाई भत्ते की किस्म का हो, तथा अन्तरिम साहाय्य भत्ता, सम्मिलित हैं;

(ण) "अनुसूची" से इस स्कीम से उपावद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

(त) "विशेष वेतन" से अभिप्रेत है पद या कर्मचारी की परिलब्धियों में,—

(i) कर्त्तव्यों की विशेष कठिन प्रकृति के आधार पर; या

(ii) कार्य या उत्तरदायित्व में विनिर्दिष्ट रूप से वृद्धि के आधार पर,

वेतन की प्रकृति की अतिरिक्त रकम ।

4. अधिकारियों के वेतन और भत्ते—(1) वेतनमान और अन्य भत्ते प्रथम, द्वितीय और तृतीय अनुसूची में उल्लिखित के अनुसार होंगे।

(2) प्रत्येक अध्यक्ष और अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक अधिकारी, इस स्कीम के आरम्भ से नब्बे दिन के भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार को या अध्यक्ष को, कार्यालय के प्रधान की मार्फत सम्बोधित लिखित सूचना द्वारा, वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिससे नए निबन्धन उस पर लागू किए जाएं :

परन्तु यह कि—

(क) पैरा 2 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अधिकारी की दशा में, वह तारीख या तो 1 जनवरी, 1973 या कोई पश्चात्वर्ती तारीख, किन्तु इस स्कीम के आरम्भ की तारीख से अपश्चात्वर्ती तारीख, होगी;

(ख) उस पैरा के खण्ड (ii) से (v) में निर्दिष्ट अधिकारी की दशा में, वह तारीख या तो उस अधिकारी की पुष्टि की तारीख होगी या आमेलन की तारीख ।

(3) (क) जहां अधिकारी द्वारा उपपैरा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख इस स्कीम के आरम्भ से पूर्वतर तारीख हो वहां ऐसा अधिकारी ऐसी तारीख से आरम्भ और इस स्कीम के आरम्भ की तारीख से पूर्ववर्ती दिन को समाप्त अवधि के लिए, नए निबन्धनों और वर्तमान सकल उपलब्धियों के बीच अन्तर की राशि संदत्त की जाएगी ।

(ख) जहां खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी अधिकारी ने छुट्टी के किसी भाग के बदले में नकद संदाय लिया हो वहां ऐसे अधिकारी से ऐसे संदाय के रूप में प्राप्त की गई कोई भी रकम लौटाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ग) जहां खण्ड (क) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसा अधिकारी उस पद से, जिस पर वह सामान्यतया नियोजित था, भिन्न पद, धारण कर रहा था या स्थायी प्रकृति का कोई भत्ता पा रहा था, वहां वह वेतनमान सकल उपलब्धियां, जो वह उस पद पर पाता जिस पर कि वह सामान्यतः नियोजित था, इस पैरा और पैरा 6 के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएंगी।

5. कतिपय अधिकारियों का प्रवर्गीकरण :—(1) यदि तब तक किन्हीं अधिकारियों का प्रवर्गीकरण नहीं किया गया हो तो इस स्कीम के आरम्भ की तारीख से दो मास के भीतर बोर्ड द्वारा नियत समिति ऐसे अधिकारियों को सहायक प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में प्रवर्गीकृत करेगा ।

(2) जहां अधिकारी को उपपैरा (1) के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाये तो वह कनिष्ठ अधिकारी के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।

6. नियतन की पद्धति :—(1) जिस प्रवर्ग में किसी अधिकारी को आरम्भतः रखा जाये उसके सम्बन्ध में प्रत्येक अधिकारी का वेतन नए

वेतनमान में उतनी उस क्रम पर नियत किया जायेगा जितनी पर अधिकारी वेतन और महंगाई के भत्ते का योग ऐसे अधिकारी द्वारा नियतन की तारीख को लिये जा रहे वर्तमान सकल वेतन तथा पचास रुपये की राशि के योग के समतुल्य हो, और यदि इस प्रकार से अवधारित राशि सुसंगत में किसी आयाम के समतुल्य नहीं है तो उक्त सुसंगत वेतनमान में ठीक अगले आयाम पर नियत किया जायेगा।

(2) यदि किसी अधिकारी का उपपैरा (1) के अधीन आधारी वेतन अवधारित करने में वेतन वेतनमान के अधिकतम से अधिक पर नियत होता है तो वेतन अधिकतम पर नियत किया जायेगा या यदि वेतन वेतनमान के न्यूनतम से कम पर नियत होता है तो न्यूनतम पर नियत किया जायेगा ।

(3)(क) जहां किसी अधिकारी के संबंध में नियतन की तारीख को अवधारित सकल उपलब्धियां वर्तमान सकल उपलब्धियों से कम हैं तो उसे नीचे विनिर्दिष्ट तीन अनुकल्पों में से निम्नतम राशि वैयक्तिक वेतन के रूप में संदत्त की जायेगी, अर्थात् :--

(i) उसकी वर्तमान सकल उपलब्धियां इस प्रकार अवधारित सकल उपलब्धियों से जितनी अधिक हों, उतनी राशि; या

(ii) इस प्रकार अवधारित सकल उपलब्धियों से चार हजार रुपये की रकम जितनी अधिक हो, उतनी राशि ; या

(iii) सुसंगत प्रवर्ग के लिये प्रथम अनुसूची की मद 4 में या द्वितीय अनुसूची की मद 5 में या तृतीय अनुसूची की मद 5 में यथा-विनिर्दिष्ट अधिकतम वैयक्तिक वेतन की राशि ।

(ख) वैयक्तिक वेतन की राशि, आधारी वेतन में नियतन की तारीख के पश्चात् जब-जब वेतनवृद्धियां मंजूर की जायें-तब-तब कम नहीं होगी, किन्तु वैयक्तिक वेतन इस शर्त के अधीन होगा कि अधिकारी को आधारी वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाटक भत्ता, नगर प्रतिकरात्मक भत्ता और व्यक्तिगत वेतन का योग, किसी भी आयाम पर, चार हजार रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं हो । उपलब्धियों के ऐसे योगफल को चार हजार रुपये प्रतिमास से अधिक न होने देने के लिये जहां आवश्यक हो वहां वैयक्तिक वेतन उतना ही कम कर दिया जायेगा।

7. प्रोन्नति की दशा में वेतन का नियतन :--जहां कोई अधिकारी जिसका वेतन इस स्कीम के अधीन नियत किया गया है, इस स्कीम के आरम्भ से पूर्व उच्चतर पद पर प्रोन्नत हो गया था या प्रोन्नति के पद में उसका आधारी वेतन प्रोन्नति से पूर्व उसके द्वारा धारण किये गये पद में उसके आधारी वेतन के बराबर है तो प्रोन्नति के पद में उसका आधारी वेतन नए वेतनमान में उसके ठीक उच्चतर आयाम पर नियत किया जायेगा :--

8. वेतनवृद्धियां :--(1) नए वेतनमान में वेतनवृद्धियां प्रति कलेण्डर वर्ष में उस समय के प्रथम दिन को, जिस मास में विद्यमान वेतनमान में वेतन नियत किये जाने के पूर्व अन्तिम वेतनवृद्धि मंजूर की गई थी, या अगले उस मास के जिसमें वह धारित पद में बारह मास की निरन्तर सेवा पूरी करता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो प्रथम दिन शोध्य होगी ।

(2) जहां वेतनवृद्धि, वेतन के नियतन की तारीख को शोध्य हो वहां नया वेतनमान अधिकारी द्वारा अपने विद्यमान वेतनमान में ली गई वार्षिक वृद्धि यदि कोई हो, के पश्चात् वेतन के आधार पर लागू किया जायेगा ।

9. भविष्य निधि :--प्रत्येक अधिकारी अपने आधारी वेतन का, जिसमें व्यक्तिगत वेतन, यदि कोई हो, सम्मिलित है, 8½ प्रतिशत का अभिदाय भविष्य निधि में करेगा जिसके साथ, यथास्थिति, निगम या कम्पनी द्वारा भी उतना ही अभिदाय किया जायेगा।

10. उपदान का संदाय:--(1)(क) निगम या कम्पनी में, या दोनों में, कम से कम पांच वर्ष निरन्तर सेवा के पश्चात् (जिसके अन्तर्गत उस बीमाकर्ता के साथ या पूर्ववर्ती नियोजक के साथ, जिसकी सेवा में अधिकारी 31 दिसम्बर, 1972 को कार्यरत था, की गई निरन्तर सेवा भी है) किसी अधिकारी के नियोजन की समाप्ति पर निम्नलिखित दशाओं में उपदान संदेय होगा :--

(i) उसकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति होने पर, या

(ii) उसकी सेवानिवृत्ति होने पर या उसके द्वारा त्यागपत्र किये जाने पर; या

(iii) उसकी मृत्यु पर या दुर्घटना अथवा बीमारी के कारण असमर्थता पर; या

(iv) नियम या कम्पनी द्वारा उसकी सेवा पर्यवसित किये जाने पर, चाहे वह किसी भी कारण से क्यों न हो; या

(v) कर्मचारिवृन्द में कमी करने या स्थापन का पुनर्गठन के कारण उसकी सेवायें समाप्त करने पर;

परन्तु उस दशा में पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी होना आवश्यक नहीं होगा जहां अधिकारी के नियोजन की समाप्ति मृत्यु या असमर्थता के कारण हो ।

स्पष्टीकरण :--इस पैरा के प्रयोजनों के लिये "असमर्थता" से ऐसी असमर्थता अभिप्रेत है जिसके कारण कर्मचारी वह कार्य करने से सर्वथा असमर्थ हो जाये जो वह, उस दुर्घटना या बीमारी के पूर्व जिसके परिणामस्वरूप वह असमर्थता हुई है, निर्वहन करने में समर्थ था।

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या उसके ऐसे भाग के लिये जो छह मास से अधिक हो, अधिकारी को उपदान नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर संदत्त किया जायेगा, अर्थात् :--

सेवा के पूर्ण वर्षों की संख्या	सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये उपदान की दर
1	2
5 वर्ष से 11 वर्ष तक	अन्तिम बार किये गये आधारी वेतन का 50 प्रतिशत ।
12 वर्ष	अन्तिम बार किये गये आधारी वेतन का 60 प्रतिशत ।
13 वर्ष	अन्तिम बार किये गये आधारी वेतन का 70 प्रतिशत ।
14 वर्ष	अन्तिम बार किये गये वेतन आधारी का 80 प्रतिशत ।
15 वर्ष या उससे अधिक	अन्तिम बार किये गये आधारी वेतन का 100 प्रतिशत ।

परन्तु जहां कोई ऐसा कर्मचारी जिसे साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय और अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द के वेतनमानों और सेवा की अन्य शर्तों का सुव्यवस्थीकरण और पुनरीक्षण) स्कीम, 1974 लागू होती है, 1 जनवरी, 1975 को या उसके पश्चात् अधिकारी के रूप में प्रोन्नत किया जाए, वहां उसे उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय राशि से कम उपदान संदत्त नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां अन्तिम बार लिया गया आधारी वेतन 2,500 रुपये से अधिक हो, उपदान 2,500 रुपये के आधार पर अवधारित किया जायेगा ।

(3) अधिकारी को देय उपदान की रकम बीस मास के अन्तिम बार किये गये आधारी या वेतन 30,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम हो, अधिक नहीं होगी ।

(4) ऊपर अभिकथित किसी बात के होते हुए भी, इस पैरा के अन्तर्गत देय उपदान किसी भी दशा में उस उपदान से कम नहीं होगा जिसका कि अधिकारी उसे लागू और 1 जनवरी, 1973 से ठीक प्रवृत्त सेवा की शर्तों के अधीन 31 दिसम्बर, को हकदार हो गया था ।

(5) जो निगम या कम्पनी के अधिकारियों को अनुज्ञेय उपदान की रकम पर धारणाधिकार के अधीन रहते हुए यथास्थिति, निगम या कम्पनी अधिकारी को या उसके नामनिर्देशिती या नामनिर्देशितियों को, या यदि कोई नामनिर्देशन न किया गया हो अथवा विद्यमान न हो तो उसके उत्तराधिकारियों को, इस पैरा के अधीन अनुज्ञेय उपदान की रकम देगी ।

(6) ठीक पूर्ववर्ती उप पैरा में किसी बात के होते हुए भी—

(क) जहां किसी ऐसे अधिकारी पर—

(i) जो उसके नियोजन के अनुक्रम में किये गये किसी अपराध के लिये सिद्धदोष पाया गया है, या जिस अपराध में यथास्थिति , निगम या कम्पनी की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, या

(ii) जिसे प्रबन्ध वर्ग या अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा के किसी कार्य के लिये या नियोजन के स्थान में या उसके निकट दंगा करने या विशृंखल व्यवहार के लिये,

पदच्युत किये जाने की शास्ति अधिरोपित की जाये, उसे देय उपदान पूर्णतया समपहृत हो जायेगा, और

(ख) जहां अधिकारी पर निगम को या कम्पनी को या दोनों को वित्तीय हानि पहुंचाने के किसी कार्य के लिये अनिवार्य सेवा-निवृत्ति, सेवा से हटाये जाने, या पदच्युत किये जाने की शास्ति अधिरोपित की जाये, उसे देय उपदान हानि की सीमा तक समपहृत हो जायेगा ।

11. उद्भूत पेंशन का संरक्षण.—(1) इस स्कीम में सम्मिलित किसी बात का किसी पेंशन के संदाय पर, जिसमें 1 जनवरी, 1973 को यथाप्रवृत्त पेंशन या अधिवर्षिता स्कीम के अनुसरण में किसी अधिकारी को उद्भूत कटुम्ब पेंशन या अधिवर्षिता फायदे भी हैं, कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(2) (क) उप पैरा (1) के अधीन देय रकम विद्यमान वेतनमान में 1-12-1972 को लिये गये वेतन पर और निरन्तर सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर ऐसे अवधारित की जायेगी मानो अधिकारी 1 जनवरी, 1973 के पूर्व सेवानिवृत्त हुआ था ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन अवधारित रकम अधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति पर अथवा उसके सेवा में न रहने पर देय होगी तथा पेंशन उस तारीख से आरम्भ होगी जिसको कि वह सुसंगत पेंशन या सेवा-निवृत्ति स्कीम के अनुसार सामान्यतया आरम्भ होती ।

12. अन्तरण:—कम्पनी का अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक किसी भी समय किसी भी अधिकारी का, कम्पनी के एक विभाग से कम्पनी के दूसरे विभाग में या कम्पनी के एक कार्यालय से कम्पनी के दूसरे कार्यालय में, उसी स्थान पर अथवा किसी अन्य स्थान पर, स्थानान्तरण कर सकता है ।

13. महंगाई भत्ते में फेरफार करने की शक्ति:—यदि केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक और समीचीन समझती है तो वह, आदेश द्वारा, द्वितीय अनुसूची की मद ii के नीचे सारणी के स्तम्भ (7) में या तृतीय अनुसूची की मद ii के नीचे सारणी के स्तम्भ (7) में विनिर्दिष्ट महंगाई भत्ते की रकम में फेरफार कर सकती है और प्रत्येक ऐसा आदेश इस स्कीम की संशोधनकारी स्कीम समझा जायेगा ।

14. निर्वचन:—जहां इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी के निर्वचन की बाबत कोई संदेह या कठिनाई उत्पन्न हो, वह केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय के लिये निर्विष्ट की जायेगी और उस पर केन्द्रीय सरकार का निश्चय सम्बन्धित व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा ।

15. शिथिल करने की शक्ति:—जहां बोर्ड का समाधान हो जाये कि इस स्कीम के उपबन्धों में से किसी के परिवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होगी, वहां वह आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, उस उपबन्ध की अपेक्षाओं का, ऐसे विस्तार तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन रहते हुए जैसे कि वह उस मामले में उचित और सामान्यतापूर्ण रीति से निपटारे के लिये आवश्यक समझता हो, त्याग सकता है या उन्हें शिथिल कर सकता है ।

16. अन्य फायदे:—कोई अधिकारी ऐसे किसी फायदे का हकदार नहीं होगा जो इस स्कीम द्वारा न दिया जाये ।

17. अध्यारोही प्रभाव:—तत्समय प्रवृत्त नियुक्ति के किन्हीं निबन्धनों, करार, पंचाट या अन्य लिखत में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस स्कीम के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।

प्रथम अनुसूची

(पैरा 3 और 6 देखिए)

I. वेतनमान (आधारी वेतन)—

(1) अध्यक्ष— 3500-125-4000 रुपये

(2) प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक 3000-125-3500 रुपये

II. गृह भाटक भत्ता —300 रुपये प्रतिमास

III. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता—75 रुपये प्रतिमास

IV. अधिकतम वैयक्तिक वेतन—700 रुपये प्रतिमास

द्वितीय अनुसूची

(पैरा 3, 6 और 13 देखिए)

I. वेतनमान (आधारी वेतन)

(1) साधारण प्रबन्धक :
2500-125-3000 रु०

(2) सहायक साधारण प्रबन्धक :
2000-125-2500 रु०

(3) प्रबन्धक :

1600-100-2000-125-2250 रु०

(4) उप-प्रबन्धक :

1250-50-1300-75-1600-100-2000 रु०

(5) सहायक प्रबन्धक :

1000-50-1300-75-1675 रु०

(6) प्रशासनिक अधिकारी :

770-40-1050-50-1300 रु०

(7) सहायक प्रशासनिक अधिकारी :

530-40-1050 रु०

II. मंहगाई भत्ता :

इस अनुसूची के अन्तर्गत अधिकारियों का मंहगाई भत्ता नीचे सारणी में दिए अनुसार होगा।

सारणी

निम्नलिखित अवधियों के दौरान देय मंहगाई भत्ते

आधारी वेतन	1-2-73 से 31-7-73	1-8-73 से 31-10-73	1-11-73 से 31-1-74	1-2-74 से 30-4-74	1-5-74 से 31-7-74	1-8-74 से आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
530	370	430	490	550	580	670
570	380	440	500	560	590	680
610	430	510	590	670	710	830
650	430	510	590	670	710	830
690	440	520	600	680	720	840
730	460	540	620	700	740	860
770	450	530	610	690	730	850
810	450	490	610	690	730	850
850	450	490	610	690	730	850
890	450	490	610	690	730	850
930	435	475	595	675	715	835
970	435	475	595	675	715	835
1000	435	475	595	675	715	835
1010	420	460	580	660	700	820
1050	420	460	580	660	700	820
1100	420	460	580	660	700	820
1150	405	445	565	645	685	805
1200	405	445	565	645	685	805
1250	390	430	550	630	670	790
1300	340	430	550	580	670	790
1375	285	405	525	525	645	765
1450	275	395	515	515	635	755
1525	275	395	515	515	635	755
1600	275	395	515	515	635	755
1675	230	350	470	470	590	710
1700	190	285	405	405	525	525
1800	190	190	305	305	425	425
1900	150	150	165	165	285	285
2000	150	150	150	150	185	185
2125	100	100	100	100	100	100
2250	100	100	100	100	100	100
2250 से ऊपर			—शून्य—			

III. गृह भाटक भत्ता :

गृह भाटक भत्ता प्रतिमास निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(क) 750 रु० तक आधारी वेतन के लिए.....आधारी वेतन का 15 प्रतिशत।

(ख) 750 रु० से अधिक आधारी वेतन के लिए.....ऐसे आधिक्य का 10 प्रतिशत।

परन्तु किसी अधिकारी को देय अधिकतम गृह भाटक भत्ता 300 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगा और न्यूनतम गृह भाटक भत्ता 75 रु० प्रतिमास से कम नहीं होगा।

IV. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

निम्नलिखित आस्थानों पर पदस्थ सभी अधिकारियों के लिए	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर	
(क) मुम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास और नई दिल्ली	आधारी वेतन का 8 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 75 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से प्रभावी
(ख) (i) अहमदाबाद, बंगलौर	आधारी वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 50 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से 31-10-73 तक प्रभावी
(ii) अहमदाबाद, बंगलौर और कल्याणी (कलकत्ता)	आधारी वेतन का 8 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 75 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से प्रभावी
(ग) कानपुर, लखनऊ, नागपुर और पूना	आधारी वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 50 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से प्रभावी
(घ) आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, बड़ौदा, कोचीन, कोयम्बतूर, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, मदुरई, पटना शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिवन्द्रम, वाराणसी।	740 रु० के आधारी वेतन तक 10 रुपए।	1-1-73 से प्रभावी
(ङ) धनबाद, ग्वालियर, जमशेदपुर, लुधियाना, सालेम, सिवनी, तिरुचिरापल्ली।	740 रु० के आधारी वेतन तक 10 रु०।	1-1-73 से प्रभावी

V. अधिकतम वैयक्तिक वेतन :

पैरा 6 के उप-पैरा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) में निर्दिष्ट वैयक्तिक वेतन नीचे दिए अनुसार अधिकतम रकम तक सीमित होगा।

अधिकारियों का प्रवर्ग	अधिकतम वैयक्तिक वेतन
(क) साधारण प्रबन्धक	700 रुपए प्रतिमास
(ख) सहायक साधारण प्रबन्धक	700 रुपए प्रतिमास
(ग) प्रबन्धक	500 रुपए प्रतिमास
(घ) उप-प्रबन्धक	500 रुपए प्रतिमास
(ङ) सहायक प्रबन्धक	500 रुपए प्रतिमास
(च) प्रशासनिक अधिकारी	300 रुपए प्रतिमास
(छ) सहायक प्रशासनिक अधिकारी	300 रुपए प्रतिमास

तृतीय अनुसूची

(पैरा 3, 6 और 13 देखिए)

1. वेतनमान (आधारी वेतन)—

कनिष्ठ अधिकारी :

460-35-530-40-890 रुपए।

II. महंगाई भत्ता :

इस अनुसूची के अधीन देय महंगाई भत्ता नीचे की सारणी में दिए गए अनुसार होगा।

सारणी

निम्नलिखित अवधियों के दौरान देय महंगाई भत्ते

आधारी वेतन	1-2-73 से 31-7-73	1-8-73 से 31-10-73	1-11-73 से 31-1-74	1-2-74 से 30-4-74	1-5-74 से 31-7-74	1-8-74 से आगे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
460	321	373	425	477	503	582
495	346	402	458	514	542	626
530	370	430	490	550	580	670
570	380	440	500	560	590	680
610	430	510	590	670	710	830
650	430	510	590	670	710	830
690	440	520	600	680	720	840
730	460	540	620	700	740	860
770	450	530	610	690	730	850
810	450	490	610	690	730	850
850	450	490	610	690	730	850
890	450	490	610	690	730	850

III. गृह भाटक भत्ता

गृह भाटक भत्ता प्रतिमास निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

(क) 750 रु० तक आधारी वेतन के लिए.....आधारी वेतन का 15 प्रतिशत।

(ख) 750 रु० से अधिक आधारी वेतन के लिए.....ऐसे आधिक्य का 10 प्रतिशत।

परन्तु यह है कि किसी अधिकारी को देय अधिकतम गृह भाटक भत्ता 300 रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

IV. नगर प्रतिकरात्मक भत्ता :

नगर प्रतिकरात्मक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा :

निम्नलिखित अवस्थानों पर पदस्थ सभी अधिकारियों के लिए	नगर प्रतिकरात्मक भत्ते की दर	
(क) मुम्बई कलकत्ता, हैदराबाद, मद्रास और नई दिल्ली	आधारी वेतन का 8 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 75 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से प्रभावी
(ख) (i) अहमदाबाद बंगलौर	आधारी वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 50 रुपए प्रतिमास।	1-1-73 से 31-10-73 तक प्रभावी
(ii) अहमदाबाद बंगलौर और कल्याणी (कलकत्ता)	आधारी वेतन का 8 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 75 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से प्रभावी
(ग) कानपुर नागपुर और पूना	आधारी वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक 50 रु० प्रतिमास।	1-1-73 से प्रभावी
(घ) आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, बड़ौदा, कोयम्बतूर इंदौर जबलपुर, जयपुर, मदुराई, पटना शोलापुर श्रीनगर सूरत, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी।	740 रु० के आधारी वेतन तक 10 रुपए।	1-1-73 से प्रभावी
(ङ) धनबाद ग्वालियर, जमशेदपुर, लुधियना, सालेम, सिवरी, तिरुचिरापल्ली	740 रु० के आधारी वेतन तक 10 रुपए।	1-1-73 से प्रभावी

अधिकतम वैयक्तिक वेतन--

पैरा 6 के उप-पैरा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iii) में निर्दिष्ट वैयक्तिक वेतन नीचे दी गई रकम तक सीमित होगा :

अधिकारियों का प्रवर्ग	अधिकतम वैयक्तिक वेतन
कनिष्ठ अधिकारी	300 रुपए प्रतिमास

[(सं० फा० 65(5)-बीमा III/7/75]

जी० एच० दामले, बीमा नियंत्रक तथा पदेन संयुक्त सचिव

(राजस्व और बीमा विभाग)

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1975

का. आ. 5243.—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 61 के प्रथम परन्तुक खण्ड (2) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग हर सीमा-शुल्क कलक्टर भी कर सकेंगी :

परन्तु उक्त खण्ड के अधीन सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा बढ़ाई गई अवधि, चार वर्ष की अवधि के बाद एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

[सं. 100/75 सी. शु. फा. सं. 473/250/75 सी. शु. 7]

यू. के. सेन, अवर सचिव

(Department of Revenue and Insurance)

CUSTOMS

New Delhi, the 5th December, 1975

S.O. 5243.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby directs that the powers of the Central Board of Excise and Customs under clause (ii) of the first proviso to section 61 of the said Act shall be exercisable also by every Collector of Customs :

Provided that the period extended by the Collector of Customs under the said clause shall not exceed one year beyond the period of four years.

[No. 100/75-Customs/F. No. 473/250/75-Cus. VII]

U. K. SEN, Under Secy.

(बैंकिंग विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1975

का० आ० 5244.—यतः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 52 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार बैंककारी विनियमन (कम्पनी) नियम, 1949 में और आगे संशोधन करने के लिए कुछ प्रारूप नियम, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (बैंकिंग विभाग) की 28 दिसम्बर, 1974 की अधिसूचना संख्या का० आ० 12 के अधीन 4 जनवरी, 1975 के भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड, 3, उपखण्ड (2) में पृष्ठ 8 से 23 पर प्रकाशित किये गये थे और जो व्यक्ति इससे प्रभावित होने हों, उनसे 31 जुलाई, 1975 तक आपत्तियां और सुझाव मांगे गये थे;

और यतः उक्त राजपत्र जनता को 6 फरवरी, 1975 को सुलभ कर दिया गया था;

और यतः उक्त प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 52 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात्, एतद्द्वारा बैंककारी विनियमन (कम्पनी) नियम 1949 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम बैंककारी विनियमन (कम्पनी) संशोधन नियम, 1975 है।

2. बैंककारी विनियमन (कम्पनी) नियम, 1949 में, जिन्हें आगे उक्त नियम कहा गया है "बैंककारी कम्पनी अधिनियम 1949" और "बैंककारी प्रचालन विभाग" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आए हों, "बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949" और "बैंककारी प्रचालन और विकास विभाग" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 2 में, उपनियम (i) में, खंड (च) में :—

(क) उपखंड (iv) में, अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) इस प्रकार संशोधित उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(v) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक की दशा में, उस तारीख से, जिस तारीख को बैंककारी विनियमन (कम्पनी) संशोधन नियम, 1975 राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं;"

(ग) उपखंड (v) को उपखंड (iv) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा;

(घ) परन्तुक में, "(iii) और (iv)" कोष्ठकों, अंकों और शब्द के स्थान पर "(iii) से (v) तक कोष्ठक, अंक और शब्द, जिसमें दोनों सम्मिलित हैं," रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 2क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2क भारतीय स्टेट बैंक, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक और अधिनियम की धारा 51 के अधीन अधिसूचित अन्य बैंककारी संस्थाओं को नियमों का लागू होना। ये नियम और उससे उपाबद्ध प्रारूप, नियम 6 से 10 और प्रारूप 2 से 5 और 11 को छोड़कर, यावत्शक्य भारतीय स्टेट बैंक या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तत्स्थानी नए बैंक या अधिनियम की धारा 51 के अधीन अधिसूचित कोई अन्य बैंककारी संस्था को भी उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे भारत में निगमित बैंककारी कम्पनियों को और उनके सम्बन्ध में लागू होते हैं :

परन्तु यह कि इस प्रकार नियमों और प्ररूप में "रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" पद से यथास्थापित "केन्द्रीय कार्यालय या प्रधान कार्यालय" अभिप्रेत होगा।"

5. उक्त नियमों के नियम 10क का लोप किया जाएगा।

6. उक्त नियमों के नियम 11 में-

(i) खंड (क) में, "प्ररूप 5" पद के स्थान पर "प्ररूप 3" पद रखा जाएगा;

(ii) खंड (ख) में, "प्ररूप 6" पद के स्थान पर "प्ररूप 4" पद रखा जाएगा; और

(iii) खंड (ग) में, "प्ररूप 7" पद के स्थान पर "प्ररूप 5" पद रखा जाएगा।

7. उक्त नियमों के नियम 12 में, "प्ररूप 8" पद के स्थान पर "प्ररूप 6" पद रखा जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 13 में, "प्ररूप 9" पद के स्थान पर "प्ररूप 7" पद रखा जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 15क में "प्ररूप 13" पद के स्थान पर, "प्ररूप 11" पद रखा जाएगा।

10. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप i के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :—

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

प्ररूप i (नियम 5 देखिए)

धारा 10

(प्रति वर्ष 31 जनवरी से पूर्व रिजर्व बैंक को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा)

बैंककारी कम्पनी का नाम .....

विवरणी प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम .....

31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदत्त पारिश्रमिक* .....

(क) भारत में निगमित बैंककारी कम्पनी द्वारा अपने प्रत्येक निदेशक तथा प्रथम दस अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जहां कहीं भी वे नियोजित हों;

(ख) भारत से बाहर निगमित बैंककारी कम्पनी द्वारा भारत में प्रथम दस अधिकतम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को

खंड 1							खंड 2								
नाम	आयु	अर्हताएं	बैंककारी और अ-बैंककारी संस्थाओं का अनुभव	नियुक्ति/पुनः नियुक्ति की तारीख	पदनाम	31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदत्त कुल पारिश्रमिक* खंड 2 या खंड 3 देखिए	बैठक की फीस		अन्य संदाय						
							दर प्रति अधिवेशन	संदत्त रकम	यात्रा भत्ता		विराम/दैनिक भत्ता		अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट कीजिए)		
									दर	संदत्त रकम	दर	संदत्त रकम	दर	संदत्त रकम	वेतन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
क. निदेशक															
1.															
2.															
3. इत्यादि															
ख. अन्य कर्मचारी															
1.															
2.															
3. इत्यादि															

खंड 3												
भत्ते						अन्य	प्रीसुविधायें	परिलब्धियां				
महंगाई भत्ता	गृह भत्ता	सवारी भत्ता	स्थानीय भत्ता	अन्य भत्ते (प्रकृति विनिर्दिष्ट कीजिए)	भविष्य निधि में अभिदाय	बोनस	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट कीजिए)	मुफ्त या सहायकी प्राप्त अनावासीय वास सुविधा	मुफ्त या सहायकी प्राप्त कारों का उपयोग	गृहस्थी से संबद्ध सेवकों यदि कोई हो को संदत्त वेतन	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट कीजिए)	टिप्पणियां
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

तारीख :

हस्ताक्षर

*पारिश्रमिक में वेतन, फीस और परिलब्धियां सम्मिलित हैं किन्तु कर्तव्यों का पालन करने में वस्तुतः उपगत किसी खर्चे की प्रतिपूर्ति करने के प्रयोजन के लिए संदत्त कोई भत्ता या अन्य रकम सम्मिलित नहीं होगी। भारत से बाहर निगमित बैंककारी कम्पनी की दशा में, कर्मचारियों की ओर से संदत्त कर, स्तम्भ 29 में पृथक्-पृथक् उपदर्शित किए जाने चाहिए।

टिप्पण : (i) बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को निदेशक या अन्य कर्मचारियों के नाम के सामने टिप्पणियों के स्तंभ में उपदर्शित करना चाहिए।

(ii) प्रबंध या पूर्ण-कालिक निदेशक की दशा में या ऐसे निदेशक की दशा में जो अभिकरण द्वारा नियुक्त होने के दायित्वाधीन नहीं है या प्रबंधक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी की दशा में, समस्त वर्ष के लिए प्रवृत्त नियुक्तियों के निबन्धनों का ब्यौरा स्तम्भ 29 में उल्लिखित किया जाएगा।

(iii) निदेशकों की बाबत विशिष्टियां खंड 2 में दी जानी चाहिए। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और अन्य कर्मचारियों की बाबत विशिष्टियां खंड 3 में दी जानी चाहिए। स्तम्भ 10 से 13 में विशिष्टियां भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी की बाबत दी जानी चाहिए।

(IV) स्तम्भ 25 से 28 की दशा में, परिलब्धियों का आर्थिक समतुल्य दिया जाना चाहिए।

11. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 और 4 का लोप किया जाएगा।

12. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 5, 6 और 7 को क्रमशः प्ररूप 3, 4 और 5 में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

13. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

प्ररूप 6 (नियम 12 देखिए)

धारा (23)

अधिनियम की धारा 23 के अधीन कारबार का नया स्थान खोलने या कारोबार के विद्यमान स्थान की अवस्थिति (उसी नगर नगरी या गांव के भीतर से अन्यथा) परिवर्तन की अनुज्ञा के लिए आवेदन का प्ररूप

पता ----------
तारीख----------

बैंककारी प्रचालन और विकास विभाग
भारतीय रिजर्व बैंक

प्रिय महोदय,

हम बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 के निबन्धनों के अनुसार----------में कारबार का नया स्थान खोलने ----------विद्यमान कारबार के स्थान की अवस्थिति के----------से----------को परिवर्तन की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं।

भवदीय

हस्ताक्षर

(1) बैंककारी कंपनी का नाम :

(2) प्रस्थापित कार्यालय :

निम्नलिखित जानकारी दीजिए

(क) नगर/नगरी/गांव का नाम।

(उस दशा में जहां स्थान एक से अधिक नाम द्वारा ज्ञात हो तो संबंधित जानकारी भी दी जानी चाहिए)

(ख) परिक्षेत्र स्थान का नाम :

(ग) तालुक जिला और राज्य का नाम :

(घ) प्रस्थापित कार्यालय की प्रस्थिति :

(ङ) प्रस्थापित कार्यालय और निकटतम विद्यमान वाणिज्यिक बैंक कार्यालय के बीच की दूरी और साथ ही बैंक तथा केन्द्र/परिक्षेत्र का नाम :

@(च) 5 कि०मी० के घेरे के भीतर कृत्य करने वाले वाणिज्यिक बैंकों के नाम और उनके कार्यालयों की संख्या और साथ ही उन केन्द्रों के नाम जहां ये कृत्य कर रहे हैं :

(3) पूर्ववर्ती आवेदन :

प्रस्थापित कारबार के स्थान की बाबत रिजर्व बैंक को किए गए पूर्ववर्ती आवेदनों यदि कोई हो की विशिष्टियां दीजिए।

(4) प्रस्थापित कार्यालय के कारण :

प्रस्थापित कार्यालय के विस्तृत कारण बताइए और निम्न प्रकार के ऐसे सांख्यिकीय और अन्य आंकड़े दीजिए जो प्रस्थापित कार्यालय के लिए एकत्रित किए गए हों।

(i) स्थान की जनसंख्या :

(ii) प्रस्थापित कार्यालय के कमांड क्षेत्र (अर्थात् प्रचालन क्षेत्र) की विशिष्टियां

(क) कमांड क्षेत्र का लगभग घेरा :

(ख) जनसंख्या :

(ग) कमांड क्षेत्र में गांवों की संख्या :

(iii) प्रस्थापित कार्यालय के प्रचालन क्षेत्र का निम्नप्रकार से कृषि खनिज और औद्योगिक उत्पादन तथा आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य :

पदार्थ	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7

(iv) यदि कृषि खनिज या औद्योगिक विकास की स्कीमें हों तो उनका विवरण दीजिए और वर्तमान उत्पादन आयात और निर्यातकी मात्रा और मूल्यय पर उनका अधिसंभाव्य प्रभाव बताइए।

(v) यदि विद्यमान बैंककारी सुविधाएं अपर्याप्त समझी जाती हैं तो उसके कारण बताइए।

(vi) संभाव्यतः उस न्यूनतम कारबार का प्राक्कलन निम्न प्रकार से दीजिए जो बैंककारी कंपनी प्रस्थापित कार्यालय में 12 मास के भीतर आकृष्ट करने की आशा करती है।

(क) निक्षेप : रकम हजारों में

(ख) उधार : रकम हजारों में

(5) विद्य मान कार्यालय की अवस्थिति का परिवर्तन :

नई अवस्थिति की सं० 2, 3 और 4 में के अनुसार विशिष्टियां देते हुए उस कार्यालय की जिसे बन्द करने की प्रस्थापना की गई है और उस स्थान की जहां उसे परिवर्तित करने की प्रस्थापना की गई है ठीक अवस्थिति दीजिए।

(6) व्यय :

प्रस्थापित कार्यालय के सम्बन्ध में कर्मचारिवृन्द परिसरों फर्नीचर, लेखन सामग्री, विज्ञापन इत्यादि पर पहले ही खर्च की गई और खर्च करने के लिए प्रस्थापित रकम बताइए। वह न्यूनतम आय भी बताइए जिसे बैंककारी कंपनी प्रस्थापित कार्यालय में 12 मास के भीतर अर्जित करने की आशा करती है।

(7) अन्य विशिष्टियां :

ऐसे अतिरिक्त तथ्य जो बैंककारी कम्पनी अपने आवेदन की पुष्टि में देना चाहे।

---

*वह भाग जो लागू न हो काट दीजिए।

@केवल एक लाख से कम की जनसंख्या वाले केन्द्रों के लिए आवेदनों की दशा में यह जानकारी देना आवश्यक है।

ध्यान दें :

1. इस प्ररूप में 'कार्यालय' शब्द जहां कहीं भी आएं हैं में कारबार के वे स्थान भी सम्मिलित हैं जहां पर निक्षेप प्राप्त किए जाते हैं, चैक भुनाए जाते हैं, रकम उधार दी जाती है या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कारबार किसी अन्य में किया जाता है।

2. मद (5) का उत्तर केवल तभी देना है यदि आवेदन विद्यमान कारबार के स्थान की अवस्थिति के परिवर्तन के लिए है।

3. यदि बैंककारी कंपनी किसी मद की बाबत पूरा विवरण देने में असमर्थ हो या न देना चाहती हो तो उसके लोप के कारण दिए जाएं।

4. मद (2), (3), (4), (5) और (6) में मांगी गई जानकारी जहां आवेदन एक से अधिक कार्यालय के खोलने या उसकी अवस्थिति के परिवर्तन से संबंधित हो प्रत्येक कार्यालय के लिए पृथक् पृथक् दी जाएगी।

5. "प्रशासनिक कार्यालय" की अवस्थिति के परिवर्तन की दशा में जहां कोई बैंककारी कारबार नहीं किया जाता है या करने की प्रस्थापना नहीं की गई (जैसे कि "रजिस्ट्रीकृत कार्यालय केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान कार्यालय या प्रधान कार्यालय") वहां परिवर्तन के कारण बताते हुए पत्र के रूप में केवल एक आवेदन देना आवश्यक है।

14. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 9 को प्ररूप 7 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

15. प्ररूप 10, 11 और 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात् :—

बैंककारी विनियम अधिनियमन, 1949

प्ररूप 8

(धारा 18 और 24)

बैंककारी कंपनी का नाम----------

विवरणी प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम----------

----------मास के लिए मांग और काल दायित्व तथा नकद, स्वर्ण और बिल्लंगम रहित अनुमोदित प्रतिभूतियों का विवरण (उस मास की समाप्ति के पश्चात् जिससे यह संबंधित है, 15 दिन के भीतर रिजर्व बैंक को दिया जाएगा) ।

(निकटतम हजार में पूर्णांकित)

	जैसे कि निम्नलिखित को कारबार के बंद होने पर है				
	प्रथम शुक्रवार (क)	द्वितीय शुक्रवार (क)	तृतीय शुक्रवार (क)	चतुर्थ शुक्रवार (क)	पंचम शुक्रवार (क)
क-भारत में दायित्व :					
1. मांग दायित्व (जिसमें से रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि पुनर्वित निगम और *अधिसूचित बैंकों से उधार ग्रहण कम किए जाएंगे)					
2. काल दायित्व (जिसमें से रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा कृषि पुनर्वित निगम और *अधिसूचित बैंकों से उधार ग्रहण कम किए जाएंगे)					
3. क1 और क2 का जोड़					
ख 1. अधिनियम की धारा 24 के अधीन धारण करने के लिए अपेक्षित आस्तियों की न्यूनतम राशि (क3 का 25 प्रतिशत)					
2. अधिनियम की धारा 18 के अधीन धारण करने के लिए अपेक्षित आरक्षित-नकद की न्यूनतम राशि (क3 का 3 प्रतिशत)†					

	जैसे कि निम्नलिखित को कारबार बंद होने पर है				
	प्रथम शुक्रवार	द्वितीय शुक्रवार	तृतीय शुक्रवार	चतुर्थ शुक्रवार	पंचम शुक्रवार
ग. भारत में आस्तियां :					
1. (क) हाथ नकदी					
(ख) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाते में अतिशेष					
(ग) **अधिसूचित बैंकों में चालू खाते में अतिशेष					
2. ग के अधीन (क), (ख) और (ग) का जोड़					
3. रिजर्व बैंक में चालू खाते में अतिशेष					
4. ग 2 और ग 3 का जोड़†					
5. बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 18 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित नकद और/या अतिशेष†					
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित अतिशेष††					
6. ग4 की वह रकम जो ग5 आधिक्य में है, †					
ग2 का जोड़ और ग3 का ग5 पर अधिक्य††					
7. स्वर्ण (चालू बाजार कीमत से अनधिक कीमत पर मूल्यांकित)					
8. बिल्लंगम रहित अनुमोदित आस्तियां (चालू बाजार कीमत से अधिक कीमत पर मूल्यांकित)					
9. अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक में रखे जाने के लिए अपेक्षित निक्षेप					

(i) नकद

(ii) विल्लगम रहित अनुमोदित आस्तियां (चालू बाजार कीमत से अनधिक कीमत पर मूल्यांकित)

10. ग6, ग7, ग8 और ग9 का जोड़

11. बचत निक्षेप

(क) मांग दायित्व भाग

(ख) काल दायित्व भाग

जोड़ :

तारीख—————— हस्ताक्षर——————

(क) तारीखें दीजिए [जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अधीन शुक्रवार अवकाश दिन हो, वहां पूर्ववर्ती कार्य दिवस दीजिए]

*"अधिसूचित बैंक" से ऐसी बैंकारी संस्था अभिप्रेत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (i) के स्पष्टीकरण के खड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो।

**अधिसूचित बैंक" से ऐसा कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

*केवल अननुसूचित बैंकों के लिए

**केवल अननुसूचित बैंकों के लिए

†केवल अननुसूचित बैंकों को लागू होगा

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

प्ररूप 9

(धारा 26)

बैंककारी कंपनी का नाम——————————

विवरणी प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम——————————

भारत में उन अदावाकृत निक्षेप खातों की विवरणी, जो यथा विवरणी की तारीख को 10 वर्ष या अधिक के लिए प्रचालन में नहीं रहे।

यथा 31 दिसम्बर——————————को

प्रत्येक कैलण्डर वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 30 दिन के भीतर रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा)

विशिष्टियां	चालू खाते		बचत बैंक खाते		नियत निक्षेपों (जिसमें नकद प्रमाणपत्र, आवर्ती निक्षेप, इत्यादि सम्मिलित हैं)		जोड़	
	खातों की सं०	बकाया अतिशेष	खातों की सं०	बकाया अतिशेष	खातों की सं०	बकाया अतिशेष	खातों की सं०	बकाया अतिशेष
		रु० पै०		रु० पै०		रु० पै०		रु० पै०
यथा 31-12-19....को पूर्ववर्ती विवरणी से अग्रणीत अतिशेष								
......पूर्ववर्ती विवरणियों में अनवधानता से छोड़ दिए गए खाते यदि कोई हों								
19—————*के दौरान परिवर्तन								
जोड़								

**ऐसे खाते जो 19.... के दौरान प्रवर्तित या बंद किए गए हों——————

यथा 31-12-19.... को कुल अतिशेष

जोड़िए–वर्ष के दौरान खातों में जमा किया गया

ब्याज

कम करिए–वर्ष के दौरान लेखाओं में उद्गृहीत आनुषंगिक प्रभार——————

जोड़

तारीख—————— हस्ताक्षर——————

*यह मद ऐसे खातों में वस्तुतः अतिशेषों का दृयोतन करने के लिए आशयित है, जो ठीक पूर्ववर्ती विवरणी की तारीख से 10 वर्ष के लिए अप्रवर्तित हो गए हैं । यदि कोई ऐसे खाते जो पूर्ववर्ती विवरणियों में इस मद के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने चाहिए थे, उन विवरणियों में अनवधानता से छूट गए हैं, तो वे "यथा 31-12-19.....को पूर्ववर्ती विवरणी से अग्रानीत अतिशेष" के ठीक नीचे पृथक उप शीर्षक "पूर्ववर्ती विवरणियों में अनवधानता से छूट गए खाते यदि कोई हो" के अधीन उपदर्शित किए जाने चाहिएं । ऐसे खातों की विशिष्टियां विवरण के समस्त स्तम्भों के अधीन दी जानी चाहिएं ।

**यह मद ऐसे खातों (पूर्ववर्ती विवरणियों में अप्रदर्शित) में बकाया अतिशेषों का दृयोतन करने के लिए आशयित है, जो जमा किए गए ब्याज के परिवर्धन और उपयुक्त आनुषंगिक प्रभारों की कटौतियों पर विचार करने के पश्चात् और निक्षेपों के या निकलवाने के कारण प्रवर्तित हो गए हैं या जो वर्ष के दौरान बंद कर दिए गए हैं । इस प्रकार बनाए गए बकाया अतिशेष और पूर्ववर्ती विवरणी में उपदर्शित बकाया अतिशेष के बीच अंतर (यदि कोई हो) उपयुक्ततः स्पष्ट करना चाहिए ।

प्रारूप 10

यथा 19.....के.....मास के अंतिम शुक्रवार को वाणिज्यिक बैंकों के भारत में दायित्व और आस्तियां

भाग 1

(बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27)

(निकटतम हजार में पूर्णांकित)

क-भारत में दायित्व	ख-भारत में आस्तियां
1. समादत्त पूंजी (जिसमें समपहृत शेयर भी सम्मिलित हैं)	1. हाथ-नकदी
2. आरक्षित निधि और अन्य आरक्षितियां*	2. भारत रिज़र्व बैंक में अतिशेष
2.1 आरक्षित निधि	3. भारत में अन्य बैंकों में चालू खाते में अतिशेष
2.2 अन्य आरक्षितियां	3.1 भारतीय स्टेट बैंक
2.3 शेयर प्रीमियम खाता*	3.2 भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी
3. निक्षेप	3.3 अन्य वाणिज्यिक बैंक
3.1 चालू निक्षेप	3.4 सहकारी बैंक
3.1.1 बैंकों से (जिसमें सहकारी बैंक भी सम्मिलित है)	4. मांग और अल्प-सूचना पर प्राप्य धन
3.1.2 अन्यों से	4.1 वाणिज्यिक बैंकों के पास
3.2 बचत निक्षेप	4.2 सहकारी बैंकों के पास
3.3 नियत निक्षेप (जिसमें नकद प्रमाणपत्र, आवर्ती जमा, इत्यादि भी सम्मिलित हैं)	4.3 अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास
3.3.1 बैंकों से (जिसमें सहकारी बैंक भी सम्मिलित है)	5. विनिधान
3.3.2 अन्यों से	5.1 खजाना बिल
4. उधार	5.2 केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियां जिसमें खजाना बचत निक्षेप और डाक बचत पत्र तथा निक्षेप सम्मिलित हैं ।
4.1 भारत में के बैंकों से उधार	5.3 राज्य सरकार प्रतिभूतियां
4.1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	5.4 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
4.1.2 भारतीय स्टेट बैंक	5.5 उन कंपनियों और निगमों के शेयर और डिबेंचर जो ऊपर 5.1 में सम्मिलित नहीं हैं ।
4.1.3 भारतीय स्टेट बैंक के समनुषंगी	5.6 बैंकों, जिसमें सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं में नियत निक्षेप
4.1.4 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	5.7 भारत के अन्य विनिधान
4.1.5 कृषि पुनर्वित्त निगम	
4.1.6 अन्य वाणिज्यिक बैंक	
4.1.7 सहकारी बैंक	
4.2 भारत से बाहर के बैंकों से उधार	
5. अन्य आस्तियां	6. वे बिल जो क्रय किए गए हैं और जिनमें छूट दी गई है ।
5.1 भारत में संदेय बिल	6.1 वे अन्तर्देशीय बिल जो क्रय किए गए हैं और जिनमें छूट दी गई है ।
5.1.1 भारतीय कार्यालय द्वारा तैयार किए गए	6.2 वे विदेशी बिल जो क्रय किये गए हैं और जिनमें छूट दी गई है ।
5.1.2 *विदेशी कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए	6.2.1 भारत में तैयार किए गए निर्यात बिल
5.2 वे बिल जो भारत से बाहर संदेय है ।	6.2.2 भारत में तैयार किए गए और संदेय आयात बिल
5.3 अग्रिम में प्राप्त मांगें*	6.2.3 वे अन्य विदेशी बिल जो क्रय किए गए हैं और जिनमें छूट दी गई है ।
5.4 प्रकीर्ण दायित्व	
6. शाखा समायोजन @	
6.1 भारत में के कार्यालय में	
6.2 **भारत के बाहर के कार्यालयों में	

7. कुल मांग और काल दायित्व अर्थात् क3, क4 और क5 का जोड़
8. लाभ का अतिशेष

6.2.3.1 भारत में संदेय
6.2.3.2 भारत के बाहर संदेय
7. उधार और अग्रिम
7.1 उधार और अग्रिम, नकद जमा और ओवर ड्राफ्ट (बैंकों से शोध्य को छोड़कर नीचे की मद 7.2 देखिए)
7.2 बैंकों से शोध्य
7.2.1 भारत में सहकारी बैंक
7.2.2 भारत में वाणिज्यिक बैंक
7.2.3 †भारत के बाहर बैंक
8. परिसर फर्नीचर फिक्सचर और अन्य स्थिर आस्तियां
9. शाखा समायोजन@
9.1 भारत में के कार्यालयों में
9.2 भारत के बाहर के कार्यालयों में**
10. पंजीकृत व्यय जिसमें प्रारंभिक व्यय संगठनकारी व्यय, शेयर बेचने का कमीशन दलाली में अपगत हानि और ऐसे अन्य व्यय सम्मिलित हैं, जिनको मूर्त आस्तियों द्वारा निरूपित न किया गया हो***
11. ऐसी अ-बैंककारी आस्तियां जो दावों के समाधान में अर्जित की गई हों।
12 अन्य मूर्त आस्तियां

कुल दायित्व	कुल आस्तियां

भाग 2

कुल अग्रिम (उप भाग 1 में आस्तियों के पद 6 और 7 का जोड़)			कुल अग्रिमों के प्रति क्लीन (अप्रतिभूत) अग्रिमों का प्रतिशत (स्तंभ 2 से 3 का प्रतिशत)	कुल निक्षेप (भाग 1 में दायित्वों की मद 3)	कुल निक्षेपों के प्रति कुल अग्रिम का प्रतिशत (स्तंभ 3 से 5 का प्रतिशत)
प्रतिभूत	अप्रतिभूत (क्लीन)	कुल			
1	2	3	4	5	6

भाग 3

(धारा 25)

(निकटतम हजार में पूर्णांकित)

1. भारत के मांग और काल दायित्व
(भाग 1 में दायित्वों की मद 7)
(ऐसी मदों को छोड़कर जिन्हें छोड़ने के लिए वर्तमान में बैंकों को अनुज्ञात किया हुआ है अर्थात् ऐसे मद जो बाह्य दायित्वों की प्रकृति के नहीं हैं)
2. आस्तियों की ऐसी न्यूनतम राशि जिसे अधिनियम की धारा 25 के अधीन भारत में रखना अपेक्षित है (ऊपर मद 1 का 75 प्रतिशत)
3. भारत में आस्तियां
3.1 भाग 1 में आस्तियों की ओर की मद ख1 से ख8, ख11 और ख12 का जोड़
3.2 अधिनियम की धारा 25(3) (क) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित और ऊपर 3.1 में सम्मिलित न की गई प्रतिभूतियां।

हस्ताक्षर
पदनाम

तारीख

*भारत में प्रचलित विदेशी बैंकों को लागू नहीं होता।

@शुद्ध अतिशेष या शाखा समायोजन, यथास्थिति, दायित्वों या आस्तियों के रूप में उपदर्शित किए जाने चाहिएं।

**कृपया पाद टिप्पण में भारतीय कार्यालयों के बकाया उधार दीजिए।

†भारत के बाहर बैंकों/संवाददाताओं को अनुदत्त उधार/ओवर ड्राफ्ट रुपयों में होंगे।

***यदि लाभ और हानि खाते में अतिशेष घाटा निरूपित करता है तो इसे इस मद में सम्मिलित करना चाहिए।

टिप्पण :

(1) भाग 1 और 2 के अधीन आंकड़े, यथा प्रत्येक मास के अंतिम शुक्रवार को कारबार के बंद करने पर और भाग 3 के अधीन यथा मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के अंतिम शुक्रवार को कारबार के बंद करने पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) कृपया बैंकों के भारतीय कार्यालयों के विदेशी दायित्वों और आस्तियों के आंकड़े निम्नलिखित मदों के लिए दिए जाएं :

(i) विदेशों में धारित अतिशेष

(ii) विदेशों में धारित विनिधान

(iii) भारत के बाहर संदेय ऐसे अन्य विदेशी बिल जो क्रय किए गए हैं और जिनमें छूट दी गई है ।

(iv) भारत के बाहर धारित कोई अन्य आस्तियां ।

(3) सहकारी बैंकों में राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंक, सहकारी भू बंधक बैंक और प्राथमिक सहकारी बैंक आते हैं ।

(4) यदि परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 (1881 का 26) के अधीन सम्बद्ध शुक्रवार लोक अवकाश दिन हो तो पूर्ववर्ती कार्य-दिन को कारबार के बंद करने पर ।

16. उक्त नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 13 को प्ररूप 11 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं० फा० 3/4/74-बी० ओ० आई]

स० व० कटारिया, निदेशक

(Department of Banking)

New Delhi the, 15th November, 1975

S.O. **5244** .—Whereas certain draft rules further to amend the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949 were published as required by sub-section (3) of section 52 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), at pages 8-23 of the Gazette of India, Part II-Section 3—Sub-section (ii) dated 4th Januay, 1975 under notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Banking) No. S.O. 12 dated the 28th December, 1974 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the 31st July, 1975;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 6-2-1975.

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 52 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949, namely:—

1. These rules may be called the Banking Regulation (Companies) Amendment Rules, 1975.

2. In the Banking Regulation (Companies) Rules, 1949, (hereinafter referred to as the said rule) for the words and figures "Banking Companies Act, 1949" and "Department of Banking Operations" wherever they occur, the words and figures "Banking Regulation Act 1949" and "Department of Banking Operations and Development" shall respectively be substituted.

3. In rule 2 of said rules, in sub-rule (1), in caluse (f)—

(a) in sub-clause (iv), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(b) after sub-clause (iv) as so amended, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(v) in the case of a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), from the date on which the Banking Regulation (Companies) Amendmen Rules, 1975, are published in the Official Gazette;"

(c) sub-clause (v) shall be renumbered as sub-clause (vi) ;

(d) in the proviso, for the brackets, figures and word "(iii) and (iv)", the brackets, figures and word "(iii) to (v) both inclusive' shall be substituted.

4. For rule 2A of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"2A. Application of rules to the State Bank of India, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and other banking institutions notified under section 51 of the Act. These rules and the Forms appended thereto, excluding rules 6 to 10 and Forms II to V and XI, shall also apply, so far as may be, to the State Bank of India or a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or any other banking institution notified under section 51 of the Act, as they apply to and in relation to banking companies incorporated in India :

Provided that in the rules and Forms as so applied, the expression "registered office" shall mean "the central office or the head office, as the case may be."

5. Rule 10A of the said rules shall be omitted.

6. In rule 11 of the said rules—

(i) in clause (a), for the expression "Form V", the expression "Form III" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the expression "Form VI", the expression "Form IV" shall be substituted; and

(iii) in clause (c), for the expression "Form VII", the expression "Form V" shall be substituted.

7. In rule 12 of the said rules, for the expression "Form VIII", the expression "Form VI" shall be substituted.

8. In rule 13 of the said rules, for the expression "Form IX", the expression "Form VII" shall be substituted.

9. In rule 15A of the said Rules, for the expression "Form XIII", the expression "Form XI" shall be substituted.

10. For Form I appended to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—

THE BANKNG REGULATION ACT, 1949

FORM I (See Rule 5)

Section 10

(To be submitted in dupliate to the Reserve Bank not later than the 31st January each year)

Name of the banking company ——————————————

Name and designation of the officer submitting the return ——————————————

Remuneration* paid during the year ended the 31st December ——————————————

(a) by a banking company incorporated in India to each of its directors and the first ten highest paid employees wherever employed;

(b) by a banking company incorporated outside India to the first ten highest paid employees in India.

Section I							Section II								Section III													
									Other payments																			
							Sitting Fees		Travelling Allowance		Halting Daily Allowance		Others (Nature to be specified)			Allowances					Other benefits			Perquisites				
Name	Age	Qualification	Experience in banking and non-banking institutions	Date of appointment/re-appointment	Designation	Total remuneration paid during the year ended 31st December vide Section II or Section III	Rate per meeting	Amount paid	Rate	Amount paid	Rate	Amount paid	Rate	Amount paid	Salary	Dearness Allowance	House Allowance	Conveyance Allowance	Local Allowance	Other-Allowances (Nature to be specified)	Contribution to Provident Fund.	Bonus	Others (Nature to be specified)	Free or subsidised residential accommodation.	Free or subsidised use to cars.	Salary paid to the servants attached to the house-hold, if any.	Others (Nature to be specified)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

A. Directors

1.

2.

3. etc.

B. Other Employees

1.

2.

3. etc.

Date : Signature :

*Remuneration includes salary, fees and perquisites but shall not include any allowances or other amounts paid for the purpose of reimbursing any expenses actually incurred in the performance of duties. In the case of a banking company Incorporated outside India, taxes, paid on behalf of employees should be shown separately in column 29.

Note: (i) Chief Executive Officer of the bank should be indicated in the remarks column against the name of the director or other employees.

(ii) In the case of a managing or whole-time director or of a director not liable to retire by rotation or of a manager or a Chief Executive Officer, details of the terms of appointments in force for the entire year may be mentioned in column 29.

(iii) In Section II particulars in respect of director should be given. In Section III particulars in respect of Chief Executive Officer, by whatever name called, and other employees should be given. The particulars in column 10 to 13 should also be given in respect of the Chief Executive Officer.

(iv) In the case of columns 25 to 28 the monetary equivalent of the perquisites should be given.

11. Forms III and IV appended to the said rules shall be omitted.

12. Forms V, VI and VII appended to the said rules shall be renumbered respectively as Forms III, IV, and V.

13. For Form VIII appended to the said rules, the following Form shall be substituted, namely:—

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

FORM VI (See Rule 12)

(Section 23)

Form of application for permission to open a new place of business or change the location (otherwise than within the same city, town or village) of an existing place of business under Section 23 of the Act.

Address————————

Date————————

————————

Department of Banking Operations and Development,

Reserve Bank of India,*

————————

Dear Sir,

We hereby apply for permission to* open a new place of business at————————

change the location

of an existing place of business from ————to————in terms of section 23 of the Banking Regulation Act, 1949. We give below the necessary information in the form prescribed for the purpose.

Yours faithfully,

Signature————

(1) Name of the banking company:

(2) Proposed Office. Give the following information :

(a) Name of city/town/village:

(In case the place is known by more than one name, the relative information should also be furnished)

(b) Name of locality/Location :

(c) Name of taluk, district and State:

(d) Status of the proposed office:

(e) The distance between the proposed office and the nearest existing commercial bank office together with the name of the bank and that of the centre/locality.

@ (f) Names of the commercial banks and the number of their offices functioning within a radius of 5 Kms. together with the names of centres where these are functioning.

(3) Previous applications.
Give particulars of applications, if any, previously made to the Reserve Bank in respect of the proposed place of business.

(4) Reasons for the proposed offices.
State detailed reasons for the proposed office and give statistical and other data, as under, which may have been collected for the proposed office.

(i) Population of the place.

@ (ii) Particulars of the command area (i.e. the area of operation of the proposed office

(a) Approximate radius of the command area.

(b) Population.

(c) Number of Villages in the command area.

(iii) The volume and value of agricultural, mineral and industrial production and imports and exports of the area of operation of the proposed office as under:

Commodity	Production		Imports		Exports	
	Volume	Value	Volume	Value	Volume	Value
1	2	3	4	5	6	7

(iv) If there are schemes for agricultural, mineral or industrial development give details of the same and their probable effects on the volume and value of the present production, imports and exports.

(v) If the existing baking facilities are considered inadequate, give reasons.

(vi) Prospects:—Give, as under, an estimate of the minimum business which the banking company expects to attract at the proposed office within 12 months.

(a) Deposits : Amount in thousands of rupees.

(b) Advances : Amount in thousands of rupees.

(5) Change of location of an existing Office:
Give the exact location of the office which is proposed to be closed and of the place to which it is proposed to be shifted giving particulars of the new locations as in items (2), (3) and (4).

(6) Expenditure :
State the amount already spent or proposed to be spent on staff, premises, furniture, stationery, advertising etc. in connection with the proposed office. Also state the minimum income which the banking company expects to earn at the proposed office within 12 months.

(7) Other particulars:
Any additional facts which the banking company may wsih to adduce in support of its application.

* The portion not applicable to be struck off.

@ The information need be furnished only in the case of applications for centres with a population of less than one lakh.

N.B.:—

1. The words 'office' and 'offices' wherever they occur in this form include a place or places of business at which deposits are received, cheques cashed, moneys lend or any other form of business referred to in sub-section (1) of section 6 of the Act is transacted.

2. Item (5) to be replied to if the application is for changing the location of an existing place of business.

3. If a banking company is unable or unwilling to supply full details in respect of any of the items, reasons for the omission may be given.

4. The information asked for in items (2), (3), (4), (5) and (6) is to be given separately for each office where the application relates to the opening of or changing the location of more than one office.

5. In the case of change of the location of "administrative office", where no banking business is transacted or proposed to be transacted (such as "Registered Office, Central Office or Head Office") only an application in the form of a letter need be submitted, indicating the reasons for the change.

14. Form IX appended to the said rules shall be renumbered as Form VII.

15. For Forms X, XI and XII, the following Forms shall be substitued, namely :—

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

FORM VIII

(Sections 18 and 24)

Name of the banking company.....

Name and designation of the officer submitting the return.....

Statement of demand and time liabilities and cash, gold and unencumbered approved securities for the month of.....

(To be furnished to the Reserve Bank not later than 15 days after the end of the month to which it relates)

(Rounded off to the nearest thousand)

	As at the close of business on				
	1st Friday	2nd Friday	3rd Friday	4th Friday	5th Friday
	(a)	(a)	(a)	(a)	(a)
A. LIABILITIES IN INDIA :					
1. Demand Liabilities (Less borrowings from the Reserve Bank, the State Bank of India, Industrial Development Bank of India and Agricultural Refinance Corporation and notified banks*)					
2. Time Liabilities (Less borrowings from the Reserve Bank, the State Bank of India, Industrial Development Bank of India and Agricultural Refinance Corporation and notified banks*).					
3. TOTAL OF A1 AND A2					

B. 1. Minimum amount of assets required to be held under section 24 of the Act (25 per cent of A3)

2. Minimum amount of cash reserve required to be held under section 18 of the Act (3 per cent of A3)†

	As at the close of business on				
	1st Friday	2nd Friday	3rd Friday	4th Friday	5th Friday
C. ASSETS IN INDIA :					
1. (a) Cash in hand					
(b) Balances with the State Bank of India in current account					
(c) Balances with notified banks** in current account					
2. Total of (a), (b) and (c) under CI					
3. Balances with the Reserve Bank in current account					
4. Total of C2 and C3†					
5. Cash and/or balances required to be maintained under section 18 of the Banking Regulation Act +					
Balances required to be maintained under section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 + +					
6. Excess of C4 over C5 +					
7. Total of C2 and excess of C3 over C5 + +					
8. Gold (valued at a price not exceeding current market price) Unencumbered approved securities (valued at a price not exceeding current market price)					
9. Deposits required to be maintained with the Reserve Bank under sub-section (2) of section 11 of the Act (i) Cash					
(ii) Unencumbered approved securities (valued at a price not exceeding current market price)					
10. Total of C6, C7, C8 and C9					
*11. Savings deposits					
(a) Demand liability portion					
(b) Time liability portion					
Total :					

Date..... Signature.....

(a) Give dates [where Friday is a holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), the preceding working day].

*'Notified bank' means any banking institution notified by the Central Government under clause (c) of the Explanation to sub-section (1) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).

**'Notified bank' means any other bank which may be notified by the Central Government under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949.

+For non-scheduled banks only.

+ +For scheduled banks only.

†Applicable to non-scheduled banks only.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

FORM IX

(Section 26)

Name of the Banking Company.....

Name and Designation of the officer submitting the return.....

Return of unclaimed deposit accounts in India which have not been operated upon for 10 years or more as on the date of the return.

As on the 31st December.....

(To be submitted to the Reserve Bank within thirty days after the close of each calendar year)

Particulars	Current Accounts		Savings Bank Accounts		Fixed Deposits(including cash certificates, recurring deposits, etc.)		Totol	
	No. of A/cs.	Balance outstanding	No. of A/cs.	Balance outstanding	No. of A/cs.	Balance outstanding	No. of A/cs.	Balance outstanding
		Rs. P.		Rs. P.		Rs. p.		Rs. p.
Balance brought forward from the previous return as on 31-12-19.....								
Accounts, if any, inadvertently omitted in the previous returns.....								
Additions during 19.....*								
Total								
**Accounts which have become operative or were closed during 19.....								
Total balance as at 31-12-19.....								

Add: Interest credited to the accounts during the year.

Less : Incidental charges levied to the accounts during the year.

Total

Signature.....

Date.....

* This item is intended to denote actual balances in accounts which have, since the date of the immediately previous return, become inoperative for ten years. If any of the accounts, which should have been included under this item in the previout returns, have been inadvertently omitted from those returns, they should be shown under the separate sub-head "Accounts, if any, inadvertently omitted from the previous returns" immediately below "Balance brought forward from the previous return as on 31-12-19.....". Particulars of such accounts should be given under all columns of the statement.

** This item is intended to denote the outstanding balances in such of the accounts (shown in the previous returns) as have become operative on account of further deposits or withdrawals or were closed during the year, after taking into consideration the additions thereto on account of interest credited and deductions therefrom on account of incidental charges applied. The difference (if any), between the out standing balance thus reported and that shown in the previous return should be suitably explained.

FORM X

Liabilities and Assets in India of Commercial Banks as on the last Friday of the month of 19

PART I

(Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949)
(Rounded off to the nearest thousand)

A. Liabilities in India

1. Paid-up capital (including* forfeited Shares)
2. Reserve Fund and other Reserves
   - 2.1 Reserve Fund
   - 2.2 Other Reserves
   - 2.3 Share Premium Account*
3. Deposits
   - 3.1 Current Deposits
     - 3.1.1 From Banks (including co-operative Banks)
     - 3.1.2 From Others
   - 3.2 Savings Deposits
   - 3.3 Fixed Deposits (including cash certificates, recurring deposits, etc.)
     - 3.3.1 From Banks (including co-operative Banks)
     - 3.3.2 From others

B. Assets in India

1. Cash in hand
2. Balances with the Reserve Bank of India
3. Balances with other banks in India in current account
   - 3.1 The State Bank of India
   - 3.2 Subsidiaries of the State Bank of India
   - 3.3 Other Commercial Banks
   - 3.4 Co-operative Banks
4. Money at call and Short Notice
   - 4.1 With commercial Banks
   - 4.2 with Co-operative banks
   - 4.3 With other financial institutions.
5. Investment
   - 5.1 Treasury bills
   - 5.2 Other Central Government securities (including Treasury Savings Deposit Certificates & Postal Savings Certificates and Deposits)

4. Borrowings
   - 4.1 Borrowings from banks in India
     - 4.1.1 Reserve Bank of India
     - 4.1.2 State Bank of India
     - 4.1.3 Subsidiaries of the State Bank of India
     - 4.1.4 The Industrial Development Bank of India
     - 4.1.5 Agricultural Refinance Corporation
     - 4.1.6 Other Commercial Banks
     - 4.1.7 Co-operative Banks
   - 4.2 Borrowings from banks outside India

5. Other Liabilities
   - 5.1 Bills payable in India
     - 5.1.1 Drawn by Indian Offices
     - 5.1.2 Drawn by foreign offices*
   - 5.2 Bills payable outside India
   - 5.3 Calls received in advance*
   - 5.4 Miscellaneous liabilities

6. Branch Adjustments@
   - 6.1 Among offices in India
   - 6.2 With offices outside India**

7. Total demand and time liabilities i.e. total of items A3, A4, and A5

8. Balance of profit

Total Liabilities

5.3 State Government Securities
5.4 Other approved securities
5.5 Shares and debentures of companies & Corporations not included in 5.4 above
5.6 Fixed deposits with banks (including co-operative banks)
5.7 Other investments in India

6. Bills purchased and discounted
   - 6.1 Inland Bills purchased and discounted
   - 6.2 Foreign Bills purchased and discounted
     - 6.2.1 Export Bills drawn in India
     - 6.2.2 Import Bills drawn on and payable in India
     - 6.2.3 Other foreign bills purchased and discounted
       - 6.2.3.1 Payable in India
       - 6.2.3.2 Payable Outside India

7. Loans and Advances
   - 7.1 Loans and Advances, Cash credits and overdrafts (excluding due from banks vide item 7.2 below)
   - 7.2 Due from banks
     - 7.2.1 Co-operative banks in India
     - 7.2.2 Commercial banks in India
     - 7.2.3 Banks outside India†

8. Premises, furniture, fixtures, and other fixed assets

9. Branch adjustments@
   - 9.1 Among offices in India
   - 9.2 With offices outside India**

10. Capitalised expenses including preliminary expenses, organisational expenses, shares selling commission, brokerage, loss incurred and any other expenditure not represented by tangible assets***

11. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims

12. Other tangible assets

Total Assets

PART II

Total Advances (Total of items 6 and 7 of Assets in Part I above)			Percentage of clean (unsecured) advances to total advances Percentage of columns 2 to 3	Total Deposits (items 3 of Liabilities in Part I)	Percentage of Total Advances to Total Deposits (percentage of columns 3 to 5)
Secured	Unsecured (Clean)	Total			
1	2	3	4	5	6

PART III

(Section 25)

(Rounded off to the nearest thousand)

1. Demand and time liabilities in India (Item 7 of Liabilities in Part I)

(excluding items which banks are at present allowed to exclude e.g. items not in the nature of outside liabilities)

2. Minimum amount of assets required to be held in India under sectoin 25 of the Act (75 per cent of item 1 above)
3. Assets in India.

3.1 Total of items B.1 to B.8, B.11 and B.12 on assets side in Part I.

3.2 Securities approved by the Reserve Bank of India under section 25 (3)(a) of the Act and not included in 3.1 above.

Signature

Date.....

Designation

*Not applicable to foreign banks operating in India.

@The net balance or branch adjustments should be shown as liabilities or assets as the case may be.

**Please give in a foot-note the outstanding borrowings of India offices.

†Comprising rupee loans/overdrafts granted to banks/correspondents outside India.

***If the balance in the profit and loss account represents loss, it should be included in this item.

Notes :

(1) Data under Parts I and II may be furnished as at the close of business on the last Friday of every month and under Part III as at the close of business on the last Friday of March, June, September and December.

(2) Data on foreign liabilities and assets of Indian offices of banks may please be supplied for the following items :
(i) Balances held abroad
(ii) Investments held abroad
(iii) Other foreign bills purchased and discounted payable outside India
(iv) Any other assets held outside India

(3) Co-operative banks comprise State and Central Co-operative banks, co-operative land mortgage banks and primary co-operative banks.

(4) If the concerned Friday is a public holiday under the Negotiable Instruments Act, 1881 (26 of 1881), at the close of business on the preceding working day.

16. Form XIII appended to the said rules shall be renumbered as Form XI.

[No. F. 3/4/74-B.O.I]

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1975

का० आ० 5245.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध व्यवस्थाएं) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री ए० के० दत्त के स्थान पर वित्त मंत्रालय बैंकिंग विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री के० पी० ए० मेनोन को एतद्द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

सं० एफ० 9 (2)/75-बी० ओ० 1 (1)

New Delhi, the 22nd November, 1975.

S.O. 5245.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri K. P. A. Menon, Joint Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of Punjab National Bank, vice Shri A K. Dutt.

[No. F. 9/2/75-B.O. 1(1)]

का० आ० 5246.—राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध व्यवस्थायें) योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री ए० के० दत्त के स्थान पर वित्त मंत्रालय, बैंकिंग विभाग, नयी दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री के० पी० ए० मेनोन को एतद्द्वारा इलाहाबाद बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9(2)/75-बी० ओ० 1(2)]

ल०द० कटारिया, निदेशक

S.O. 5246.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri K. P. A. Menon, Joint Secretary, Department of Banking, Ministry of Finance, New Delhi as a Director of Allahabad Bank, vice Shri A. K. Dutt.

[No. F. 9/2/75-B.O. I(2)]

L. D. KATARIA, Director

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1975

का० आ० 5247.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्द्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध इसलामपुर अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसलामपुर, जिला सांगली (महाराष्ट्र) पर 25 जनवरी, 1973 से 25 जुलाई, 1974 तक की अवधि के लिए लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8/4/75-ए० सी०]

New Delhi, the 24th November, 1975

S.O. 5247.—In exercise of the powers conferred by section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section(1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Islampur Urban Co-operative Bank Ltd., Islampur, District Sangli (Maharashtra) for the period form 25 January 1973 to 25 July 1974.

[No. F. 8/4/75-AC]

का० आ० 5248.—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठितधारा 53 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्ध 1 मार्च, 1975 से 29 फरवरी, 1976 तक की अवधि के लिए शिवसागर डिस्ट्रिक्ट सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड और कामरूप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लागू नहीं होंगे।

[सं० एफ० 8 (4)/75-ए० सी०]

हृषीकेश गुहा, अवर सचिव

S.O. 5248.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (1) of Section 11 of the said Act shall not apply to the Sibsagar District Central Cooperative Bank Ltd. and Kamrup District Central Co-operative Bank Ltd. for the period from 1st March 1975 to 29th February 1976.

[No. F. 8(4)/75-AC]

H. K. GUHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० आ० 5249.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश, 1975 (1975 का 13) की धारा 11 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्थानीय मुख्य कार्यालय, कानपुर के स्टाफ अफसर श्री एस० चिन्तामणि को, गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर, के अध्यक्ष श्री के० डी० अग्रवाल की 1 दिसम्बर, 1975 से आरम्भ होने वाली तथा 13 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होने वाली, छुट्टी की अनुपस्थिति की अवधि के लिए, उक्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 4-13/75-ए० सी०]

के० भवानी, उप सचिव

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5249.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 11 of the Regional Rural Banks Ordinance,1975 (13 of 1975), the Central Government hereby appoints Shri S. Chintamani, Staff Officer, State Bank of India, Local Head Office, Kanpur, to act as the Chairman of the Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank, Gorakhpur during the period of absence of leave of Shri K. D. Agrawal, Chairman of the said Kshetriya Gramin Bank, commencing on 1st December, 1975 and ending with 13th December, 1975.

[No. F. 4-13/75-AC]

K. BAVANI, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

आय-कर

का० आ०5250.- आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 49 (फा० सं० 261/13/72-आई टी जे) तारीख 4-3-1972 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

उक्त अनुसूची में —

(i) 'ग' रेंज कलकत्ता के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा :—

1. कम्पनी जिला 3 कलकत्ता (क से च वार्ड)।
2. को-आपरेटिव हाउसिंग सर्किल, कलकत्ता।

(ii) 'क च' रेंज, कलकत्ता के सामने निम्नलिखित रखा जाएगा:—

1. कम्पनी जिला 5 कलकत्ता।
2. जूट सर्किल, कलकत्ता।
3. को-आपरेटिव सर्किल, कलकत्ता।

यह अधिसूचना 25-7-1975 से प्रभावी होगी।

[सं० 979 (फा० सं० 261/8/75-आई टी जे)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 23rd July, 1975

INCOME-TAX

S.O. 5250.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule appended to its Notification No. 49 (F. No. 261/13/72-ITJ) dated 4-3-1972 as amended from time to time, viz.

In the said Schedule—

I. Against "C" Range, Calcutta following shall be substituted :—

1. Comp. Dist. III Calcutta (A to F Wards).
2. Co-operative Housing Circle, Calcutta.

II. Against "AF" Range, Calcutta following shall be substituted :—

1. Comp. Distt. V Calcutta.
2. Jute Circle, Calcutta.
3. Co-operative Circle, Calcutta.

This notification shall take effect from 25-7-1975.

Explanatory Note :—The amendment has become necessary consequent on creation of Co-operative Circles Calcutta.

The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 979 (F. No. 261/8/75-ITJ]

का० आ०5251.—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित्त इसे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष

कर बोर्ड, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 728 (फा० सं० 261/5/74-आई टी जे) तारीख 30 सितम्बर, 1974 से उपाबद्ध अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

2. उक्त अनुसूची में, विशेष रेंज-1 और विशेष रेंज-3, नई दिल्ली के सामने स्तम्भ 3 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी :—

क्रम सं०	रेंज	आय-कर सर्किल/वार्ड/जिले
1.	विशेष रेंज - 1	(i) कम्पनी सर्किल 2, 7, 12 13 और कम्पनी सर्किल 14, 16, 19 और 20 (ii) घ-1, जिला, नई दिल्ली ।
2.	विशेष रेंज-3 नई दिल्ली ।	(i) कम्पनी सर्किल 3, 10, 15, नई दिल्ली । (ii) विशेष सर्किल 3, नई दिल्ली । विशेष सर्किल 4 और 4 (अतिरिक्त) नई दिल्ली । (iii) चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स सर्किल, नई दिल्ली ।

जहां इस अधिसूचना द्वारा कोई आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग एक रेंज से दूसरे रेंज को अन्तरित हो जाता है, वह उस आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसके भाग में किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व उस रेंज के, जिससे वह आय-कर सर्किल, वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित अपीलें, उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होगी, उस रेंज के, जिसे उक्त सर्किल वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक आयुक्त (अपील) को अन्तरित कर दी जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी ।

यह अधिसूचना 25-7-1975 से प्रभावी होगी ।

[981 [फा० सं० 261/4/75-आई टी जे]

एस० रामस्वामी, अवर सचिव

S.O. 5251.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in that behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the schedule appended to its notification No. 728 (F. No. 261/5/74-ITJ) dated the 30th September, 1974 as amended from time to time.

2. In the said schedule the entries in column 3 against Special Range-I and Special Range-III, New Delhi shall be substituted by the following :—

S.No.	Range	Income-tax Circles/Wards/ Districts
1.	Special Range I	(i) Coy. Circles, II, VII, XII, XIII & Coys. Circle XIV, XVI, XIX & XX. (ii) D-I, Distt., New Delhi.
2.	Special Range III New Delhi.	(i) Coys. Circle, III, X, XV, New Delhi. (ii) Special Circles III, New Delhi, Special Circles IV & IV (Addl.) New Delhi. (iii) Chartered Acctts. Circle, New Delhi.

Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this notification from one Range to another Range appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof and pending immediately before the date of this notification before the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range from whom that Income-tax Circle, Ward or District or part thereof is transferred shall from the date this notification takes effect, be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of the Range to whom the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred.

This notification shall take effect from 25-7-1975.

Explanatory Note.—The amendment has become necessary consequent on redistribution the work load between AACs Special Range I and III New Delhi.

(The above note does not form a part of notification but is intended to be merely clarificatory).

[No. 981 (F.No. 261/4/75-ITJ]

S. RAMASWAMI, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1975

का. आ. 5252.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि पीतल की कला वस्तुओं का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाए ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) द्वारा यथा उपेक्षित निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है ।

अतः, अब, उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार जनता की, जिसकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए उक्त प्रस्तावों को प्रकाशित करती है ।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देने की वांछा रखने वाला कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, निर्यात निरीक्षण परिषद् (वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट, आठवीं मंजिल, कलकत्ता-700001 को भेज सकेगा ।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करने के लिए कि पीतल की कला-वस्तुओं का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाएगा ।

(2) इस आदेश के उपाबंध-1 में दिये गए पीतल की कला-वस्तुओं के निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1975 के प्रारूप के अनुसार निरीक्षण के प्रकार को निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए जो ऐसी पीतल की कला-वस्तुओं पर निर्यात से पूर्व लागू किया जाएगा ।

(3) इस आदेश के उपाबंध-2 में दिए गए न्यूनतम विनिर्देशों के अधीन रहते हुए, पीतल की कला-वस्तुओं के लिए निर्यात कर्ता द्वारा घोषित निर्यात संविदा के स्वीकृत विनिर्देशों को पीतल की कला वस्तुओं के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देने के लिए ।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान ऐसी पीतल की कला-वस्तु के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करने के लिए, जब तक

कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाणपत्र न हो कि ऐसी पीतल की कला-वस्तुएं निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करती हैं तथा निर्यात-योग्य हैं।

2. इस आदेश में 'पीतल की कला वस्तु' से पीतल की बनी वह वस्तु अभिप्रेत है जिस पर कला कार्य हो और जो सजावट के प्रयोजन के लिए आशयित हो।

उपाबंध-1

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाए जाने के लिए प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम पीतल की कला वस्तुओं का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है।

(ख) 'अभिकरण' से अधिनियम की धारा 7 के अधीन कोचीन, मद्रास, कलकत्ता, मुम्बई तथा दिल्ली में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) 'पीतल की कला वस्तु' से पीतल की बनी वह वस्तु अभिप्रेत है जिस पर कला कार्य हो और जो सजावट के प्रयोजन के लिए आशयित हो।

3. **निरीक्षण का आधार.**—निर्यात के लिए आशयित पीतल की कला वस्तु का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया—(1) पीतल की कला वस्तुओं का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना लिखित रूप में देगा तथा ऐसी सूचना के साथ, ऐसे निर्यात से संबंधित निर्यात संविदा में बताए गए विनिर्देशों की घोषणा भी किसी अभिकरण को देगा, जिससे वह नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा घोषणा पोत-लदान की अनुसूचित तारीख से कम से कम दस दिन पहले दी जाएगी। सूचना की एक प्रति उसी समय निर्यात निरीक्षण परिषद् के निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी कार्यालय को, जो भी निरीक्षण के स्थान से निकटतम हो, भेजी जाएगी, अर्थात् :—

मुख्य कार्यालय	निर्यात निरीक्षण परिषद् 'वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर' 14/1-बी, एजरा स्ट्रीट (आठवीं मंजिल), कलकत्ता-700001
क्षेत्रीय कार्यालय	1. निर्यात निरीक्षण परिषद्, अमन चेम्बर्स, पांचवीं मंजिल, 113, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई-400004
	2. निर्यात निरीक्षण परिषद् मनोहर बिल्डिंग, महात्मा गांधी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011
	3. निर्यात निरीक्षण परिषद्, 13/37, पश्चिमी विस्तार क्षेत्र, आर्य समाज रोड, नई दिल्ली-110005

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने पर, अभिकरण नियम 3 तथा इस विषय में परिषद् द्वारा जारी किए गए निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार पीतल की कला वस्तुओं का निरीक्षण करेगा।

(4) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात्, अभिकरण उसी समय परीक्षण के पैकेजों को इस ढंग से यह सुनिश्चित करने के लिए मोहरबन्द करेगा कि उनको बिगाड़ा नहीं जा सके। परीक्षण के अस्वीकृत किए जाने की दशा में, यदि निर्यात कर्ता ऐसा चाहे, परीक्षण अभिकरण द्वारा मोहरबंद या स्टाम्पित नहीं किया जाएगा या उस पर स्टैंसिल नहीं बनाया जाएगा किन्तु, ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता परीक्षण के अस्वीकृत किए जाने के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

(5) जब अभिकरण का यह समाधान हो जाए कि पीतल की कला-वस्तुओं का परीक्षण मान्य विनिर्देश की अपेक्षाओं के अनुरूप है, तो वह निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् 3 दिन के भीतर, यह घोषणा करते हुए निर्यात कर्ता को प्रमाणपत्र दे देगा कि परीक्षण निरीक्षण से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा निर्यात योग्य है,

परन्तु, यदि अभिकरण का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह उक्त तीन दिन की अवधि के भीतर ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर देगा तथा इस प्रकार इंकार किए जाने की सूचना, उसके कारणों सहित, निर्यातकर्ता को देगा।

5. **निरीक्षण का स्थान.**—इन नियमों के अधीन निरीक्षण केवल विनिर्माता के परिसर पर ही किया जाएगा।

6. निरीक्षण फीस :—इन नियमों के अधीन ऐसे परीक्षण के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के प्रत्येक सौ रुपयों के लिए 50 पैसे की दर से फीस, एक या अधिक परीक्षणों के निरीक्षणार्थ जाने हेतु सौ रुपयों की न्यूनतम फीस के अधीन रहते हुए, निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस के रूप में दी जाएगी।

7. अपील—(1) नियम 4 के उप-नियम (5) के अधीन ऐसे प्रमाणपत्र के देने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उसके द्वारा, इस प्रकार इंकार किए जाने की सूचना की प्राप्ति से 10 दिन के भीतर, इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक सात व्यक्तियों के विशेषज्ञों के पैनल को अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल में कुल सदस्यता के दो तिहाई सदस्य गैर सरकारी होंगे ।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन की होगी ।

(4) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(5) अपील का, प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर, निपटारा कर दिया जाएगा ।

उपाबंध 2

[पैरा 2 का उप-पैरा (3) देखिए]

पीतल की कला वस्तुओं के लिए न्यूनतम विनिर्देश

1. सामग्री—कला वस्तुएं कम से कम 58 प्रति शत तांबे वाले पीतल से बनाई जाएंगी ।

2. परिमाप—आकार, परिमाप तथा अन्य संरचनात्मक विवरण क्रेता एवं निर्यातकर्ता के बीच किए गए करार के अनुसार होंगे ।

3. **कर्म-कौशल तथा परिसज्जा (फिनिश)**

3. (1) कला वस्तुएं विकृति चिन्हों, भुर्रियों सरन्ध्रता तथा वात-छिद्रों से रहित होंगी ।

(2) सभी जोड़ बहुत अच्छी तरह चिकने किए जाएंगे, तेज किनारे गोल किए जाएंगे या खूट्टल किए जाएंगे तथा उन पर मजबूती से पीतल का टांका लगाया जाएगा या झाला जायेगा । जहां कहीं भी लागू हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिसने नहीं पावेगा उपयुक्त परीक्षण किया जाएगा ।

(3) पैकिंग—कला वस्तुएं क्रेता की अपेक्षाओं के अनुसार तथा इस रीति से पेक की जाएंगी कि वे गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकें ।

[सं. 6(21)/नि. नि. तथा नि. सं.]

के. वी. बालसुब्रह्मण्यम, उप-निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 13th December, 1975

S.O. 5252.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to do for the development of the export trade of India that brass artware shall be subject to inspection prior to export.

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council, as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 :

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that any person desiring to forward any objections or suggestions with respect to the said proposals may forward the same within thirty days of the date of publicaiton of this Order in the Official Gazette, to the Export Inspection Council, "World Trade Centre" 14/1B, Ezra Street, 7th Floor, Calcutta-700001.

PROPOSALS

(1) To notify that brass artware shall be subject to inspection prior to export ;

(2) To specify the type of inspection in accordance with that draft Export of Brass Artware (Inspection) Rules, 1975, set out in Annexure I to this Order as the type of inspection which would be applied to such brass artware prior to export ;

(3) To recognise the specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract for brass artware subject to a minimum of the specifications as set out in Annexure II to this Order, as the standard specifications for brass artware.

(4) To prohibit the export, in the course of international trade, of any such brass artware, unless the same is accompanied by a certificate issued by one of the Agencies established by the Central Government under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that such brass artware satisfy the conditions relating to inspection and is export-worthy.

In this Order Brass Artware shall mean an article made of brass, having art work on it and intended for decorative purposes.

ANNEXURE-I

DRAFT RULES PROPOSED TO BE MADE UNDER SECTION 17 OF THE EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) ACT, 1963.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Brass Atrware (Inspection) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established at Cochin, Madras, Calcutta, Bombay and Delhi under Section 7 of the Act ;

(c) "Brass Artware" shall mean an article made of brass having art work on it and intended for decorative purposes.

3. Basis of Inspection.—Inspection of brass artware intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the standard specifications recognised by the Central Government under Section 6 of the Act.

4. Procedure of inspection :

(1) The exporter intending to export brass artware shall give intimation in writing of his intention so to do and submit along with such intimation a declaration of the specifications stipulated in the export-contract relating to such export to any of the Agencies to enable it to carry out the inspection in accordance with rule 3.

(2) Every intimation and declaration under sub-rule (1) shall be given not less than ten days before the schedule date of shipment. A copy of the intimation shall simultaneously be endorsed to any of the

following Offices of the Export Inspection Council, which is nearest to the place of inspection, namely :

Head Office

Export Inspection Council,
'World Trade Centre',
14/1-B, Ezra Street, (7th Floor),
Calcutta-700001.

Regional Offices :

1. Export Inspection Council,
Amin Chambers, 4th Floor,
113, Maharshi Karve Road,
Bombay-400004.

2. Export Inspection Council,
Monohar Buildings,
Mahatma Gandhi Road,
Ernakulam, Cochin-682011.

3. Export Inspection Council,
13/37, Western Extension Area,
Arya Samaj Road,
New Delhi-110005.

(3) On receipt of the intimation and declaration under sub-rule (1) the Agency shall carry out the inspection of brass artware in accordance with rule 3 and the instructions, if any, issued by the Council in this regard.

(4) After completion of the inspection, the Agency shall immediately seal the packages in the consignment in a manner as to ensure that the sealed goods cannot be tampered with. In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed or stamped or stencilled by the Agency. In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer an appeal against the rejection.

(5) When the Agency is satisfied that the consignment of brass artware complies with the requirement of the recognised specification, it shall issue within 3 days of completion of inspection, a certificate to the exporter declaring that the consignment satisfies the conditions relating to inspection and is exportworthy:

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period—three days refuse to issue such certificate and communicate such refusal to the exporter along with the reasons therefor.

5. Place of Inspection :—Inspection under these rules shall be carried out at the premises of the manufacturer only.

6. Inspection fee :—Subject to a minimum of rupees hundred per visit for one or more consignments a fee at the rate of fifty paise for every hundred rupees of f.o.b. value of such consignment shall be paid by the exporter to the Agency as inspection fee under these rules.

7. Appeal :

(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4, may, within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to the panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The panel will consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The decision of the panel on such appeal shall be final.

(5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its receipt.

ANNEXURE II

[See sub-paragraph (3) of paragraph 2]

Minimum specification for brass artwares.

1. Material.—Artwares shall be manufactured out of brass having a minimum copper content of 58 per cent.

2. Dimensions.—The shape, dimensions, and other constructional details shall be as per the agreement between the buyer and the exporter.

3. Workmanship and finish.—(1) The artwares shall be free from distortion, dents, wrinkles, porosity and blow holes.

(2) All joints shall be finished with a high degree of smoothness, sharp edges rounded off or deburred and shall be soundly brazed or soldered. Wherever applicable, a suitable test shall be conducted to ensure leak-proofness.

4. Packing : The artwares shall be packed in accordance with the requirements of the buyer and in such a manner as to ensure the safe arrival of the goods at the destination.

[No. 6(21)/74-BI & EP.]

K. V. BALASUBRAMANIAM, Dy. Director

(निर्यात उत्पादन विभाग)

नई दिल्ली, दिसम्बर, 1975

(समुद्री उत्पाद उद्योग-विकास नियंत्रण)

का०आ० 5253.—समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 3 तथा 4 के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 (1972 का 13) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० 2240, दिनांक 12 अगस्त 1972 द्वारा स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में निम्नोक्त व्यक्तियों को एतद्द्वारा नियुक्त करती है, अर्थात् :—

1. श्री टी०पी०के० नायर, अध्यक्ष
अध्यक्ष,
समुद्री उत्पाद निर्यात
विकास प्राधिकरण,
एम०जी० रोड,
एर्नाकुलम साउथ,
कोचीन-16।

2. श्री के० चिदाम्बरम, सदस्य-पदेन
निदेशक,
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास
प्राधिकरण, एम०जी० रोड,
एर्नाकुलम साउथ, कोचीन-16।

3. श्री ज्योतिर्मय बसु, सदस्य
सदस्य,
लोक-सभा।
4. श्री डी०पी० जदेजा, सदस्य } 16 अगस्त 1975 से
सदस्य,
लोक सभा।

5. श्री विश्वनाथन मेनन, सदस्य, राज्य सभा, 47, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली।	सदस्य	
6. श्री एस०पी० बालसुब्रह्मण्यम संयुक्त सचिव, कृषि विभाग, नई दिल्ली।	सदस्य	कृषि मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
7. श्री एस०वाई० गुप्ते, निदेशक, वित्त मंत्रालय।	सदस्य	वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
8. श्री बी०सी० पांडे, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।	सदस्य	वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
9. श्री जे०जी० राजाध्यक्ष, उप-सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।	सदस्य	औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए
10. श्री टी०के० सारंगन, जहाजरानी के वरिष्ठ उप-महानिदेशक, जहाजरानी महानिदेशालय, बम्बई।	सदस्य	जहाजरानी एवं परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
11. डायरेक्टर आफ फिशरीज, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)।	सदस्य	आंध्र प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
12. कमिश्नर आफ फिशरीज, गुजरात सरकार, गांधी नगर, अहमदाबाद, गुजरात।	सदस्य	गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
13. विकास सचिव, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम (केरल)।	सदस्य	केरल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
14. सचिव, कृषि तथा सहकारिता विभाग, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई।	सदस्य	महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
15. डायरेक्टर आफ फिशरीज, कर्नाटक सरकार, बंगलौर।	सदस्य	कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
16. सचिव, उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।	सदस्य	उड़ीसा सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
17. डायरेक्टर आफ फिशरीज, तमिलनाडु सरकार, मद्रास (तमिलनाडु)।	सदस्य	तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
18. सचिव, फिशरीज विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कलकत्ता।	सदस्य	बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
19. मुख्य सचिव, अंडमान तथा निकोबार प्रशासन।	सदस्य	अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
20. श्री टी०एम० जोसेफ, जार्ज मैजो एण्ड कं०, 14/15, सेनटोफ फर्स्ट स्ट्रीट, मद्रास, तमिलनाडु।	सदस्य	मत्स्य पोतों के मालिकों, प्रोसेसिंग संयंत्रों तथा समुद्री उत्पादों को स्टोर करने के स्थानों एवं समुद्री उत्पादों को लाने ले जाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वाहनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
21. एम्ब्रोस फर्नान्डो, गल्फ फिश एक्सपोर्ट हाउस, 41, करप्पा स्ट्रीट, तूतिकोरीन।	सदस्य	
22. श्री आर०डी० पुसालकर, अध्यक्ष, एवं प्रबंध निदेशक, न्यू इंडिया फिशरीज लि०, बम्बई।	सदस्य	
23. श्री एस०आर० बनर्जी, 11, पोल्लोक स्ट्रीट, पांचवी मंजिल, कलकत्ता।	सदस्य	
24. श्री एम० माधवराव, कर्नाटक कोरोनेट केनिंग एण्ड फिश प्लांट मालपे।	सदस्य	समुद्री उत्पादों का कारोबार करने वालों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
25. श्री सी० चेरियन, सेमीन्स (रजि०), XXiii/30, कोचंगदी, कोचीन।	सदस्य	
26. रिक्त (बाद में घोषित की जाएगी)।	सदस्य	समुद्री उत्पाद उद्योग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
27. श्री जी०के० कूरियन, निदेशक, सैंट्रल इंस्टिट्यूट आफ फिशरी, टेक्नोलोजी, एर्नाकुलम, कोचीन।	सदस्य	समुद्री उत्पाद उद्योग से संबंधित गवेषणाओं में लगे हुए गवेषणा संस्थानों में नियोजित व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए।
28. श्री ह०जे० फर्नान्डेस, एसमैरिए एक्सपोर्ट एन्टरप्राइसिस, क्विलोन।	सदस्य	धारा 4(3)(ई)(vi) के अधीन समुद्री उत्पादों के निर्यातकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया।
29. श्री माधवन नायर, कोचीन कं० (प्रा०) लि०, पो०बा० सं० 712, एम०जी० रोड, कोचीन-16 (केरल)।	सदस्य	

संसद सदस्यों तथा पदेन सदस्य को छोड़कर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जिनके नाम ऊपर दिये गए हैं, सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। संसद के तीन सदस्य 16 अगस्त, 1975 से 3 वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

[सं० फा० 5(14)/75-ई०पी० (एमी)-2]

बी० सी० पांडे, संयुक्त सचिव

(Department of Export Production)

New Delhi, the Dec., 1975

(MARINE PRODUCTS INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

S.O. 5253.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972 (13 of 1972), read with the rules 3

and 4 of the Marine Products Export Development Authority Rules, 1972, the Central Government hereby appoints the following persons to be members of the Marine Products Export Development Authority established by the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2240, dated the 12th August, 1972, namely :—

1.	Shri T.P.K. Nayar, Chairman, Marine Products Export Development Authority, M.G. Road, Ernakulam South, Cochin-16.	Chairman	
2.	Shri K. Chidambaram, Director, Marine Products Expori Development Authority, M.G. Road, Ernakulam South, Cochin-16.	Member—ex-officio	
3.	Shri Jyotirmoy Basu, Member, Lok Sabha.	Member	from 16th August 1975.
4.	Shri D.P. Jadeja, Member, Lok Sabha.	Member	
5.	Shri Viswanathan Menon, Member, Rajya Sabha, 47, North Avenue, New Delhi.	Member	
6.	Shri S.P. Balasubramaniam, Joint Secretary, Department of Agriculture, New Delhi.	Member	To represent the Ministry of Agriculture.
7.	Shri S.Y. Gupte, Director, Ministry of Finance.	Member	To represent the Ministry of Finance.
8.	Shri V.C. Pande, Joint Secretary, Ministry of Commerce.	Member	To represent the Ministry of Commerce.
9.	Shri J.G. Rajadhyaksha, Deputy Secretary, Ministry of Industrial Development, New Delhi.	Member	To represent the Ministry of Industrial Development.
10.	Shri T.K. Sarangan, Senior Deputy Director General of Shipping, Directorate General of Shipping, Bombay.	Member	To represent the Ministry of Shipping and Transport.
11.	Director of Fisheries, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, (Andhra Pradesh).	Member	To represent the Govt. of Andhra Pradesh.
12.	Commissioner of Fisheries, Govt. of Gujarat, Gandhi Nagar, Ahmedabad, Gujarat.	Member	To represent the Govt. of Gujarat.
13.	Development Secretary, Govt. of Kerala Trivandrum (Kerala).	Member	To represent the Govt. of Kerala.
14.	Secretary, Deptt., of Agriculture, and Cooperation, Govt. of Maharashtra, Bombay.	Member	To represent the Govt. of Maharashtra.
15.	Director of Fisheries, Govt. of Karnataka, Bangalore.	Member	To represent the Govt. of Karnataka
16.	Secretary to the Govt. of Orissa, Bhubaneswar (Orissa).	Member	To represent the Govt. of Orissa.
17.	Director of Fisheries Govt. of Tamilnadu, Madras, (Tamilnadu).	Member	To represent the Govt. of Tamilnadu.
18.	Secretary, Department of Fisheries, Govt. of West Bengal, Calcutta.	Member	To represent the Govt. of West Bengal.
19.	Chief Secretary, Andaman and Nicobar, Administration.	Member	To represent the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands.
20.	Shri T.M. Joseph, George Maijo and Co. 14/15, Contaph First Street, Madras-18, Tamilnadu.	Member	To represent the interests of the owners of the fishing vessels, processing plants and storage premises for marine products and conveyances used for the transport of the marine products.
21.	Shri Ambrose Farnande, Gulf Fish Export House, 41, Karappa Street, Tuticorin.	Member	
22.	Shri R.D. Pusalkar, Chairman and Managing Director, New India Fishery Ltd., Bombay.	Member	
23.	Shri S.R. Banerjee, 11, Pollock Street, 5th Floor, Calcutta.	Member	
24.	Shri M. Madhavaraj, Karnataka Coronet Canning and Fish Plant, Malpe.	Member	To represent the interests of dealers in the marine products.
25.	Shri C. Chorian, CHEMMENS (Regd.), XXIII/30, Kochangadi, Cochin.	Member	
26.	Vacant (To be announced later)	Member	To represent the interests of persons employed in the marine products industry.
27.	Shri G.K. Kurian, Director, Central Institute of Fishery Technology, Ernakulam, Cochin.	Member	To represent the interests of persons employed in research institutions engaged in the researches connected with marine products industry.
28.	Shri E.J. Fornandes, Esmario Export Enterprises, Quilon.	Member	Appointed to represent the interests of exporters in the marine products under section 4(3)(e)(vi).
29.	Shri Madhavan Nayar, Cochin Co. (P) Ltd., P.B. No. 1712, M.G. Road, Cochin-16 (Kerala).	Member	

2. The Chairman and the other members of the Marine Products Export Development Authority named above, other than the member ex-officio and the Members of Parliament shall held office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette. The three Members of Parliament shall held Office for a period of 3 years from the 16th August, 1975.

[No. F.5/14/72-EP (AGRI.II)

V. C. PANDE, Jt. Secy

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय,

आदेश

[नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

का० आ० 5254.—सर्वश्री एटलस इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज ग्रैण्ड ट्रंक रोड, बटाला को कच्चा माल और संघटकों का आयात करने के लिए 1,74,000 रुपये के लिए आयात लाइसेंस सं० पी०/डी/2199479 दिनांक 28-5-75 प्रदान किया गया था।

अब फर्म ने उक्त आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उनसे मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति उपयोग में लाए बिना और किसी भी सीमाशुल्क कार्यालय में पंजीकृत कराए बिना ही खो गई है।

अपने तर्क के समर्थन में आवेदक ने आयात व्यापार नियंत्रण, हैंडबुक, 1975-76 के पैरा 320 के अनुसार एक शपथ पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि मूल आयात लाइसेंस सं० पी०/डी/2199479 दिनांक 28-5-75 की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश देता है कि आवेदक को उक्त लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि जारी की जानी चाहिए। मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति यदि मिल जाएगी तो इस कार्यालय को रद्द करने के लिए भेज दी जाएगी।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति की अनुलिपि अलग से जारी की जा रही है।

[संख्या : टूल्ज/148- (आर एम)/74-75/आर एम-7]

ए० एन० चटर्जी, उप-मुख्य नियंत्रक

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

ORDER

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5254.—M/s. Atlas Engineering Industries, Grand Trunk Road, Batala were granted import licence No. P/D/2199479 dated 28-5-75 for Rs. 1,74,000 for the import of Raw Material and Components.

2. The firm have now requested for the issue of duplicate copy of Exchange Control Copy of the above said import licence on the ground that the original Exchange Control Copy has been lost without being utilised and without being registered with any Custom House.

3. In support of their contention, the applicant have filed an affidavit as required in para 320 of the import Trade Control, Hand Book of Rules & Procedure, 1975-76. The undersigned is satisfied that the original Exchange Control Copy of import licence No. P/D/2199479 dated 28-5-1975 has been lost and directs that a duplicate Exchange Control Copy of the said licence should be issued to the applicant. The original Exchange Control Copy, if found, will be forwarded to this office for cancellation.

4. The duplicate copy of Exchange Control Copy of import licence is being issued separately.

[F. No. Tools/148-A(RM)/74-75/RM-7]

A. N. CHATTERJI, Dy. Chief Controller

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1975

का० आ० 5255.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसार केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा वैंकवर स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास में सहायक, श्री जे० एम० माथुर को तत्काल कौंसली एजेंट का कार्य करने का अधिकार देती है।

[फाईल सं० टी० 4330/2/75]

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 29th September, 1975

S.O. 5255.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri J. M. Mathur, Assistant in the Consulate General of India, Vancouver to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330(2)/75]

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1975

का० आ० 5256.—राजनयिक एवं कौंसली अधिकारी (शपथ एवं फीस) अधिनियम, 1948 (1948 का 41 वां) के खंड 2 की धारा (क) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लोरेंको मारक्यूस स्थित भारत का राजदूतावास में सहायक, श्री ओ० पी० वासन को तत्काल कौंसली एजेंट का कार्य करने का अधिकार देती है।

[फाईल सं० टी-4330 (2)/75]

पी० आर० नाम्बिसन, अवर सचिव

New Delhi, the 13th November, 1975

S.O. 5256.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorises Shri O. P. Wason, Assistant in the Embassy of India, Laurenco Marques to perform the duties of a Consular Agent with immediate effect.

[File No. T. 4330(2)/75]

P. R. NAMBISAN, Under Secy.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 20, नवम्बर, 1975

का० आ० 5257.—यतः पेट्रोलियम पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3367 तारीख 4-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

ग्रौर, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल ग्रौर प्रकृतिक गेस आयोग में, सभी संधकों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

जंक्शन प्वाइंट से वाल्व प्लेटफार्म ग्रौर जंक्शन प्वाईंट से जी० जी० एस०/सी०टी० एफ० दक्षिणी कादी तक पाइप लाइन बिछाने के लिये

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कादी

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए०आर०ई	सैण्टीयर
1	2	3	4	5
कादी . .	1978	0	05	00
	1977	0	18	00
	1976	0	27	35
	1957	0	09	00
	1955	0	09	00
	1954	0	14	25
	1953	0	20	85
	कार्ट ट्रैक	0	05	25
	1855	0	05	25

[सं० 12016/2/74-एल० एन्ड एल]

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 20th November, 1975

S.O. 5257.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3367 dated 4-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines;

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section of the said Act, submitted report to the Government;

And Further Whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now Therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And Further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

FOR LAYING PIPELINE FROM JUNCTION POINT TO VALVE PLATFORM AND JUNCTION POINT TO GGS/CTF SOUTH KADI

STATE : GUJARAT DISTRICT : MEHSANA TALUKA : KADI

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
KADI	1978	0	05	00
	1977	0	18	00
	1976	0	27	35
	1957	0	09	00
	1955	0	09	00
	1954	0	14	25
	1953	0	20	85
	Cart track	0	05	25
	1855	0	05	25

[No. 12016/2/74-L&L.]

का० आ० 5258.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3238 तारीख 19-11-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

ग्रौर यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

ग्रौर आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से सलंग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।;

ग्रौर, आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल ग्रौर प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संधों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए० आर० ई०	सैण्टीएर
1	7	3	4	5
सैज . .	959	0	23	63
	963	0	64	28
	960	0	02	02
	969	0	03	08
	970	0	14	79

[सं० 12016/10/74-एल०एण्ड एल०]

S.O. 5258.—WHERES by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3238 dated 19-11-74 under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appendd to that notification for the purpose of laying pipelines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the Publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM WELL NOS. K-17, 110, 163 TO C.T.F.
STATE : GUJARAT DISTRICT : MEHSANA TALUKA : KALOL

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SAIJ	959	0	23	63
	963	0	64	28
	960	0	02	02
	969	0	03	08
	970	0	14	79

[No. 12016/10/74-L&L]

का० आ० 5259.—यतः पेट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 3716 तारीख 17-12-74 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी के उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी भारों से मुक्त रूप में इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

जी० जी० एस० सोभासन से सी० टी० एफ० कालोल तक पाइप-लाइन के लिए अतिरिक्त भूमि

राज्य गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कालोल, कादी, महसाना

गांव	सर्वेक्षण नं०	हैक्टेयर	ए०	आ०	सण्टीएर ई०
1	2	3	4		5
सेज	1306/पी०	0	06		15
पिछज	296/पीसे	0	04		20
अहजडरा	863/पी (रोड़)	0	03		00
	861/पी० (रोड़)	0	00		48
	862	0	14		40
	580	0	05		75
सोभासन	449/पी	0	11		55

[सं० 12016/14/74-एल० एन्ड एल०/1]

S. O. 5259.—Whereas by a notification of the Govt. of India in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. No. 3716 dated 17-12-74 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipleines.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedle appeneded to this notification;

Now therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from all encumbrances.

SCHEDULE

ADDITIONAL LAND FOR PIPELINE FROM GGS SOBHASAN TO CTF KALOL

STATE : GUJARAT DISTRICT: MEHSANA TALUKA : KALOL, KADI, MEHSANA

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
SAIJ	1396/P	0	06	15
PIEJ	296/P	0	04	20
ADUJDRA	863/P (Road)	0	03	00
	861/P (Road)	0	00	48
	862	0	14	40
	580	0	03	75
AMBASAN	449/P	0	11	55

[No. 12016/14/74-L&L/I]

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1975

का० आ० 5260.—यतः पैट्रोलियम, पाइपलाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ० सं० 2678 तारीख 16-8-75 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनें बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है ।

और, आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय भारतीय तेल निगम लि० में सभी संबंधों से मुक्त रूप में, इस घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

तालुका : सानन्द जिला : अहमदाबाद गुजरात राज्य

गांव	सर्वेक्षण नं०	क्षेत्र		
		एच०	ए०	वर्गमीटर
खोडा	300/5	0	04	85
	300/7	0	03	10
	1+2			
	300/4	0	00	40
	300/1	0	16	65

[सं० 12017/2/75-एल० एण्ड एल०]

टी० पी० सुब्रह्मनियम, अवर सचिव

New Delhi, the 21st November, 1975

S.O. 5260.—Whereas by a notification of the Govt. of India the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) S.O. 2678 Dated 16-8-75 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines :

And Whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And Further Whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now Therefore in exercise of the Power conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And Further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on the date of the publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

TALUKA : SANAND DISTRICT : AHMEDABAD GUJARAT STATE

Village	Survey No.	Extent	
		H.A.	Sq.M.
KHODA	300/5	0	04 — 85
	300/7	0	03 — 10
	1 + 2		
	300/4	0	00 — 40
	300/1	0	16 — 65

[No. 12017/2/75-L&L]

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

उद्योग तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1975

का० आ० 5261.—बहु-इकाई सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1942 (1942 का 6) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) की अधिसूचना संख्या 7/27/66-सी०एल०, तारीख 18, नवम्बर, 1974 को अधिक्रांत करते हुए केन्द्रीय सरकार उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव श्री ए० दास को सहकारी सोसाइटियों के केन्द्रीय राजिस्ट्रार के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[सं० एल०-11011/49/75-विधि तथा प्रबन्ध]

ने० कृष्णमूर्ति, उप-सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(Deptt. of Civil Supplies & Cooperation)

New Delhi, the 20th November, 1975

S.O. 5261.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Multi-unit Cooperative Societies Act, 1942 (6 of 1942) and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry and Civil Supplies (Deptt. of Civil Supplies and Cooperation) No. 7/27/66-C.L. dated the 18th November, 1974, the Central Government hereby appoint Shri A. Das, Joint Secretary in the Ministry of Industry and Civil Supplies, Department of Civil Supplies and Cooperation, as the Central Registrar of Cooperative Societies.

[No. L. 11011/49/75-L&M]

N. KRISHNAMURTHI, Dy. Secy.

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 1975

का० आ० 5262—केन्द्रीय सिल्क बोर्ड अधिनियम 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुच्छेद (च) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार कुटीर एवं लघु उद्योग, कलकत्ता के सचिव के स्थान पर कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, के संयुक्त सचिव को नामित करती है और 14 सितम्बर, 1973 के भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 482(इ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्र०सं० (9) के सामने "अधिनियम की 4(3)(च) के अधीन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नामित" की गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा, अर्थात्:—

"संयुक्त सचिव,
कुटीर एवं लघु उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता-1"

[फाइल सं० 6/24/75-सी० एण्ड एस०]

एस० एन० घोष, उप-निदेशक

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 25th November, 1975

S.O. 5262.—In exercise of the powers conferred under clause (f) of Sub-Section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby nominates the Joint Secretary to the Government of West Bengal, Cottage and Small Scale Industries, Department of that Government in place of the Secretary to the Government of West Bengal, Cottage and Small Scale Industries, Calcutta and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Industrial Development S.O. 482 (E) published in the Government of India Extraordinary Gazette dated 14th September, 1973, namely :—

In the said notification, for the entry against Serial No. (9) under "NOMINATED BY THE GOVERNMENT OF WEST BENGAL UNDER SECTION 4(3)(f) of the ACT" the following shal be substituted, namely:—

"Joint Secretary, Cottage & Small Scale Industries Deptt. Government of West Bengal Calcutta."

[F. No. 6/24/75/C&S]

S. N. GHOSH, Dy. Director.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1975

का०आ० 5263—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 27 मार्च, 1962 की अधिसूचना संख्या 16-15/61-एम० 1 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के प्रयोजनों के लिये बेलेन्सिया विश्वविद्यालय स्पेन) द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हता "लाइसेन्सिएडो-इन-मेडिसिन सिरुजिया" मान्य चिकित्सा अर्हता होगी;

और यतः डा० मान्टेगट फ्रिक्सास मेरिया डेल रोजारियो को जिसके पास उक्त अर्हता है अध्यापन और धर्मार्थ कार्य के प्रयोजनों के लिये फिलहाल सोसाइटी आफ क्राइस्ट जैसस गोमिया, बिहार के साथ सम्बद्ध है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के भाग (ग) का पालन करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(1) इस आदेश के सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि

अथवा

(2) उस अवधि को जब तक डा० माण्टेगट फ्रिक्साज मेरिया डेल रोजारिया, सोसाइटी आफ क्राइस्ट जैसस, गोमिया, बिहार के साथ सम्बद्ध रहते हैं, जो भी कम हो वह अवधि विनिर्दिष्ट करती है, जिसमें पूर्वोक्त डा० मैडिकल प्रैक्टिस कर सकेंगे ।

[सं० वी० 11016/23/75-एम०पी०टी०]

वि० कु० अग्निहोत्री, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 22nd November, 1975

S.O. 5263.—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Health No. 16-15/61-MI, dated the 27th March, 1962, the Central Government has directed that the medical qualification, Licenciado en Medicine Cirugia shall be recognised medical qualification for the purposes of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956);

And whereas Dr. Montagut Freixas Meria del Rosario who possesses the said qualification is for the time being employed with the Society of Christ Jesus, Gomia, Bihar for the purposes of teaching and charitable work;

Now, therefore, in pursuance of clause (c) of the proviso to sub-section (1) of section 14 of the said Act, the Central Government hereby specifies :—

(i) a period of two years from the date of publication of this order in the official Gazette, or

(ii) the period during which Dr. Montagut Freixas Meria del Rosario is employed wtih the said Society of Christ Jesus, Gomia, Bihar.

whichever is shorter, as the period to which the medical practice by the aforesaid doctor shal be limited.

[N. V. 11016/23/75-MPT]

V. K. AGNIHOTRI, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1975

का० आ० 5264.—मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 में संशोधन करने के लिये स्कीम का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 566, तारीख 14 फरवरी, 1975 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2), तारीख 22 फरवरी, 1975 के पृष्ठ——पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

और उक्त राजपत्र 28 फरवरी, 1975 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार नियोजन का (विनियमन) स्कीम, 1957 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन)——— संशोधन स्कीम, 1975 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. मद्रास अरजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1957 में,—

(i) खण्ड 10 के उपखंड (1) में, "और साथ ही साथ उसके पास ऐसी फीस जमा करेगा, जो इस निमित्त विहित की जाये" शब्दों का लोप किया जायेगा—

(ii) खंड 14-कक के उपखण्ड (2) में,—

(क) मद (i) की उपमद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना उसे उपमद (ख) के अधीन इस प्रकार नहीं हटाया जायेगा।";

(ख) मद (2) की उपमद (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना उपमद (घ) के अधीन ऐसी समाप्ति या उपमद (ङ) के अधीन पदच्युति नहीं की जायेगी।"

(iii) खण्ड (15) के उपखंड (3) में, "और ऐसी अपील में पारित आदेश अन्तिम होगा" शब्दों का लोप किया जायेगा;

(iv) खण्ड 16 के उपखण्ड (3क) में, निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जायेगा, अर्थात् :—

"और इस प्रकार पारित आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा"

[सं० एच० 11013/3/7/-पी०एण्ड डी०(ix)]

वी० शंकरलिंगम, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, the 22nd November, 1975

S.O. 5264.—Whereas certain draft scheme to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1949) at pages 714-15 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 22nd February, 1975 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 566, dated the 14th February, 1975 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 28th February, 1975;

And whreas no objections and suggestions have ben received from the public on the said draft by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme to amend the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957, namely :—

1. Short titel and comencement.—(1) This Scheme may be called the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Emp'oyment) Amendment Scheme, 1975.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Madras Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1957,—

(i) in sub-clause (1) of clause 10, the words 'and simultaneously deposit with him such fees as may be fixed from time to time, in this behalf" shall be omitted;

(ii) in sub-clause (2) of clause 14-AA,

(a) after sub-item (b) of item (i), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no such removal under sub-item (b) shal be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.";

(b) after sub-item (e) of item (ii) the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under sub-item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.";

(iii) in sub-clause (3) of clause (15), the words "and the order passed on such appeal shall be final" shall be omitted;

(iv) in sub-clause (3A) of clause 16, the words namely:—

"and the order so passed shall be final and conclusive." shall be omitted.

[No. H. 11013/3/74-P&D-(ix)]
V. SANKARALINGAM, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1975

शुद्धिपत्र

(व्यापार पोत)

का०आ० 5265.—भारत के दिनांक 2 अगस्त, 1975 के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (2) के 2873 से 2875 तक के पृष्ठों पर प्रकाशित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना का० आ० सं० 2473, दिनांक 15 जुलाई, 1975 में:—

(1) पृष्ठ 2874 पर—

क्रम संख्या 15 में—चाय तथा/अथवा काफी (ग) के बाद "*" लगाये।

(2) शीर्षक "टैंकरों के लिये" ताजा दूध (समांगीकृत अथवा अल्पाधिक गर्म किया हुआ) के बाद "(ट)" रखें।

[एफ० सं० एम०एस०ई०(9)/75-एम०टी०]

दीवानचन्द अहीर, अवर सचिव

New Delhi, the 26th November, 1975

CORRIGENDUM

(Merchant Shipping)

S.O. 5265.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) S. O. No. 2473, dated the 15th July, 1975, published at pages 2873 to 2875 of the Gazette of India, Part II, secion 3, sub-section (ii), dated the 2nd August, 1975—

(1) at page 2875—

under serial No. 15-Tea & Coffee(h) insert "*" after (h)

(ii) under the heading "For Tankers" insert "(k)' after Fresh Milk (Homogenised or Ultra Heat treated Milk).

[F. No. MSE(9)/75-MT]

D. C. AHIR, Under Secy.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली 31, दिसम्बर, 1975

सार्वजनिक सूचना

का. आ. 5266.—केन्द्रीय सरकार दिल्ली डवलपमेंट एक्ट 1957 की धारा 2 ए(3) के अंतर्गत जोन डी-2 (माता सुन्दरी रोड क्षेत्र) के स्वीकृत जोनल डवलपमेंट प्लान में निम्नलिखित संशोधन करने का विचार कर रही है। इसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जा रहा है? इस संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे अपने आपत्ति/सुझाव इस ज्ञापन के 30 दिन के भीतर सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेज सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आपत्ति या सुझाव दें वे अपना नाम तथा पूरा पता भी लिखें।

संशोधन

(1) लगभग 0.646 हैं. (1.6 एकड़) का क्षेत्र जिसे जवाहर लाल नेहरु मार्ग में गिरधारी लाल अस्पताल के साथ के भूखण्ड में 'अस्पताल उपयोग,' के लिए दिखलाया गया है इसे अब 'पुलिस चौकी' के रूप में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(2) रणजीत सिंह रोड के पार रणजीत सिंह होटल के पूर्व में एक तिकोने क्षेत्र को क्षेत्रीय क्रीड़ास्थल एवं उद्यान के रूप में दिखलाया गया है, इसे अब 'अस्पताल उपयोग' (इर्विन अस्पताल) के विस्तार में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) माता सुन्दरी गुरूद्वारे के पूर्व में इस क्षेत्र को 'मौलाना आजाद मेडिकल कालेज' के लिए निर्दिष्ट किया गया है इसे अब 'सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान' (गालिब मेमोरियल हाल) में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(4) प्रस्तावित तानसेन मार्ग ब्रिज तथा वह सड़क जो रणजीत सिंह मार्ग के साथ मिलती है, इसे अब समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है तथा कालेज लेन ब्रिज के अतिरिक्त इसे राउज एवेन्यू लेन के साथ मिला देने का प्रस्ताव है।

(5) राउज एवेन्यू (दीन दयाल उपाध्याय मार्ग) तथा इस क्षेत्र की अन्य सड़कों के एलाइनमेंट में इस क्षेत्र के सरकुलेशन में सुधार करने के लिए पुनः समायोजन करने का प्रस्ताव किया गया है।

(6) 'सामान्य व्यवसाय उपयोग' के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र में से लगाग 2.424 हैं. (6 एकड़) के क्षेत्र को 'शैक्षिक उपयोग', '(दिल्ली कालेज)' में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(7) रणजीत सिंह होटल के निकट स्थानीय शापिंग क्षेत्र के दक्षिण में 24.4 मीटर (80 फीट) चौड़ी सड़क के एक भाग को बंद कर देने का प्रस्ताव है। इस प्रकार स्थानीय शापिंग क्षेत्र में बढ़े हुए क्षेत्र को 'सामुदायिक केन्द्र' के रूप में पुनः रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(8) उक्त पैरा (7) के अनुसार प्रस्तावित 'सामुदायिक केन्द्र' के दक्षिण में जो क्षेत्र है इसे अब 'शैक्षिक उपयोग' (हायर सेकेन्डरी स्कूल) में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(9) माता सुन्दरी गुरूद्वारा के दक्षिण में इस क्षेत्र को पुनः समायोजित करने के लिए 'शैक्षिक उपयोग' तथा क्षेत्रीय उद्यान (निकटवर्ती उद्यान) से आवासीय उपयोग में परिवर्तित किया जाय।

(10) रणजीत सिंह रोड के समानान्तर जाने वाली सड़क को बंद किए जाने के कारण आवासीय तथा क्षेत्रीय उद्धान क्षेत्रों में पुनः समायोजन किए जाने का प्रस्ताव है।

(11) अन्डरब्रिज जो कालेज लेन तथा राउज एवेन्यू लेन के साथ मिलता है, के प्रस्ताव के कारण आवासीय क्षेत्र में कमी हो गई है तथा संस्थानीय उपयोग सम्बन्धित क्षेत्रों को पुनः निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।

(12) कनाट सर्कस तथा राउज एवेन्यू के बीच रेलवे लाइन के उत्तर के क्षेत्र को आवासीय एवंम् क्षेत्रीय उद्धान के लिए निश्चित किया गया है। इसे अब हायर सैकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

(13) हायर सैकेन्डरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, स्थानीय शापिंग क्षेत्र तथा क्षेत्रीय उद्धान (निकटवर्ती उद्धान) की स्थितियों को समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(14) राउज ऐवन्यू के अलाइनमेंट को पुनः निर्धारित करने तथा मार्गाधिकार को 36.6 मीटर (120 फीट) से 24.4 मीटर (80) फीट तक कम करने का प्रस्ताव है।

(15) राउज ऐवन्यू के मार्गाधिकार में 24.4 मीटर (80 फीट) से 30.5 मीटर (100 फीट) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। कुछ 24.4 मीटर (80 फीट) चौड़ी अन्य सड़कें तथा मार्गाधिकार या तो बन्द किए जाने हैं या पुनः अलाइनमेंट तैयार किया जाना है।

(16) रामलीला ग्राउंड के निकट उपमार्ग को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है।

(17) राउज ऐवन्यू तथा बहादुरशाह जफर मार्ग के चौराहे पर एक कालेज की स्थिति समाप्त करने का प्रस्ताव है इस प्रकार जो क्षेत्र प्राप्त होगा इसे आवासीय एवं संस्थानीय उपयोग में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव है।

शनिवार को छोड़कर समस्त कार्यशील दिनों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यालय विकास भवन, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली में उक्त अवधि में आकर प्रस्तावित संशोधन के मानचित्र का निरीक्षण किया जा सकता है।

[सं. एफ. 16(168)/73-एम. पी.]

हृदय नाथ फोतेदार, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 13th December, 1975

PUBLIC NOTICE

S.O. 5266.—The following modifications, which the Central Government proposes to make to the approved zonal Development Plan for Zone D-2 (Mata Sundri Road area) under Section 11-A (3) of the Delhi Development Act, 1957, are hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modifications may send his objection or suggestion in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his name and full address.

MODIFICATIONS :

(1) An area measuring about 0.646 hectare (1.6 acres), shown for 'hospital use' adjacent to Girdhari Lal Hospital on Jawahar Lal Nehru Marg, is proposed to be changed for a 'Police Post'.

(2) A triangular area, on the east of Ranjit Singh Hotel, across Ranjit Singh Road, shown as zonal-playgrounds and parks, is proposed to be changed to 'Hospital Use' (for expansion of Irwin Hospital).

(3) The area, located east of Mata Sundri Gurdwara, earmarked for 'Maulana Azad Medical College', is proposed to be changed to 'social and cultural institution' (Galib Memorial Hall).

(4) The Tansen Mark Bridge and the road connecting this with Ranjit Singh Road, is proposed to be omitted and instead College Lane Bridge connecting it with Rouse Avenue Lane, is proposed.

(5) The alignments of Rouse Avenue (Deen Dayal Upadhayaya Marg) and some other roads of this zone are proposed to be readjusted to improve the circulation pattern of the area.

(6) An area measuring about 2.424 hectares (6 acres), out of the area earmarked for 'General Business Use', is proposed to be changed to "Educational Use" (for Delhi College).

(7) A portion of 24.4 metre (80 ft.) wide road, in the South of local shopping area near Ranjit Singh Hotel, is proposed to be closed. The local shopping area thus extended is proposed to be redesignated as a "Community Centre".

(8) The area further south of the proposed 'community centre', as in para (7) above, is proposed to be changed to "Educational Use" (higher secondary school).

(9) The area, south of Mata Sundri Gurdwara, is proposed to be readjusted, by changing the educational use and zonal parks (neighbourhood parks), to residential use.

(10) Readjustment of the residential and the zonal park areas, on account of closure of the road parallel to Ranjit Singh Road, is proposed.

(11) The reduction of residential area and relocation of institutional area, on account of the proposed underbridge connecting College Lane and Rouse Avenue Lane, is proposed.

(12) The area north of the Railway line in between Connaught Circus and Rouse Avenue for residential use and zonal park is proposed to be changed to higher secondary school.

(13) Location of higher secondary schools, primary schools, local shopping areas and zonal parks (neighbourhood parks) are proposed to be readjusted.

(14) The alignment of a portion of Rouse Avenue is proposed to be diverted and the right-of-way is proposed to be reduced from 36.6 metres (120 ft.) to 24.4 mts. (80 ft.).

(15) The right-of-way of Rouse Avenue Lane is proposed to be increased from 24.4 metres (80 ft.) to 30.5 metres (100 ft.). Some other roads of 24.4 metres (80 ft.) right-of-way are either proposed to be closed or realigned.

(16) The sub-way near Ramlila Ground is proposed to be omitted.

(17) The location of a college at the crossing of Rouse Avenue and Bahadurshah Zafar Marg is proposed to be dropped and the area thus available is to be changed to residential and institutional use.

The plan indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Authority, Delhi Vikas Bhavan, Indraprastha Estate, New Delhi, on all working days except Saturdays, within the period referred to above.

[No. F. 16(168)/73-MP]

H. N. FOTEDAR, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1975

का०आ० 5267.—अजमेर टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की वायत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक पब्लिक नोटिस उन सब की जानकारी के लिये जैसा कि भारतीय नियमावली 1951 के नियम 434 (3) (बी०बी०) में अपेक्षित है, अजमेर में प्रचलित समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 10 जनवरी, 75 को दैनिक समाचार पत्र "न्याय" और 11 जनवरी, 75 के "दैनिक समाचार पत्र" "दैनिक नवज्योति" और उसका अगला संशोधन 5 सितम्बर, 75 दैनिक समाचार पत्र "न्याय" में निकाला गया था।

उक्त नोटिस के उत्तर में जनसाधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव नहीं मिले हैं ।

अतः अब, उक्त नियमावली के नियम 434 (iii) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते महानिदेशक डाक-तार ने घोषित किया है कि 1-1-76 से अजमेर का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :—

अजमेर टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :

अजमेर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि अजमेर नगर पालिका के अन्तर्गत, पड़ता है । किन्तु वे टैलीफोन उपभोक्ता जो कि अजमेर नगर पालिका सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें अजमेर टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था के किसी भी एक्सचेंज से जब तक कि 5 कि० मी० दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्कदर से अदायगी करेंगे ।

[सं० 3-12/74-पी०एच०बी०]

DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 27th November, 1975

S.O. 5267.—Whereas a public notice for revising the local area of Ajmer Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Ajmer, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 10th January 1975 in daily newspaper 'Nyaya' and on 11th January 1975 in daily newspaper "Dainik Navjyoti"; and as further amended on 5th September 1975 in daily newspaper 'Nyaya';

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-1-1976 the revised local area of Ajmer shall be as under, Ajmer Telephone Exchange System.

The local area of Ajmer shall cover an area falling under the jurisdiction of Ajmer Municipality :

Provided that the telephone subscribers located outside Ajmer Municipality limit but who are served from Ajmer Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-12/74-PHB.]

का०आ० 5268.—मदुराई टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक पब्लिक नोटिस उन सब की जानकारी के लिये जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(iii) (बी०बी०) में अपेक्षित है मदुराई में प्रचलित समाचार पत्रों में निकाला गया था, और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 7-7-75 के दैनिक पत्र "इंडियन एक्सप्रैस" और 3-8-1975 के समाचार पत्र "मलाई मुरासु" में प्रकाशित कराया गया था।

उक्त नोटिस के उत्तर में प्राप्त जनसाधारण की आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है।

इसलिये अब उक्त नियमावली के नियम 434 (iii) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक डाक-तार ने घोषित किया है कि 1-1-76 से मदुराई का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :

मदुराई टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :—

मदुराई का स्थानीय क्षेत्र वही क्षेत्र होगा जो कि मदुराई नगर निगम के अन्तर्गत पड़ता है । किन्तु वे टैलीफोन उपभोक्ता जो कि मदुराई नगर निगम की सीमा के बाहर स्थित हैं किन्तु जिन्हें मदुराई टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था से सेवा प्रदान होती है वे इस व्यवस्था की किसी भी एक्सचेंज से जब तक 5 कि०मी० दूरी के भीतर स्थित रहेंगे और इस व्यवस्था से जुड़े रहेंगे तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करेंगे ।

[सं० 3-13/74-पी० एच०बी०]

S.O. 5268.—Whereas a public notice for revising the local area of Madurai Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Madurai, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 7th July 1975 in daily newspaper "Indian Express" and on 3rd August 1975 in newspaper "Malai Murasu";

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-1-76 the revised local area of Madurai shall be as under;

Madurai Telephone Exchange System.

The local area of Madurai shall cover an area falling under the jurisdiction of Madurai Municipal Corporation;

Provided that the telephone subscribers located outside Madurai Municipal Corporation limit but who are served from Madurai Telephone Exchange System shall continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 Kms of any exchange of this system and remain connected to it.

[No. 3-13/74-PHB]

का० आ० 5269.—तिरूनगर टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था के स्थानीय क्षेत्र में बदली किये जाने की बाबत जिन लोगों पर इस परिवर्तन का प्रभाव पड़ने की संभावना है एक पब्लिक नोटिस उन सब की जानकारी के लिये जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(iii) (बी०बी०) में अपेक्षित है तिरूनगर में प्रचलित समाचार पत्रों में निकाला गया था और उनसे कहा गया था कि इस बारे में यदि

उन्हें कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे नोटिस के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजने का कष्ट करें।

उक्त नोटिस सर्वसाधारण की जानकारी के लिये 7 जुलाई, 1975 के दैनिक पत्र को "इंडियन एक्सप्रेस" और 3 अगस्त, 1975 के समाचार "मलाई मुरासु" पत्र में निकाला गया था।

उक्त नोटिस के उत्तर में प्राप्त जन-साधारण से मिली आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 434(iii) (बी०बी०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके महानिदेशक डाक-तार ने घोषित किया है कि 1-1-76 से तिरूनगर का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :--

तिरूनगर टैलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था :--

तिरूनगर का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो कि तिरूनगर टैलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० की दूरी के भीतर पड़ता है ।

किन्तु यह सीमा मदुराई टैलीफोन एक्सचेंज से या मदुराई नगर निगम सीमा से 5 कि०मी० की अरीय दूरी जो भी मदुराई और तिरूनगर टैलीफोन एक्सचेंज के बीच तिरूनगर टैलीफोन एक्सचेंज के समीपस्थ हो तक प्रतिबंधित होगी।

[सं० 3-13/74-पी०एच०बी०]

एच० सी० माथुर, निदेशक फोन (ई)

S.O. 5269.—Whereas a public notice for revising the local area of Tirunagar Telephone Exchange System was published as required by rule 434 (III) (bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Tirunagar, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publicaton of the notice in the Newspapers;

And whereas the said notice was made available to the public on 7th July 1975 in daily newspaper "Indian Express" and on 3rd August 1975 in newspaper "Malai Murasu";

And whereas objections and suggestions received from the public on the said notice have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434 (III) (bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 1-1-76 the revised local area of Tirunagar shall be as under;

Tirunagar Telephone Exchange System:

The local area of Tirunagar shall cover an area falling within 5 Kms. radial distance from the Tirunagar Telephone Exchange:

Provided that this limit shall be restricted to the line of 5 Kms. radial distance from Madurai Telephone Exchange or Madurai Municipal Corporation boundary whichever nearer to Tirunagar Telephone Exchange between Madurai and Tirunagar Telephone Exchange Systems.

[No. 3-13/74-PHB]

H. C. MATHUR, Director of Telephones (E)

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1975

का०आ० 5270.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में मैसर्स भारत कोकिंग, कोल लिमिटेड की लोयाबाद कोलियरी डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र से सम्बन्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण संख्या 2, धनबाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की लोयाबाद कोलियरी, डाकघर बांसजोरा, जिला धनबाद के प्रबन्धतन्त्र का सर्वश्री (1) कैलाश प्रसाद, खनन सीरदार, (2) फौदार सिंह, लैम्प इस्यू क्लर्क, (3) हरिहर भार, खनिक और (4) भाजु पाशी, खनिक को 7 नवम्बर, 1973 से सेवा से पदच्युत करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?

[संख्या एल०-20012/117/75-डी० 3 (ए०)]

एल० के० नारायणन, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 25th September, 1975

S.O. 5270.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bansjora, District Dhanbad, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby refers the said dispute for adjudication to the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, constituted under 7A of the said Act.

SCHEDULE

Whether the management of Loyabad Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited. Post Office Bansjora, District Dhanbad, is justified in dismissing from service, Sarvashri (1) Kailash Prasad, Mining Sirdar, (2) Foudar Singh, Lamp Issue Clerk, (3) Harihar Bhar, Miner and (4) Bhaju Pashi, Miner, with effect from the 7th November, 1973? If not, to what relief are the said workmen entitled?

[No. L-20012/117/75-D.III.A]

L. K. NARAYANAN, Section Officer (Spl.)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1975

का०आ० 5271.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चरखी दादरी, के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और यतः केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निदेशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री मोहन लाल जैन होंगे, जिनका मुख्यालय फरीदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है।

अनुसूची

क्या मैसर्स डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड, चरखी दादरी को श्री सूबे सिंह, लिपिक की परिवीक्षा को समय-समय पर बढ़ाने और 11 फरवरी, 1975 से उसकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई सद्भावपूर्ण न्यायोचित तथा वैध है ? यदि नहीं, तो उक्त, कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[संख्या एल०-29011/101/75 डी०3बी०]

ORDER

New Delhi, the 21st October, 1975

S.O. 5271.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri, and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal with Shri Mohan Lal Jain as Presiding Officer with headquarters at Faridabad and refers the said dispute for adjudication to the said Industrial Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of Messrs Dalmia Dadri Cement Limited, Charkhi Dadri in extending the probation of Shri Sube Singh, Clerk from time to time and in terminating services with effect from the 11th February, 1975 is bona fide justified and legal ? If not, to what relief is the said workman entitled ?

[No. L-29011/101/75-D. III. B]

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1975

शुद्धि-पत्र

का०आ० 5272.—भारत के तारीख 30 अगस्त, 1975 के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) के पृष्ठ 3167 पर प्रकाशित श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 2829 तारीख 23 जुलाई, 1975 में अनुसूची में "राम बरारी" के लिये "राम बराई" पढ़िए।

[संख्या एल०-19012/19/74-एल०आर० 2-डी०ओ०-3बी]

एस० एच० एस० अय्यर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

New Delhi, the 22nd October, 1975

CORRIGENDUM

S.O. 5272.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2829 dated the 23rd July, 1975 published on page 3167 of the Gazette of India, part II, Section 3, Sub Section (ii), dated the 30th August, 1975, in the Schedule, for "Ram Barari" read "Ram Barai".

[No. L 19012/19/74-LR 2/D.O.-3B]

S. H. S. IYER, Section Officer (Spl.)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1975

का०आ० 5273.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स सिंह हिन्दुस्तान मैरिन (प्राइवेट) लिमिटेड, 2, देवी चौधरी रोड, कलकत्ता-23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1975 की जनवरी के इकतीसवें दिन को प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

[सं० एस०-35019(14)/75-पी०एफ०-2]

New Delhi, the 19th November, 1975

S.O. 5273.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Singh Hindustan Marine (Private) Limited, 2 Devi Chowdhury Road, Calcutta-23 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of January, 1975.

[No. S. 35017(14)/75-PF. II.]

का०आ० 5274.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, 7-बी सर्वोदय नगर, कानपुर जिसके अंतर्गत टांडा, जलालपुर, बाराबंकी और अकबरपुर स्थित इसके स्टेपल यार्न डिपो भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना कानपुर स्थित स्थापन की बाबत जिसके अंतर्गत टांडा, जलालपुर और बाराबंकी स्थित इसके स्टेपल यार्न डिपो हैं। एक अप्रैल, 1972 से और स्टेपल यार्न डिपो अकबरपुर की बाबत 1 जून, 1972 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35019(54)/73 पी० एफ० 2]

राम प्रसाद भरुला, अवर सचिव,

S.O. 5274.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Uttar Pradesh State Ttextile Corporation Limited, 7-B, Sarvodayanagar, Kanpur, including its Staple Yarn Depots at Tanda, Jabalpur, Barabanki and Akbarpur have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provision of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1972 in respect of the establishment at Kanpur including its Staple yarn Depots at Tanda, Jabalpur and Barabanki and on the first day of June, 1972 in respect of the Staple yarn Depot at Akbarpur.

[No. S. 35019(54)/73-PF. II]

R. P. NARULA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1975

का० आ० 5275 यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स दीपक लेबोरेटरी, सी० 5, इण्डस्ट्रिएल एस्टेट, बेरहामपुर, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1973 के अगस्त् के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस० 35019(158)/75-पी०एफ० II(i)]

New Delhi, the 20th November, 1975

S.O. 5275.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Dipak Laboratories, C-5, Industrial Estate, Berhampur have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of August, 1973.

[No. S. 35019(158)/75-PF.II(i)]

का० आ०-5276 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि, अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अगस्त्, 1975 से मैसर्स दीपक लेबोरेटरी, सी०-5, इण्डस्ट्रिएल एस्टेट, बेरहामपुर, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं०एस०-35019(158)/75-पी०एफ2 (ii)]

एस० एस० सहस्रानामन, उप-सचिव

S.O. 5276.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952) the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of August, 1973, the establishment known as Messrs Dipak Laboratories, C-5, Industrial Estate, Berhampur for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35019(158)/75-PF. II(ii)]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 24th November, 1975

S.O. 5277.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hutti Gold Mines Company Limited and their workman Shri Suresh Babu, which was received by the Central Government on the 24th November, 1975.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL) AT HYDERABAD.

Industrial Dispute No. 22 of 1975.

BETWEEN

Suresh Babu ... Petitioner.

AND

The Management of Hutti Gold Mines, Hutti ... Respondent

APPEARANCES :

(1) Sri K. Srinivasamurthy, Advocate—for Management.

(2) Sri A. Lakshmana Rao, Advocate—for Workman.

AWARD

The Government of India in Ministry of Labour through notification L-29012/27/74-LR-IV-D-IV(B) dated 13th June, 1975 referred the Industrial Dispute between the employers in relation to the Management of Hutti Gold Mines Company Limited, and their Workmen under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Dispute Act for adjudication by this Tribunal on the following issue.

> "Whether the action of the Management of Hutti Gold Mines Company Limited, Hutti Post Office (Raichur District) was justified in terminating the services of Sri Suresh Babu, the Security inspector of the Company with effect from the 18th December, 1973? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The reference was registered as I.D. 22 of 1975 and notices were directed to the workman and to the Management. The claimant workman in his claim statement inter alia alleged that he was appointed as Security Inspector on 26th May, 1971 in the scale of Rs. 170-10-260 per month plus Rs. 56 D.A. and that at the time of his illegal termination he was drawing in all Rs. 264 per month. After the successful completion of his probationary period the Respondent Company confirmed his services on 9th June, 1972. Since the date of his appointment and up to the date of the illegal order of termination, he was performing his duties to the entire satisfaction of his superiors, as the Claimant was an Ex-Naval Service personnel. It is however alleged that at the instance and instigation of some of co-workers of the claimant, the Security Officer started harassing the claimant, and in pursuance of this plan a notice was issued to the claimant by

the Security Officer on 29th November, 1973. Without holding any enquiry and without giving opportunity to the claimant, his services were illegally terminated on 18th December, 1973. It is alleged that the Security Officer himself made a complaint before the higher officials of the Respondent Company and the same Security Officer got appointed himself as the enquiry Officer to conduct the enquiry against the claimant. Thus the enquiry officer is said to be biased and prejudiced against the claimant. Even before the enquiry was completed the services of the claimant are said to have been terminated. During the course of enquiry the claimant made a request to the said Enquiry Officer on 11th November, 1973 for appointment of any other Officer as the Enquiry Officer so as to ensure a fair and proper enquiry. Immediately there after, the claimant was kept under suspension from 12th December, 1973 and ultimately, his services were terminated on 18th December, 1973 even before the enquiry was completed. On account of the illegal termination, the claimant is said to have been put to much financial loss.

3. In the Counter filed by the Management it is contended that the reference by the Central Government is bad as there was said to be no Industrial Dispute in as much as no demand was made by the workman for reinstatement nor the management denied the same. The rejection of the reference on this ground was said to be agitated as a preliminary issue. The confirmation of the petitioner on 9th June, 1972 is admitted. It is however alleged that the claimant-petitioner was warned of acts of misconduct on a number of occasions. It is contended that the claimant did not work to the satisfaction of his superiors and his annual increment was stopped in 1973 as a measure of punishment for unsatisfactory work. The claimant is said to have been charge-sheeted by the Security Officer on 29-11-1973 for damaging Teel-Tale Clock and for disobedience of instructions in that regard. To this the claimant is said to have given his explanation denying the charges and the management initiated an enquiry. As per the request of the claimant, the assistance of a co-employee is said to have been permitted to him during the enquiry proceedings. On 5-12-1973 the claimant filed a letter asking for Welfare Officer or any Kannada knowing officer to be present during the enquiry to safeguard his interest. This request was also conceded by the Management. Later on the claimant asked for a change in the Enquiry Officer. It is however alleged that the Management did not proceed further with the enquiry but as the Management lost its confidence, it terminated the services of the petitioner in terms of the conditions of employment. It is contended that the Management has a right to terminate the services of this employee by giving one month's notice or pay in lieu there of. It is denied that the claimant was dismissed from service on the basis of enquiry for misconduct or that he was dismissed with reference to the subject of the charge sheet. The termination is said to have been not imposed as a measure of punishment. It is contended whether the enquiry was proper or whether the charges mentioned in the charge sheet are proved or not are mere questions of academic nature, as it is a case of discharge simpliciter. The claim of the workman for the back wages is said to be untenable. It is contended that the claimant-workman has been working in another establishment after the termination of his services and therefore he is not entitled to any back wages.

4. In support of his case, the workman examined himself as W.W. 1 and Exs. W1 to W24 were marked. For the Management Exs. M1 to M8 were marked. At the stage of rebuttal evidence the parties reported a settlement. That settlement was also recorded by way of abundant caution on ascertaining its terms from the parties that were present. As per this settlement the claimant was paid a sum of Rs. 6,000 under Demand Draft dated 11-10-1975 towards the final settlement of his claim including the claim for reinstatement and back wages. The parties also prayed for an award being passed in terms of his compromise.

5. The only point that falls for consideration is whether the settlement is just and fair. It is in the evidence of W.W.1, the claimant that from August 1974, he has been working as Security Incharge in M. S. K. Mills, Gulbarga and that he is drawing a sum of Rs. 350 per month. It is however alleged by him that this appointment is a temporary one. It can be seen that the present emoluments of the claimant are higher than what he was drawing in the Respondent Company. Having regard to this fact the payment of Rs. 6,000 as compensation for the illegal termination appears to be only reasonable. There is nothing to show that the settlement is the out-come of any compulsion upon the claimant. In the circumstances the settlement appears to be fair and reasonable, and this can be made the base of an Award.

6. The claimant however asked for the issue of a service certificate by the maangement without casting any stigma upon him. This request was made by the claimant when the settlement was being recorded. Note of it is accordingly made on the Dock Sheet dated 16-10-1975. Since it is the very case of the Management that the order is one of termination simplicitor, there may not be any impediment in issuing a service certificate without casting any stigma. It can also be noted that under the standing orders, the Management is bound to issue a certificate of service. In this view also there will be a direction to the management for the issue of a service certificate.

7. Award passed accordingly in terms of the settlement and with a direction to the management for the issue of a Service Certificate to the Claimant without a stigma.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 17th day of October, 1975.

SRI T. NARASING RAO, Presiding Officer,
Industrial Tribunal

[No. L-29012(27)/74-LR. IV/D-IV(B)]

New Delhi, the 25th November, 1975

S.O. 5278.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the Chairman, Madras Stevedores Association, North Beach Road, Madras-1 and their workmen, which was received by the Central Government on the 22nd November, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal, Madras.
(Constituted by the Central Government)
Thursday, the 6th day of November, 1975
Industrial Dispute No. 26 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of Madras Stevedores Association, Madras-1).

BETWEEN

The workmen represented by

The President,

Tamilnadu Port and Dock Workers' Welfare Association,

No. 123/124/, Moore Street, Madras-1.

AND

The Chairman, Madras Stevedores' Association, MDLB Buildings, North Beach Road, Madras-1.

REFERENCE :

Order No. L-33012/1/74-P&D/CMT/DIV(A), dated 21st March, 1975 of the Ministry of Labour, Government of India.

This dispute coming on for final hearing on Tuesday the 21st day of October, 1975 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal N. T. Vanamamalai and R. Ganesan, Advocates for Thiru M. Munishami, Advocate appearing for the workmen and of

Thiru A. S. Raman, Advocate for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following award.

AWARD

The Government of India by its order No. L-33012/1/74-P&D/CMT/DIV(A), dated 21-3-1975 of the Ministry of Labour, Government of India have referred to this Tribunal an industrial dispute between the employees and the Management of Madras Stevedores Association, Madras for adjudication by this Tribunal.

2. The issue is as follows :—

"Whether the Chairman, Madras Stevedores Association was justified in terminating the services of Shri K. Mathiah, General Secretary of Tamil Nadu Port and Dock Workers Welfare Association with effect from the 25th February, 1974. If not, to what relief is he entitled and from what date?"

3. The President of Tamil Nadu Port and Dock Workers Welfare Association has filed a claim statement alleging that his termination from the service of the Madras Stevedores' Association is illegal and this is a clear case of vicitimisation for trade union activities and hence the order of termination has to be set aside.

4. The Association has filed a counter statement contending that the Union purporting to represent the workmen has no representative character to espouse the cause of the individual workman and this reference being one under Section 10(1)(b) of the Industrial Disputes Act, 1947 will not constitute a valid industrial dispute. It is also contended that there was no direct demand either by the workmen individually or through the Union on the Management asking for reinstatement before the dispute was raised before the Regional Labour Commissioner. On merits, the Union has raised several contentions alleging that the discharge is one of simplicitor on the ground of loss of confidence.

5. On behalf of Management, Misc. Appln. No. 110 of 1975 was filed requesting this Tribunal to dispose of a preliminary objection before deciding the case on merits. The preliminary objection is that no demand was made on the management prior to the reference for the reinstatement of the worker Thiru K. Muthiah and hence it has to be held that there was no industrial dispute. The second ground of objection is that no resolution was passed authorising it to raise the dispute and so it should be held that there is no industrial dispute.

6. I will now take up the first point, namely, whether there was any direct demand either by the individual workman or through his Union on the employer prior to the reference. Thiru K. Muthiah, W.W. 1 deposed before me that after the termination of his services, the President of the Union demanded twice for taking him in service and had talks with the Management and that the demand was only oral. His further evidence is that before the Regional Labour Commissioner also they demanded reinstatement and in both in Ex. M-84 and Ex. W-25, there is no reference to the termination. Ex. M-86 is the Conciliation failure report. The learned counsel for the management cited a ruling reported in 1968—I—L.L.J—page 434 (Sindhu Resettlement Corporation Ltd., Vs. Industrial Tribunal, Gujarat, and others) in support of the contention that demand by the workmen must be raised first on the management and rejected by them before industrial dispute can be said to arise and exists. The case, namely, that the demand was only oral has been purposely made to get over the failure of the demand that should have been actually made on the employer before the reference. If really, there had been any demand on the employer, the workmen who claims to have the support of the Union would not have failed to make the demand on the employer in writing. So I do not believe the case that there was an oral demand for reinstatement by the President of the Union.

7. The learned counsel for the union put forward an alternative argument, namely, that there was demand before the Conciliation Officer and it would clearly show that an industrial dispute existed. In the above decision, their Lordships at page 839 have observed as follows :

"If no dispute at all was raised by the respondents with the management, any request sent by them to the Government would only be a demand by them and not an industrial dispute between them and their employer. An industrial dispute, as defined, must be a dispute between employers and employers, employers and workmen and workmen and workmen. A mere demand to a Government, without a dispute being raised by the workmen with their employer, cannot become an industrial dispute."

In the ruling reported in 37 F. J. R. page 69, their Lordships of the Delhi High Court have laid down what is meant by Industrial Disputes and also its essentials. Their Lordships have observed at page 78 as follows :—

"The Supreme Court has also clarified that even if the Conciliation Officer found that an industrial dispute existed and so reported to the Government, this could not be regarded as the existence of the industrial dispute which has to be founded upon a demand by the workmen on the employers. If this is the ratio of the Supreme Court decision, it cannot be said that an industrial dispute existed in the present case as no demand was made by respondent No. 3 on the petitioner-company before he made an application under section 10(2) for reference. In the event the fact that the demand of respondent No. 3 was forwarded by the Conciliation Officer to the petitioner-company and was not accepted by the latter would not constitute an industrial dispute."

In view of these observation, the workman cannot contend that there was sufficient demand before the Conciliation Officer about the termination of his services.

8. The next point that was urged on behalf of the management was that no resolution of the Union was passed authorising it to espouse the cause of the workman. In support of the contention the counsel for the Management cited a ruling reported in 1965—I—L.L.J. page 95 (Nellai Cotton Mills, Tirunelveli Vs. Labour Court, Madurai and another). The learned counsel for the management relied on the observations at page 96, as follows:

"Learned counsel for the petitioner thereafter urged before me the further ground that the dispute was only an individual dispute and not a collective one. He relied, for this purpose, on the views expressed by the Supreme Court in Bombay Union of Journalists and other v. Hindu (1961-II-L.L.J. 436) which was followed by Veeraswami J. in Vianlakshi Mills v. Labour Court and another (1962—II—L.L.J. 93). The gist of these decisions is that before a dispute can become a collective dispute, it should not merely be sponsored by a union which has got a substantial number of the employees of the particular concern on its rolls, but it is also necessary that a substantial number of the employees of the concern, should have supported the decision of the union to take up the cause of the individual worker. In the absence of these circumstances, the dispute sponsored by the union cannot be considered to be a collective dispute. I give the following extract from the head not in Visalakshi Mills, Vs. Labour Court and another (1962—II—L.L.J.—93) (Vide supra)".

"From the mere fact that a general union, at whose instance an industrial dispute concerning an individual workman is referred for adjudication, has on its rolls a few of the workmen in the establishment as its members, it could not be assumed the individual dispute was converted into a collective dispute. In such a case not only should it be proved that the workmen who are members of the general union formed a substantial or considerable section of the workmen of the particular mills, but also that in order to vest the dispute with the character of an industrial dispute those members participated in or acted together and arrived at an understanding, either by a resolution or by other means, and collectively supported on the date of the reference the demand or the cause of an individual dispute."

The Union was not able to produce any resolution passed at the general body meeting or at any other meeting authorising it to espouse the cause of the workmen. The above decision shows that before a dispute can become a collective dispute, it should not merely be sponsored by the Union which has got a substantial number of employees of the Particular concern on its roll, but it is also necessary that a substantial number of the employes of the concern should have supported the decision of the Union to take up the cause of the individual worker. No materials were placed before this Tribunal to show that as a matter of fact, any resolution was passed by the Union authorising it to espouse the cause of the workmen. Following the principle laid down in the above ruling, I come to the conclusion that the Union had no authority to espouse the cause of the workmen. In view of my discussion above I find this point against the claimant.

9. In the result, the preliminary objections are upheld. An award is passed holding that the reference is incompetent.

Dated, this 6th day of November, 1975.

T. PALANIAPPAN

Presiding Officer

WITNESSES EXAMINED

For workmen

W.W.1—Thiru K. Muthiah.

For management.—Nil

DOCUMENTS MARKED

For workmen

Ex. W—1/23-8-71—Temporary pass to enter Madras Harbour issued to W.W. 1.

Ex. W—2/28-8-71—Letter from W.W.1 to the Management about the enquiry.

Ex. W—3/6-9-71—Reply by W.W.1 to the charge sheet.

T.P. SUBRAHMANYAN, Under Secy.

Ex.W-4/18-9-71 — Letter from W.W. 1 to the Management about the enquiry.

Ex.W-5/8-11-71 — Medical fitness certificate issued to W.W. 1.

Ex.W-6/12-11-75 — Sick leave certificate issued to W.W. 1.

Ex.W-7/19-11-71 — Memo issued to W.W. 1 directing to submit his explanation for his unlawful entry into harbour premises.

Ex.W-8/30-11-71 — Reply by W.W. 1 to Ex. W-7.

Ex.W-9/1-12-71 — Medical fitness certificate issued to W.W. 1.

Ex.W-10/2-12-71 — Letter by W.W. 1 to the Government General Hospital, Madras for collecting medical examination fees from the employer.

Ex.W-11/8-1-72 — Letter from W.W. 1 to the Dean, Government General Hospital, Madras regarding medical examination by the medical Board.

Ex.W-12/29-9-72 — Sick leave certificate issued to W.W. 1.

Ex.W-13/4-10-72 — Letter by W.W. 1 to the enquiry officer for postponement of enquiry.

Ex. W-14/4-10-72 — Letter by W.W. 1 to the Management for postponement of enquiry.

Ex. W-15/4-10-72 — Letter from W.W. 1 to the Medical Officer of the Management enclosing medical certificate.

Ex. W-16/27-10-72 — Letter from W.W. 1 to the Dean, Government General Hospital, Madras regarding medical examination by the Medical Board.

Ex. W-17/14-11-72 — Letter from W.W. 1 to the Dean, Government General Hospital, Madras regarding medical examination by the Medical Board.

Ex. W-18/14-11-72 — Medical certificate issued to W.W. 1.

Ex. W-19/24-11-72 — Letter from W.W. 1 to the Medical Officer of the Management stating to enclose Ex. W-18.

Ex. W-20/1-12-72 — Letter from W.W. 1 to the Government General Hospital, Madras regarding medical examination by the Medical Board.

Ex. W-21/1-12-73 — Letter from W.W. 1 to the enquiry officer requesting to revise the ex-parte decision.

Ex. W-22/13-12-73 — Letter from W.W. 1 to the Chairman of the Management requesting to change the enquiry officer.

Ex. W-23/18-12-73 — Letter from W.W. 1 to the enquiry officer seeking clarifications about the enquiry.

Ex. W-24/27-12-73 — Letter from W.W. 1 requesting to postpone the enquiry.

Ex. W-25/5-4-74 — Reply from the union to the Management's letter dated 25-3-74 addressed to the Regional Labour Commissioner, Madras.

Ex. W-26/8-11-71 — Fitness certificate issued to W.W. 1.

Ex. W-27/1-12-71 — Fitness certificate issued to W.W. 1.

Ex. W-28/2-12-71 — Copy of Ex. W-10.

Ex. W-29/26-6-72 — Enquiry Proceedings conducted on 26-6-72.

Ex. W-30/22-9-72 — Memo issued to W.W. 1 informing the change of enquiry officer.

Ex. W-31/22-9-72 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting information about the enquiry.

Ex. W-32/29-9-72 — Enquiry proceedings conducted on 29-9-72.

Ex. W-33/5-10-72 — Enquiry proceedings conducted on 5-10-72.

Ex. W-34/30-12-72 — Medical certificate issued to W.W. 1 (copy).

Ex. W-35/4-10-72 — Letter from W.W. 1 to the Medical Officer of the Management stating to enclose a medical certificate.

Ex. W-36/4-10-72 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting to postpone the enquiry as he is sick.

Ex. W-37/19-1-73 — Letter from W.W. 1 to the Medical Officer of the Management stating to enclose a medical certificate.

Ex. W-38/5-7-73 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting to intimate to him the date of enquiry.

Ex. W-39/27-7-73 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting to intimate the date of enquiry.

Ex. W-40/6-8-73 — Conciliation failure report.

Ex. W-41/13-11-73 — Memorandum of settlement u/s. 12(3) of the I.D. Act, 1947 between parties (copy).

Ex. W-42/15-11-73 — Letter from the Regional Labour Commissioner (C), Madras to the parties cancelling the Concillation on 16-11-73 (copy).

Ex. W-43/22-11-73 — Letter from the Management to W.W. 1 informing the change of enquiry officer and intimating the date of enquiry.

Ex. W-44/28-11-73 — Letter from W.W. 1 to the enquiry officer requesting to fix the enquiry time at 3.00 P.M.

Ex. W-45/30-11-73 — Letter from the union to the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras regarding verification of Union's record.

Ex. W-46/28-11-73 — Wage slip for the month of November, 1973 of W.W. 1.

Ex. W-47/6-12-73 Letter from the Enquiry Officer to W.W. 1 reopening the enquiry and posting the enquiry on 12-12-1973.

Ex. W-48/12-12-73 — Memorandum of settlement u/s. 12(3) of the I.D. Act, 1947 between parties (copy).

Ex. W-49/11-1-74 — Enquiry Proceedings conducted on 11-1-74.

Ex. W-50/11-1-74 — Letter from the Medical Officer of the Management to the Stanley Hospital sending W.W. 1 for treatment.

Ex. W-51/31-1-74 — Letter from W.W. 1 to the Management for grant of P.F. loan for Rs. 1000/-.

Ex. W-52/3-7-74 — Letter from W.W. 1 requesting for subsistance allowance.

Ex. W-53/14-7-75 — Award in I.D. No. 9/75 of the Industrial Tribunal, Madras.

For Management

Ex. W-1/21-8-71 — Suspension order issued to W.W. 1.

Ex. M-2 — Report of Thiru M. Nevi's against W.W. 1.

Ex. M-3 — Report of Thiru M. Nevi's against W.W. 1.

Ex. M-4 — Report of Thiru N. Ramalingam against W.W. 1.

Ex. M-5 — Report of Thiru E.V. Rao against W.W. 1.

Ex. M-6/23-8-71 — Report signed by Staff members against W.W. 1.

Ex. M-7/23-8-71 — Report of Thiru G.B. Chinnikrishnan against W.W. 1.

Ex. M-8/26-8-71 — Enquiry notice issued to W.W. 1.

Ex. M-9/28-8-71 — Reply by W.W. 1 to Ex. M-8.

Ex. M-10/31-8-71 — Report by Staff members against W.W. 1.

Ex. M-11/2-9-71 — Charge memo issued to W.W. 1.

Ex. M-12/6-9-71 — Reply by W.W. 1 to Ex. M-11.

Ex. M-13/17-9-71 — Enquiry notice issued to W.W. 1.

Ex. M-14/18-9-71 — Letter from W.W. 1 to the Management regarding enquiry.

Ex. M-15/25-9-71 — Memo issued to W.W. 1 informing the appointment of Enquiry Officer.

Ex. M-16/25-9-71 — Enquiry notice issued by the Enquiry Officer.

Ex. M-17/28-10-71 — Enquiry notice issued by the Enquiry Officer.

Ex. M-18/30-10-71 — Letter from W.W. 1 to the Enquiry Officer about the fixation of date of enquiry.

Ex. M-19/1-11-71 — Letter from W.W. 1 to the Enquiry Officer informing that he was placed on sick list.

Ex. M-20/13-11-71 — Letter from W.W. 1 to the Enquiry Officer for postponement of enquiry.

Ex. M-21/13-11-71 — Letter from the enquiry officer to the Management regarding enquiry.

Ex. M-22/29-11-71 — Letter from the Government General Hospital Madras to W.W. 1 requesting him to appear before the Medical Board.

Ex. M-23/30-11-71 — Enquiry notice issued to W.W. 1.

Ex. M 24/2-12-71 — Similar to Es. W 10.

Ex. M-25/6-12-71 — Letter from W.W. 1 to the Enquiry Officer for postponement of enquiry.

Ex. M-26/6-12-71 — Letter from the enquiry officer to W.W. 1 informing the date of enquiry.

Ex. M-27/6-12-71 — Letter from the Government General Hospital, Madras to the Management regarding the collection of medical examination fees.

Ex. M-28/8-12-71 — Reply letter from the Management to Ex. M-27.

Ex. M-29/8-12-71 — Memo issued by the Management advising W.W. 1 to appear before Dean, Government General Hospital, Madras.

Ex. M-30/13-12-71 — Memo from the Government General Hospital, Madras asking W.W. 1 to appear before the Medical Board.

Ex. M-31/17-12-71 — Letter from the Management to the Hospital regarding the medical examination of W.W. 1 by the Medical Board.

Ex. M-32/18-12-71 — Letter from W.W. 1 to the enquiry officer about the conduct of enquiry.

Ex. M-33/23-12-71 — Memo advising W.W. 1 to collect the true copy.

Ex. M-34/24-12-71 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting to furnish copies of complaints and list of witnesses to be examined.

Ex. M-35/13-1-72 — Enquiry notice issued to W.W. 1.

Ex. M-36/29 11-71 — Copy of W.P. No. 3635/71 and High Court's notice.

Ex. M-37/15-2-72 — Letter from W.W. 1 to the enquiry officer requesting to postpone the enquiry till the disposal of Writ Petition by the High Court.

Ex. M 38/22-2-72 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting to supply a copy of appointment order appointing the enquiry officer.

Ex. M 39/24-2-72 — Letter from the advocate of W.W. 1 to the enquiry officer for postponement of enquiry.

Ex. M-40/28-3-72 — Letter from the Management to W.W. 1 fixing enquiry on 30-3-72.

Ex. M-41/17-4-72 — Letter from the Management to W.W. 1 fixing enquiry on 18-4-72.

Ex. M-42/2-5-72 — Letter from the Management to W.W. 1 fixing enquiry on 4-5-72.

Ex. M-43/6-5-72 — Report of the Accountant of the Management against W.W. 1.

Ex. M-44/8-5-72 — Letter from Thiru M. Krishna Rao, Accountant stating that is he not willing to continue as Managements' representative.

Ex. M-45/13-5-72 — Memo directing W.W. 1 to give explanation about his disorderly behaviour towards Thiru M. Krishna Rao.

Ex. M-46/13-5-72 — Reply by W.W. 1 to Ex. M-45.

Ex. M-47/14-6-72 — Enquiry intimation sent to W.W. 1.

Ex. M-48/26-6-72 — Original of Ex. W-29.

Ex. M-49/21-8-71 — Order appointing Thiru K. Ranganathan. Advocate as enquiry officer.

Ex. M-50/18-9-72 — Enquiry intimation issued to W.W. 1.

Ex. M-51/22-9-72 — Enquiry intimation issued to W.W. 1.

Ex. M-52/22-9-72 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting information about the enquiry.

Ex. M-53/22-9-72 — Reply letter from the Management to Ex. M-52.

Ex. M-54/29-9-72 — Letter from the advocate of W.W. 1 stating that the enquiry may be kept pending further orders by the High Court.

Ex. M-55/10-11-72 — Memo sent by the Government General Hospital, Madras directing W.W. 1 to appear before the Medical Board.

Ex. M-56/3-10-72 — Enquiry notice issued to W.W. 1.

Ex. M-57/4-10-72 — Letter from W.W. 1 to the Management enclosing medical certificate.

Ex. M-58/27-10-72 — Letter from W.W. 1 to the Dean, Government General Hospital, Madras regarding medical examination by the Medical Board.

Ex. M-59/27-10-72 — Letter from the Union to the Dean, Madras General Hospital, Madras-3 regarding medical examination by the Medical Board.

Ex. M-60/18-11-72 — Letter from Thiru C. Velanganni informing that W.W. 1 was not turned for the Medical examination.

Ex. M-61/22-11-72 — Memo from the Government General Hospitals, Madras asking W.W. 1 to appear before the Medical, Board.

Ex. M-62/2-12-72 — Letter from Thiru C. Velanganni to the Management informing that W.W. 1 did not appear before the Medical Board.

Ex. M-63/5-12-72 — Letter from the Government General Hospital, Madras-3 to the Management regarding medical examination of W.W. 1 by the Medical Board.

Ex. M-64/27-7-73 — Letter from W.W. 1 to the Management requesting to inform the date of enquiry.

Ex. M-65/10-10-73 — Letter from the Enquiry Officer to the Management stating his inability to continue the enquiry.

Ex. M-66/3-12-73 — Letter from the Union to the Management, the Regional Labour Commissioner (Central) and the Assistant Labour Commissioner (Central), Madras regarding the conduct of the enquiry.

Ex. M-67/5-12-73 — Conciliation letter sent to the parties by the Assistant Labour Commissioner (Central-I), Madras.

Ex. M-68/6-12-73 — Letter from the Enquiry Officer to the Management re-opening the exparte enquiry.

Ex. M-69/6-12-73 — Letter from the Enquiry Officer to W.W. 1 re-opening the enquiry and posting the enquiry on 12-12-1973.

Ex. M-70/10-12-73 — Letter from the Management to the Regional Labour Commissioner (C), Madras about the strike notice issued by the Union.

Ex. M-71/12-12-73 — Memo of settlement u/s. 12 (3) of the I.D. Act, 1947 between parties.

Ex. M-72/12-12-73 — Letter from W.W.1 to the Enquiry Officer requesting to postpone the enquiry.

Ex. M-73/13-12-73 — Letter intimating the postponement of enquiry sent to W.W.1.

Ex. M-74/13-12-73 — Letter from W.W.1 to the Chairman of the Management requesting to change the enquiry officer.

Ex. M-75/14-12-73 — Reply letter by the Management to Ex. M-74.

Ex. M-76/14-12-73 — Letter from the Management to the Regional Labour Commissioner (C) Madras requesting him to advise the parties to co-operate in the finalization of the enquiry.

Ex. M-77/18-12-73 — Letter from W.W.1 to the Enquiry Officer seeking clarifications.

Ex. M-78/20-12-73 — Notice sent to the Enquiry Officer by the advocate of W.W.1.

Ex. M-79/27-12-73 — Reply letter from the enquiry officer to Ex. M-77 and M-78.

Ex. M-80/27-12-73 — Letter from W.W.1 to postpone the enquiry by one day.

Ex. M-81/25-2-74 — Order of discharge sent to W.W.1.

Ex. M-82/28-2-74 — Strike notice issued by the union

Ex. M-83/28-2-74 — Conciliation letter sent to the parties by the Assistant Labour Commissioner (Central) I, Madras.

Ex. M-84/25-3-74 — Reply letter by the Management on the strike notice, sent to the Regional Labour Commissioner (Central), Madras.

Ex. M-85/16/17-4-74 — Letter from the Management to the Regional Labour Commissioner (Central) Madras requesting to hold the discharge of W.W.1 as valid.

Ex. M-86/27-5-74 — Conciliation failure report.

Ex. M-87/24-7-74 — Letter from the Government of India to the parties stating that no further action could be taken on the failure report because of the stay granted by the High Court.

Ex. M-88/30-1-75 — Notice of the Labour Court communicating the order in C.P. No.2/74 dated 27-1-1975.

Ex. M-89/24-3-75 — Letter from the Government of India to the parties enclosing the reference for adjudication.

(Sd.) T. PALANIAPPAN
Industrial Tribunal.

Note: Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the award.

[No.L-33012/1/74 P & D/CMT/D-IV(A)]

NAND LAL, Section Officer (Spl.)

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5279.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Madras in the industrial dispute between the employers in relation to the Allahabad Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th November, 1975.

BEFORE THIRU T. PALANIAPPAN, B.A., B.L., PRESIDING OFFICER, INDUSTRIAL TRIBUNAL, MADRAS.

(Constituted by the Central Government)

Friday the 31st day of October, 1975

Industrial Dispute No. 11 of 1975

(In the matter of the dispute for adjudication under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the management of the Allahabad Bank, Mount Road, Madras-2).

BETWEEN

Sri R. Paramasivam, Sevial East Street, Vallioor, Tirunelveli District. (Tamil Nadu).

AND

The Manager, Allahabad Bank, 9, Mount Road, Madras-2.

REFERENCE

Order No. L. 12012/53/74/LRIII, dated 10-2-1975 of the Ministry of Labour, Government of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Wednesday the 22nd day of October, 1975 upon persuing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiruvalargal G.. Venkatraman and R. Jamal Nazeem for Tiruvalargal Aiyer and Dolia, Advocates appearing for the worker and of Thiruvalargal M. R. Narayanaswami and S. Jayaraman, Advocate for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

AWARD

By order No. L-12012/53/74/LR.III, dated 10-2-1975 of the Ministry of Labour, Government of India, the following dispute between the workmen and the management of Allahabad Bank has been referred to this Tribunal for adjudication. The issue is as follows :—

"Whether the action of the management of the Allahabad Bank in terminating the services of Shri R. Paramasivan, peon, employed in the Mount Road Branch at Madras is justified? If not to what relief is Shri Paramasivan entitled and from what date?"

2. The claimant Thiru R. Paramasivan has filed a claim statement alleging that he was employed as a peon in the Allahabad Bank, Madras from July, 1969 and after completion of six months service he was confirmed in that post. The grievance of the workmen is that on 1st July, 1972 the Manager of the Bank sent a notice to the petitioner stating that three months notice is given for the termination of his services on the ground that his attendance has been highly unsatisfactory and absented himself without sanction of leave or even without having any leave to his credit. The claimant alleges that in any view of the order it would amount only to a termination of his service for alleged misconduct. But the management without issuing any charge memo and holding any enquiring to prove the alleged misconduct terminated his services in terms of para 522(1) of the Sastry Award. The petitioner went on casual leave on 4-8-1972 and 5-8-1972; that after availing of the casual leave he reported for duty on 6-8-1972 but he was not allowed to join duty. The petitioner alleges that the order of termination is illegal and that paragraph 522(1) of the Sastry Award cannot be invoked to the facts of this case; that the leave applied for has been either covered by leave letter on medical certificates; that the absence without sanction of leave, or overstayal of sanctioned leave amounts to a minor misconduct in terms of para 521(6) of the Sastry Award; that para 521(1) is subject to and conditioned by clause 6 of para 521 that as such in cases covered by para 521(6) of the Sastry award para 521(1) cannot be invoked; that in any event the order of termination which is only a cloak for dismissal in harsh unconscionable and disproportionate to the alleged misconduct.

3. The Management has filed a counter statement contending that the workman was employed in the Bank on 17th July, 1969 on probation for six months as Peon and posted at Madras Branch and subsequently he was confirmed in the Bank's service, notwithstanding that during the probationary period itself he had absented himself for 31 days out of which 28 days' absence was on loss of pay and three days were treated as casual leave; that on perusal of his attendance record in Annexure B to the counter would appear that the workman was a habitual absentee and he used to remain absent without obtaining sanction of leave or even without having any leave to his credit; that he was served with warning notices; that he was absenting himself frequently submitting medical certificates, and so the Bank felt that a thorough medical examination was called for and so he was asked to get himself examined by a Civil Surgeon, but the workman did not submit any medical certificate and that committed violation of leave rules of the Bank. Hence the Bank decided to invoke the provisions of Paragraph 522(1) of the Sastry Award and discharged him from service.

4. ISSUE : Thiru R. Paramasivan, W.W. 1 examined himself to show that he was working as a peon in the Head Office of the respondent bank and that he was giving leave letters at the time of going on leave; that Exs. M-18 to M-48 are leave letters given by him and that the Manager has signed in those leave letters sanctioning leave and that he had taken leave on 4-8-1972 and 5-8-1972 and that when he went to the office on 6-8-1972, the Bank denied employment and did not allow him to work. His further evidence is that no order of termination was given to him and that there was no charge sheet was given to him alleging misconduct. The endeavour on the part of the management was to show that out of a total service of three years he absented himself for about one year. In the course of the cross-examination he admitted that the statement in Annexure B to the counter statement is correct. This Annexure B to the counter statement showing particulars of absence of Sri R. Paramasivam during his service from 17-7-1969 to 5-8-1972. This Annexure B has been marked as Ex. M-51. It gives the particulars of leave (i.e.) casual leave, privilege leave, sick leave and unauthorised leave taken by him. It shows that he was absent for a period of 349 days out of the total service of about 3 years. The fact that he was appointed on 17th July, 1969 is not in dispute. Ex. W. 1, dated 20-7-1972, the order of termination with effect from 1st October, 1972.

5. The learned counsel for the Management referred me to Exs. M.-1 to M-12 to show that he was a habitual absentee without sanction of leave. Ex. M-1, dated 6-10-1969 is the letter written by Sri R. Paramasivan to the Bank. In that letter, he has asked for condonation and sanction of leave on 1-9-1969, 3-9-1969 and 22-9 1969. In that letter he has stated that in future he will inform the Bank in advance about his taking of leave. Ex. M-2 is the reply by the Bank. The respondent Bank has mentioned in Ex. M-2 that the absence of Sri R. Paramasivan from duty is unauthorised and he was directed to join duty forthwith and they declined the request of Sri R. Paramasivan. Ex. M-3, dated 3rd February, 1972 is the letter written by the Management Bank to Sri R. Paramasivan. The Bank has mentioned in it that a report from a Civil Surgeon about his health may be sent and then his leave application will receive further consideration. Ex. M-4 dated 15-4-1972 is a letter written by Sri R. Paramasivan to the Bank. In that letter he has stated that post-influenzial weakness was the cause for his absence. Ex. M-5, dated 15-3-1972 is the letter written by the Management stating that he was required to get himself examined by local Civil Surgeon and submit a medical certificate obtained from him. Ex. M-8 is the letter dated 23rd May, 1972 stating that he was discharged from the Government Hospital only on 22nd May, 1972. Under Ex. M-9, the respondent Bank directed Sri R. Paramasivan to produce the medical certificate. The above documents were referred to only for the purpose of showing that the claimant Sri R. Paramasivan was in the habit of applying for leave and thus

not regular in the matter of attendance. Then finally the Bank under Ex. M-12, dated 20-7-1972, the original of Ex. W-1 terminated the services of Sri R. Paramasivan with effect 1st October, 1972.

6. The learned counsel for the Union urged before me two points. namely, (1) that the discharge of the complainant Sri R. Paramasivan without holding a domestic enquiry into the alleged misconduct is unjustifiable and (2) Paragraph 521 of the Sastry award is not applicable to the facts of our case and that the absence from duty by Sri R. Paramasivan without sanction of leave would amount to a minor misconduct and that paragraph 521(6) of the Sastry Award is alone is applicable and that at the most the punishment is excessive and the punishment contemplated in paragraph 521(7) of the Sastry Award alone should have been imposed. In reply to this argument, the learned counsel for the management argued that Sri R. Paramasivan was a habitual absentee without sanction of leave and that he was dischrged not for any misconduct, but it was only a discharge simplicitor and as it was not for misconduct, paragraph 522(1) of Sastry Award alone is applicable and in case of Tribunal is satisfied that the discharge is bona fide, no interference is called for.

7. The documents referred to by him in the above paragraph show that Sri R. Paramasivan was in the habit of asking for leave and the Bank not granting the same and finally his services were terminated under Paragraph 522(1). Paragraph 522(1) of the Sastry Award reads as follows :—

> "In cases not involving disciplinary action for misconduct and subject to clause (6) below, the employment of a permanent employee may be terminated by three months' notice of on payment of three months' pay and allowances in lieu of notice. The services of a probationer may be terminated by one month's notice or on payment of a month's pay and allowances in lieu of notice."

After referring to this paragraph 522(1) of the Award, the learned counsel for the management interpreted the words "in cases not involving disciplinary action for misconduct in paragraph 522(1) to mean as cases where the management does not chose to take a disciplinary action for misconduct but merely terminate the services of the employee." Thus he argued that it is not obligatory on the part of the Management in all enumerated categories under paragraph 521 to have recourse to paragraph 521(7). The relevant portions of paragraph 521(6) of the Satry Award reads as follows :—

> "(6) By the expression "minor misconduct" shall be meant any of the following acts and omissions on the part of an employee ;
>
> (a) absence without leave or overstaying sanctioned leave without sufficient grounds ;
>
> (b) unpunctual or irregular attendance ;"

Paragraph 521(7) of the Sastry Award reads as follows :—

> "(7) An employee found guilty of minor misconduct may;
>
> (a) be warned or censured; or
>
> (b) have an adverse remark entered against him, or
>
> (c) have his increment stopped for a period not longer than six months."

The Management wants to treat the habitual absence without sanction of leave as a case which would not involve disciplinary action. But paragraph 521(6) of the Sastry Award shows that absence without leave or overstaying sanctioned leave without sufficient grounds would amount to minor misconduct. In the instant case, admittedly Sri R. Paramasivan absented himself without senction of the leave. So it would clearly come under the category of minor misconduct. If really the Tribunal consisting of Sri S. Panchapagesa Sastry, Chairman, Sri M. L. Tannan, Member and Sri V.L.D. 'Souze, Member which passed the Award Known as Sastry Award had intended to mean that cases contemplated in paragraph 522(1) of the Sastry Award would refer the cases where the Management does not choose to take disciplinary action for misconduct, the Tribunal would have clearly stated so and not as the case not involving disciplinary action. To my mind, it appears that cases not involving disciplinary action mean only cases not enumerated in paragraph 521(6) of the Sastry Award. Admittedly, the Management did not hold any domestic enquiry before passing the order of termination of the services. The Bank should have held a domestic enquiry and given an opportunity to the workman to explain why he was suffering from that chronic illness and absented himself without sanction of leave and considered his explanation and come to a conclusion whether the explanation offered by him is acceptable or not. In my opinion, it is not proper to terminate his services without holding a domestic enquiry.

8. The learned counsel for the management referred me to a decision reported in 1969 II L.L.J page 799 (Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Vs. Prasad (S. C.) and another), and relied on the following observations. It is as following :—

> "As against the said Dubey it was said that on 4 March 1964 one Kurup, a superintendent in the auto division, was grievously assaulted near his residence in Telco colony. On a complaint by the victim, the said Dubey and some others were prosecuted. According to the company it had reason to believe that Dubey had instigated the assault and therefore considered his continuance in its service as prejudicial to its interests. On 30 April, 1964 the company ordered termination of his service giving him wages in lieu of notice. The workmen's case, on the other hand, was that the company viewed with displeasure the said Awasthi and his group of workmen having been elected as office-bearers in the union, that the management sided with the said R. N. Prasad and his group, that the company even dragged the question of election to the High Court, and that as that was of no avail it began to victimise those who followed the said Awasthi. As regards the dismissal of the workmen under reference, their case was that the said enquiries were contrary to the rule of natural justice and company's standing orders and were the result of its anti-union policy. Regarding the termination of service of the said Awasthi, Dubey and Bhuvaneshwar Singh, workmen 8 to 10 in the reference, they said that as no charge-sheet was issued and no enquiry was held against them the orders against them were invalid. They also urged that though a large number of workmen had violated the said orders the company selected only seven of them and ordered their dismissal with a view to victimize them. Their case further was that as there were thefts of cycles when kept in the sheds the union had advised them to take their cycles inside but to keep them in such a way that they would not obstruct the work, that the workmen thereupon started taking their cycles inside, and that there was no incitement to defy the orders by those dismissed on that charge."
>
> "Under Standing Order 47, the company had the power to terminate Dubey's services on giving notice or wages in lieu thereof. No doubt, the fact that the order was couched in the language of a discharge simpliciter is not conclusive. Where such an order gives rise to an industrial dispute its form is not decisive and the tribunal which adjudicates that dispute can, of course, examine the substance of the matter and decide whether the termination is in fact discharge simpliciter or dismissal though the language of the order is one of simple termination of service. If it is satisfied that the order is punitive or *mala fide* or is made to victimize the workmen or amounts to unfair labour practice, it is competent to set it aside. The test is whether the act of the employer is *bona fide*, if it is not, and is a colourable exercise of the power under the contract of service or standing orders, the Tribunal can discard it and in a proper case direct reinstatement."

The learned counsel for the management relied on these observations for the purpose of showing that paragraph 522(1) of the Sastry Award is similar to the Standing Order No. 47 referred to in the decision and that it is open to the Management either to have recourse to 522(1) of the Sastry Award without taking any disciplinary action against

the employee. He further contended that the discharge was only a discharge simpliciter and it is not for misconduct. He laid emphasis on the point, namely, that the section of the employer is *bona fide* and so the order of termination cannot be questioned. The observations extracted from the above ruling cannot help the case of the management for the following reasons : Paragraph 522 of the Sastry Award is not similar to the Standing Order 47 referred to in the decision. Further, paragraph 522(1) of the Sastry Award cannot be said to be one of the terms of the contract of service between the parties. Their Lordships in the above decision at page 808 have observed to the effect that the Company had two alternatives either to act under Standing Order 47 or to take disciplinary action and hold domestic enquiry. But in the instant case, the Bank did not have the alternatives, namely, to terminate the services under the terms of a contract by giving notice. The rights and liabilities of the workmen are governed only by the Sastry Award. The workman was discharged from service for habitual absence. That fact has been mentioned as an item of minor misconduct in the Sastry Award. Hence the Bank has no other alternative except to have recourse to 521(6) and dispose of the case under 521(7) of the Sastry Award. Under those circumstances, it cannot be argued that the Bank can terminate the services by giving notice without taking disciplinary action. So the above decision relied on cannot help the case of the Bank. The next question, is, whether the order of termination has to be set aside. The various correspondence between the Bank and the workman show that the workman was frequently applying for leave and the Bank was not willing to grant the same. In the course of the correspondence, the Bank has hastily passed the order of termination. The circumstances under which the Bank passed the order of termination shows that it is only a colourable exercise of its power to discharge the workman from service. If the Bank had held a domestic enquiry and found him guilty and passed the order of discharge, then it cannot be said that the order is *mala fide*.

9. In the result, an award is passed holding that the termination of the services of Sri R. Paramasivan is not justified. This finding does not mean that he is entitled to get back wages from the date of the termination of his services. The Bank is directed to take the employee back in service within one month from the passing of this award and issue a fresh order of appointment. The back wages is disallowed. The employee succeeded only on technical ground in spite of his being a chronic absentee. Hence he is not awarded any costs.

Dated this, 31st day of October, 1975.

(sd) T. PALANIAPPAN, Industrial Tribunal.

WITNESSES EXAMINED

For Worker:

W.W.1 — Thiru R. Paramasivan.

For Management: Nil.

DOCUMENTS MARKED

For Worker:

Ex. W-1/20-7-72 — Letter from the Bank to W.W.1 stating that the services will be terminated from 1-10-72.

Ex. W-2/10-4-74 — Letter from W.W.1 to the Regional Labour Commissioner (Central) Madras raising dispute under section 2(A) of the Industrial Disputes Act.

Ex. W-3/7-2-73 — Letter from W.W.1 to the Assistant Labour Commissioner (Central) II Madras regarding his non-employment.

Ex. W-4/20-6-74 — Conciliation Failure Report.

For Management:

Ex. M 1/6-10-69 — Letter from W.W.1 to the Bank for sanctioning leave for 21 days.

Ex. M-2/27-8-71 — Letter from the Bank to W.W.1 requiring him to report for duty.

Ex. M-3/3-2-72 — Letter from the Bank to W.W.1 sanctioning 5 days leave.

Ex. M-4/15-4-72 — Reply Letter from W.W.1 to Ex. M-3.

Ex. M-5/15-3-72 — Letter from the Bank to W.W.1 requiring him to submit a medical certificate from Civil Surgeon.

Ex. M-6/7-4-72 — Letter from the Bank to W.W.1 to resume duty forthwith or submit a satisfactory explanation for his absence.

Ex. M-7/29-4-72 — Letter from the Bank to W.W.1 requiring him to furnish Certificate from Govt. Medical Officer.

Ex. M-8/23-5-72 — Letter from W.W.1 to the Bank stating that he was discharged from the Government Hospital and taking treatment in a private hospital.

Ex. M-9/24-5-72 — Letter from the Bank to W.W.1 requiring him to submit a leave application supported by a suitable medical certificate.

Ex. M-10/22-5-72 — Letter from the Bank to the Superintendent, Government Royapettah Hospital, Madras-14 about the ailment of W.W.1.

Ex. M-11/27-5-72 — Letter from the Government Royapettah Hospital, Madras to the Bank stating that W.W.1 was admitted on 20-5-72 for alleged Bug Killer poisoning.

Ex. M-12/20-7-72 — Letter from the Bank to W.W. determinating his services with effect from 1-10-1972.

Ex. M-13/5-8-72 — Letter from the Bank to W.W.1 stating that he was relieved from duty with immediate effect.

Ex. M-14/5-8-72 — Closed undelivered cover addressed to W.W.1. and received back from Post Office along with the postal acknowledgement card (unsigned).

Ex. M-15/26-10-72 — Letter from the Bank to Thiru R. Ganesan, Advocate, 3, Law Chambers, High Court, Madras stating that W.W.1's services were terminated by appropriate notice and they are not prepared to re-instate him in Bank's service.

Ex. M-16/ — Postal acknowledgement dated 28-10-72 addressed to Thiru R. Ganesan, Advocate.

Ex. M-17/ — Attendance Register containing 125 pages.

Ex. M-18/ — Telegram from W.W.1 for sanctioning leave on 12-12-69.

Ex. M-19/12-3-70 — Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave on 12-3-1970.

Ex. M-20/13-3-70 — Letter from W.W.1 to the Bank to grant him sick leave for 13-3-70.

Ex. M-21/18-3-70 — Letter from W.W.1 to the Bank to grant him four days casual leave w.e.f. 23-3-70.

Ex. M-22/6-5-70 — Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for 6-5-70 and 7-5-70.

Ex. M-23/25-5-70 — Letter from W.W.1 to the Bank to grant leave him for 25-5-70 and 26-5-70.

Ex. M-24/30-5-70	— Medical Certificate from Dr. D.A. Nirmala , M.D.
Ex. M-25/15-6-70	— Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for two days on 15th and 16th of June, 1970.
Ex. M-26/17-6-70	— Medical Certificate from Dr. A Dorai.
Ex. M-27/17-6-70	— Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for one day on 17-6-1970.
Ex. M-28/4-7-70	— Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for two days on 4-7-70 and 6-7-70.
Ex. M-29/7-7-70	— Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for 15 days from 4-7-1970.
Ex. M-30/7-7-70	— Medical Certificate from Dr. A Dorai.
Ex. M-31/16-10-70	— Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for one day.
Ex.M-32/4-11-70	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for 3-11-70.
Ex. M-33/17-11-70	— Letter from W.W.1 to the Bank to grant him leave for two days on 16-11-70 and 17-11-70.
Ex. M-34/	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for two days on 11-1-71 and 12-1-71.
Ex. M-35/	— Letter from W.W. 1 to the Bank to sanction him sick leave for 9 days from 11-1-71.
Ex. M-36/5/2/71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for 5-2-1971.
Ex. M-37/9-2-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for 8-2-1971.
Ex. M-38/24-2-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him casual leave for 24-2-71.
Ex. M-39/25-2-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him casual leave for three days from 25-2-71.
Ex. M-40/23-3-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for one day on 22-3-1971.
Ex. M-41/29-3-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for four days on 29-3-71, 30-3-71, 31-3-71 and 1-4-71.
Ex. M-42/21-4-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for 20-4-71.
Ex. M-43/10-5-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for four days from 3-5-71 to 6-5-71.
Ex. M-44/21-8-71	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him medical leave for 23 days from 7-8-1971.
Ex. M-45-19/1/72	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for two days on
Ex. M-46/20-1-72	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for one day on 20-1-72.
Ex. M-47/22/1-72	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for two days on 21-1-72 to 22-1-72.
Ex. M-48/5-8-72	— Letter from W.W. 1 to the Bank to grant him leave for two days on 4-8-72 and 5-8-72.
Ex. M-49/9-10-72	— Advocate's notice issued to the Management Bank regarding the dismissal of W.W. 1.

Sd- T. Palanippan,

Industrial Tribunal

Note :— Parties are directed to take return of their document/s within six months from the date of the award.

New Delhi, the 2nd December, 1975

S.O. 5279.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Delhi in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen, which was received by the Central Government on the 26th November, 1975.

BEFORE SHRI D. D. GUPTA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, DELHI.

(C.G.I.D. No. 50 of 1975)

BETWEEN

The management of Punjab National Bank.

AND

Their workmen.

PRESENT :

Shri V. V. R. No. Rao—for the management.

Shri K. R. Nagpal—for the workmen.

AWARD

The Central Government, on being satisfied that an industrial dispute existed between the aforesaid parties has referred the same for adjudication to this Tribunal by its Order No. L-12012/73/75/D-II/A dated the 4th August 1975 with the following term of reference:—

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank in not granting increment to Shri Nand Kishore Balmiki on 21st July, 1970 and subsequently on 21st July every year is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?

2. When the case came up today for hearing before me, a memorandum of settlement was jointly filed by Shri V. V. R. N. Rao on behalf of the management and by Shri K. R. Nagpal on behalf of the workmen. Both the above-named representatives of the parties verify and admit the terms of settlement Annexure 'A' and seeks an award in terms of settlement. I therefore, pass an award in terms of settlement Annexure 'A' which shall form a part of the award.

20th November, 1975.

D. D. GUPTA, Presiding Officer.

ANNEXURE "A"

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW COURT BUILDING, TIS HAZARI, DELHI-6

(Reference CGID/I.D. No. 50 of 1975)

In the matter of an Industrial Dispute

BETWEEN

The Management of Punjab National Bank, H.O. Parliament St., New Delhi.—Employer.

AND

Its workmen Sh. Nand Kishore Balmiki as represented by the General Secretary, Punjab National Bank Employees' Union, 710, Ballimaran, Chandni Chowk, Delhi.—Workman.

The dispute of the above workman has been referred for adjudication to this Hon'ble Tribunal and the terms of reference read as under:—

"Whether the action of the management of the Punjab National Bank in not granting increment to Sh. Nand Kishore Balmiki on 21st July, 1970 and subsequently on 21st July every year is justified? if not, to what relief is the said workman entitled?"

2. That the Union has filed its statement of claim and the case is now fixed on 20-11-1975 for filing bank's written statement to the aforesaid statement of claim of the union.

3. That the dispute has been discused between the parties and it is prayed that an Award be passed in terms of the settlement on the following terms and conditions:—

TERMS OF AWARD SETTLEMENT

(a) That the bank agrees to change the date of increment of Sh. Nand Kishore Balmiki from 5th May to 21st July each year without payment of any arrears for the past period.

(b) That as a result of change of date of increment, the basic salary of Sh. Balmiki shall be fitted at Rs. 270/- w.e.f. 21st July 1975 as against Rs. 255/ -presently drawn by him.

(c) That the future increment of Sh. Balmiki shall fall due on 21st July each year subject, however, to the condition that he does not remain on leave without pay during the year proceeding the due date of increment.

4. It is prayed that an award be passed in terms of the settlement.

For Punjab National Bank
Employees' Union:

For Punjab National Bank

General Secretary

Sd/-
Sr. Personnel Officer

[L-12012/73/75-D II/A]
R. KUNJITHAPADAM, Under Secy.

New Delhi, the 26th November, 1975

S.O. 5281.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the followng award of the Industrial Tribunal cum Labour Court No. 3 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jamadoba Power House of M/s. Tata Iron & Steel Co., Ltd., P.O. Jealgora, Distt. Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th Nov., 1975.

CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 42 of 1970

PRESENT:

Shri S. N. Johri, B.Sc., LL.M., Presiding Officer.

PARTIES:

Employers in relation to the management of Jamadoba Power House of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad.

AND

Their workmen represented by Tata Collieries Workers' Union, Digwadih, P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad.

APPEARANCES:

For Employers—Shri S. S. Mukherjee, Advocate.

For Workmen—Shri T. P. Chowdhury, Advocate.

INDUSTRY: Power House STATE: BIHAR

Dated, Dhanbad, the 11th November, 1975

AWARD

Government of India in Labour Department by its Order No. 1/9/70-LRII dated the 22nd April, 1970 made a reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication of the industrial dispute between the parties mentioned above on the following point.

"Whether the action of the management of Jamadoba Power House of M/s. Tata Iron & Steel Co. Ltd., P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad, in not paying Category IV wages as per the recommendation of the Coal Wage Board to Ash Trammers is justified? If not, to what relief they are entitled and from which date."

2. The historical circumstances and facts forming the background of this dispute may be usefully summarised as follows for proprly apprehending the gensis, nature and extent of the dispute at the light of the respective claims. Mazumdar Award dated 26-5-56 standardised the categorization and, as confirmed by the Labour Appellate Tribunal, the workers were classified in ten Categories. However, the Central Wage Board for Coal Mining Industry in its report Volume I Page 58 paras 14 & 15 compressed those ten categories of Mazumdar Award into six categories. Colliery trammers were placed in Category IV under the Mazumdar Award, but Categories III to VI of Mazumdar Award were compressed into Category II & III of semi-skilled lower and semi skilled higher workmen respectively in the Wage Board report. Accordingly colliery trammers (time rated) came to be placed in Category III of the Central Wage Board for Coal Mining Industry report Volume II Appendix 5 page 46. Neither the award nor the report considered the case of Asb Trammers as distinguish from colliery trammers.

3. After that an industrial dispute was raised by the workmen (Ash Trammers) of this industry that they could not be equated with the colliery trammers looking to the nature of hazards of the duties that they were required to perform. Hence they raised a demand that as per their job analysis they should be placed in Category VI of Mazumdar Award (as modified by the Labour Appellate Tribunal). Consequently a reference had been made in the following terms under Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 on 21-7-1960 for adjudication:

"Whether the demand of the Ash Trammers of Jamadoba Power House for payment of Category VI wages prescribed in the award of the All India Industrial Tribunal (Colliery Disputes) as modified by the decision of the Labour Appellate Tribunal is justified? If so, from what date after 16-4-1959 should be paid."

4. Shri G. Palit the then Presiding Officer of the Tribunal to which the aforesaid reference No. 34 of 1960 had been so made, gave an award on 18-11-60, placing the workmen (Ash Trammers) in Category V (of Mazumdar Award) holding them entitled to the wages accordingly with effect from 16-4-59. Accordingly the wages of the Ash Trammers were revised and they got better wages as compared to the colliery trammers, who were in Category IV and Mazumdar Award).

5. The industrial peace thus restored was again disturbed when the dispute was raised by some of the workmen for the general implementation of the Wage Board's recommendations. A wage Board Joint Implementation Committee was formed. It held meetings on 14-6-68 & 25-6-68 and came to a settlement on the question of categorization/gradation of the various workers looking to their job contents, but unfortunately the case of ash trammers was not specifically considered and in the last but one paragraph of the conclusion (M-6) the settlement expressed that there shall be no change in the existing wage structure of other workers impliedly—including the Ash Trammers. After that the present dispute has been raised specifically taking up the case of Ash Trammers.

6. The case of the employer is that Ash Trammers are semi skilled workmen. They have been correctly placed in Category III in the Wage Board report and Central Joint Wage Implementation Committee has also not recommended

any change in their wage structure. Due to the mechanization of tramming conditions in the Power House there had been considerable change in the working condition of the ash trammers resulting in considerable reduction of the workload. Previously the ash trammers were required to do the opening and cleaning of three heavy drop gates on tram lines. That is no more to be done. Similarly the haulage distance of 800 ft. has now been reduced to 150 ft. The trammers, who were previously required to travel along with the tubs and bring back the rope clip, have no more to do so. Previously the trammers after crossing haulage distance of 800 ft. had to push the tubs to a distance of 150 ft. on the ash heap and then had to tipple them manually at the end of the ash dump and then rerail them and push them back upto the haulage point. This work has been mechanised hence totally eliminated so far as the manual labour of the ash trammers is concerned. They have just to put the tub in the tipplers and the same are mechanically tippled in bunkers. Thus according to the management it is incongruous to raise a demand for higher wages even when the workload has comparatively reduced considerably.

7. The case of the workmen is that though the mechanisation has reduced the haulage distance yet it has increased the frequency and the introduction of the machinery demands more skilled working. Looking to the hazardous job contents in as much as they are almost required to play with fire and also because they have to perform the additional duties of clipman, pointsman, signalman and the coupler as compared to colliery trammers, they want that they should be placed in Category IV of Wage Board report i.e. in the category of skilled junior workmen. The work of the ash trammers is more hazardous then the colliery trammers and it has been so decided in the Palit Award. The settlement mentioned with the Wage Board Implementation Committee, is not binding on the ash trammers vide Section 18 of the Industrial Disputes Act as the present dispute has been raised by Tata Collieries Workers' Union (UTUC) which was not a party to that settlement. Category IV is the category of skilled (junior) workmen as distinguished from Category III which is of semi skilled (higher) workmen. To say it crudely the workers' demand is that the ash trammers should be placed in the wage category of skilled (junior) instead of semi-skilled (higher).

8. Mazumdar Award placed coal trammers in semi-skilled Category No. IV. In Palit Award, Ash trammers were held to be doing more hazardous and arduous job hence they were allotted semi-skilled Category V (of Mazumdar Award). However due to rise from category IV to V (as per Mazumdar Award classification) they were placed in the scale of wages slightly higher to the colliery trammers, but all the same they continued to be treated in semi-skilled higher category in Category III of the Central Wage Board report. Palit Award revised their classification not because of the skill but became of the hazard involved and proved to be more arduous. However upto the time when Palit Award was given then process of mechanisation had not strated in Jamadoba Power House. It is in this background that the question which has been succinctly posed by the order of the reference amounts to saying whether in the changed situation of mechanisation of tramming process the present job content should entitled the ash trammers to be placed in the wage structure of Category IV of skilled Junior workmen.

9. For evaluating the comperative rate of wages and category region-cum-industry formula propounded by the Supreme Court was neither pleaded by the parties nor evidence was adduced on that line. It appears that there is no similar industry in the region which has so mechanised the tramming process. That factor is thus out of consideration. It was observed in Das Gupta Arbitration Award para 5 under Issue No. 4 at page 2829 that—

> "piece rate implies rate per unit output. The working conditions of piece rated trammers differing as they do from region to region, from colliery to colliery or from section to section of the same colliery, the normal output of the trammers in a day could not be uniform or even near approach to that. Consequently there cannot be uniform rate for the piece rated trammers having regard to his working condition e.g. gradient, depth of seam, distance of working, place from the haulage point or where there is no haulage point from the pit month. "

10. Due to the aforesaid variability it is all the more difficult to find a comparable unit. That is why irrespective of the output and unconnected with the wages drawn the category of the trammers was fixed by Mazumdar Award. It is because of this fact that neither party has insisted on the application of region-cum-industry formula. The question of capacity of the industry has also not been raised.

11. The ash trammers in this particular industry have their own peculiar set of circumstances and working conditions. Before mechanisation their job contents left them in Category V (of Mazumdar Award) as per Palit Award which has a binding effect between the parties as it has not been overthrown by a notice under Section 19(6) of the Industrial Disputes Act. On the point of categorisation Palit Award conceived a long term arrangement and therefore on that point its binding force cannot be short lived. Principles of resjudicata are to this extent attracted to the present set of facts.

12. Consideration which impelled the Tribunal in Palit Award to place the Ash Trammers in Category V could not be re-agitated or rejuvinated for the sake of placing them in still better category of skilled workmen. It with amount to saying that Shri Palit committed an error in granting them the semi-skilled Category V (Mazumdar categorization) on the basis of those reasons and circumstances when they were in fact sufficient to raise them to Category IV of the Wage Board report i.e. to the category of the skilled (Jr.) workmen. Such a plea is not open to the workmen because Palit Award was never successfully challenged on that ground and it has thus assumed finality in that respect. In other words the reasons which spent their force after pushing the ash trammers to Category V (Mazumdar categorization) of semi-skilled workmen, could hardly be given a new lease of life or rejuvinated for getting the same workmen raised to the category of skilled workmen. Therefore taking Palit award as the basis and those reasons as spent, some additional reasons in the light of changed circumstances will have to be searched out, pleaded and proved for the purpose of claiming the category of skilled workmen.

13. In Chemical & Pharmaceutical Ltd. Vs. its workmen 1969—I L.L.J. 751 (758) Hon'ble Vaidalingam J. of Supreme Court observed as follows in identical circumstances :

> "The Tribunal is also justified in rejecting the contention of the union that the revision of the dearness allowance must be made denovo ignoring the previous award of Sri Palit. Though noramlly, when a claim for revision of dearness allowance is made and a rise in the cost of living index is established such a claim has to be considered on its merits as held by this Court in Remington Rand case (1962—I L.L.J. 287) .....it cannot be lost sight of in this case that the decision of the Palit Award was affirmed by this Court and the appeals filed by the Company and union were dismissed on the ground that the agreement of 1954 was reasonable and the findings of Sri Palit were on fact. In view of the the Tribunal in our view was perfectly justified in proceeding on the basis that the award of Sri Palit should form the basis for considering the nature of the revision of dearness allowance what would be permissible. We have already referred to various matters adverted by Sri Palit in his award. If really the case of union was as is now sought to be proved before us, that the dearness allowance on prior occasions had not been fixed on a scientific basis and Sri Palit erred in proceeding on such an assumption with reference to previous agreement the proper stage when this question should have been convassed was in the union's appeal before this Court against the award of Sri Palit. Having allowed that appeal to be dismissed as not pressed, it is no longer open to the union to raise those contentions now. We are therefore satisfied that the Tribunal's

finding that Palit Award should form the basis for further consideration of the claim for revision of the dearness allowance is correct."

14. This Tribunal has therefore to start with the assumption that Palit Award, which became final and binding because it could not be successfully assailed, depicted the correct categorization of ash trammers in the light of the circumstances then prevailing. The circumstances of hazard and onerousness of the job were specifically considered in that award.

15. In Patna Electric Supply Co. Ltd. Vs. their Workmen 1964 (II) L.L.J. 148 (S.C.) there was a 1952 award on wage structure but revision of the wages was approved by the Supreme Court only on the finding that there were change of circumstances in the form of rise in the cost of living which warranted general revision of the wage structure. In the present case neither the referenceis so general nor the questions of rise in general cost of living are involved. Therefore within the limited ambit of the reference the question involve in the present case is as to what additional circumstances and facts and what change of circumstances have been pleaded and proved which may call for the revision of that categorization, which was so fixed by the Palit Award.

16. Much stress has been laid on the hazards of the job. It is argued that ash trammers have to play with fire. Half quenched ash falls down in the empty tub when the trammers manually open the hopper. The tub gets heated. Using gunny bag piece insulations, the ash trammers have to push the trolly. The ash is then quenched completely by a jet of water poured from a hose pipe. Three trolleys are then coupled at haulage point. They are hauled up. There a trammer unclips them. Trippler is operated by a trammer and the ash falls down. Slight carelessness on the part of the workmen may result in an accident, which may even be fatal. But it is not of much consequence because carefulness of the worker is always the demand of all machines if otherwise inevitable accidents are to be saved. No premium is paid in any company or working establishment to a workman for being careful on the job. Care is simply a part of his duty.

17. Hazard of the job should play its role in the matter of categorization of workers. Indian National Mines Federation (INTUC) and All India Khan Mazdoor Federation (HMS) stated before Central Wage Board that besides the skill some other factors including the hazard involved in the job should be given due waitage in categorization and fixing of wages. Hazard has thus its weight in the matter of categorization but this aspect of hazard involved in the job received its due weight and consideration in Palit Award. Neither it is alleged nor proved that due to mechanization or other change of circumstances the job hazards have increased. It is true that increased hazards demand increased efficiency or skill on the part of the worker but as said above increase in hazard has neither been alleged and much less to say that there is any evidence to prove it. Ordinary hazard of the job received its due consideration in Palit Award as said above and the same prop of hazard cannot be raised for further bolstering the claim of the workmen for being placed in skilled category as against the present semi-skilled one.

18. Fatigue involved can also be one of the considerations. Whereas almost the identical evidence of Shri Girish Kumar MW-1 as well as of Sri Kabir Mia WW-1 as well as the note of inspection made by my learned predecessor proved that instead of travelling 800 ft. with the tubs the ash trammers have now after re-organization of tramming condition in 1968 have to travel hardly 150 ft. There is force in the argument of learned Counsel for workers Sri T. P. Chowdhury that this relief in distance travelled every time stands balanced or neutralized by the rise in frequency because of mechanisation. Again there is no evidence or allegation of any increase in fatigue involved in the work of the ash trammers.

19. Though on the one hand the workers have been relieved of the operation of the drop gates, they have on the other hand now to deal with 4 boilers instead of 3, and 5 ash hoppers instead of 3 which existed previously as the newly installed boiler has 2 ash hoppers. Again a convenience on one side has been counter balanced by some addition of work on the other side, but that can also not be called as increase in work resulting in more fatigue.

20. It is again true that ash trammers are doing the job not only of trammers but also of tripplers (category III-6), slusher (category III-8), haulage khalasi (category III-7) and ash cleaners (category 1-21), but none of the workers doing this job individually has been placed in Category IV in the Wage Board report and simple multiplicity of the kinds of jobs falling within the same or lower categories will, not, due to their cumulative effect, entitle the workers be placed in higher category i.e. Category IV. Four semi-skilled or unskilled workmen cannot conjointly make a skilled workman. Moreover this multiplicity of jobs was considered in Palit Award and was made a ground for declaring them superior to coilliery trammers and for granting them slightly higher category as compared to colliery trammers. The same ground cannot again provide a valid reason for giving further rise in the category.

21. While doing this categorization Mazumdar Award defined semi-skilled worker as, 'one who is either engaged in highly repetitive operations where sequence is wholely predetermined or one whose work involves an opportunity of independent judgement within the limits of the work entrusted to him'. Judged from the criteria so prescribed in the aforesaid definition ash trammers can be categorized only as semi-skilled workmen however high they may be placed in that category. They are doing only highly repetitive work where sequence is fully pre-determined. They have to open the hopper, clip the trolleys, push them filled with partly quenched ash, cool them by hose pipe jet, couple them for haulage and for the trippler. This process they have to repeat every time. They have not to take a decision or not to apply their mind for determining the sequence. They have no discretion in the matter and the sequence is thus wholely predetermined.

22. As against that skilled workers are those who within the limits of each trade or craft determine the sequence of operation and are responsible for accurracy of final results. The job analysis of ash trammers even at present, does not disclose that they determine the sequence of operation and are responsible for the accurracy of the final results. As such the workers have not been able to show that they can be categorized as skilled workmen (Jr.) under Category IV of the Wage Board report.

23. The allegation of the workers that against the direction contained in 1968 Palit Award, they have been placed one category below has no legs to stand as no evidence was produced in support of this plea raised in para 6 of the written statement nor was it pressed in arguments. This could well be a subject matter of an application under Section 33(c) of the Industrial Disputes Act before a Labour Court as it involves only a question of computation of benefits under an adjudication. The matter is thus beyond the scope of enquiry which is being made by this Tribunal within the circumscribed limits of the question posed in the order of reference.

24. Lastly it was argued that in case the Tribunal does not find an air of justification in the claims of ash trammers that they should be placed in Category IV, it can always grant them some relief by evolving a new wage structure for them within the limits of that category in which they have already been placed. There may not be any dispute with the principle but it appears that in this respect reliance has been incorrectly placed on Birla Cotton Mills case Vol. VI—S.C.L.J. 4060, where such a question never arose for consideration. However this need be done only when there is a finding that after Palit Award there had been a change of circumstances by the re-organisation of tramming process casting more onerous duty, additional fatigue, increased hazard and the like on the workmen but as discussed above the reorganization may have only brought some relief rather than increase in the burden on the workers. In the light of these findings revision of their wage structure even within the frame work of Category III does not appear to be necessary.

25. I am therefore of the view that for the reasons given above, the management of Jamadoba Power House of M/s. Tata Iron and Steel Company Limited, P.O. Jealgora, Dist.

Dhanbad is not unjustified in not paying Category IV wages to the Ash Trammers. The reference is answered accordingly.

S. N. JOHRI, Presiding Officer.

[F. No. 1/9/70-LR II]

G. S. SAXENA, Under Secy.

11th November, 1975

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1975

का० आ० 5282.--केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत्, यांत्रिक, सिविल) श्रमिक संघ, दिल्ली करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है;

और अतः उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उप धारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को उसमें वर्णित व्यक्ति के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 26 नवम्बर, 1975 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

करार

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन

के बीच

पक्षकारों के नाम:

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :	(1)	श्री एच० के० सेठ, सहायक इंजीनियर (विद्युत्) प्रभाग संख्या-1
कर्मकार का प्रतिनिधित्व करने वाले :	(1)	श्री टी० सी० सेठी, अवैतनिक महासचिव, अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत्, यांत्रिक, सिविल), श्रमिक संघ, दिल्ली।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच० एच० कुरैशी, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) 7/201, स्वरूप नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है :--

(1) विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :	क्या कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत्) लोक निर्माण विभाग, विद्युत् प्रभाग, संघ 1, दिल्ली प्रशासन की श्री प्रेमलाल स्टोकर की वायरमैन के पद के लिए परीक्षा/साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् सहायक वायरमैन के रूप में प्रोन्नति करने की कार्यवाही वैधानिक और न्यायोचित है ? यदि हां नहीं उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?
(2) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	(1) कार्यकारी इंजीनियर (विद्युत) लोक निर्माण विभाग, विद्युत् विभाग संख्या-1, दिल्ली प्रशासन, मनलाईट, आसफअली रोड, नई दिल्ली। (2) अवैतनिक महासचिव, अखिल भारतीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत्, यांत्रिक सिविल) श्रमिक संघ, 13/4429, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6
(3) यदि कर्मकार विवाद में स्वयं अन्तग्रस्त है, तो उसका नाम या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम।	अखिल भारतीय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (विद्युत्, यांत्रिक सिविल), श्रमिक संघ 13/1429, पहाड़ी धीरज, दिल्ली-6
(4) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या:	300
(5) विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या :	एक

हम यह करार भी करते हैं कि मध्यस्थ का विनिश्चय हम पर आबद्धकर होगा।

मध्यस्थ अपना पंचाट छः मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

साक्षी

1. हस्त०/-(अपाठ्य)	1. हरिकृष्ण सेठ,
2. हस्त०/-(अपाठ्य)	2. टी० सी० सेठी।

[संख्या एल०-42012(24)/75-डी-2(बी)]

हरबंस बहादुर, अनुभाग अधिकारी (विशेष)

ORDER

New Delhi, the 29th November, 1975

S.O. 5282.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of the Central Public Works Department and their workman represented by All India Central Public Works Department (Electrical, Mechanical, Civil) Labour Union, Delhi.

And, whereas the said employers and workmen have, by a written agreement, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration by the person specified therein, and a copy of the said arbitration agreement has been forwarded to the Central Government.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said arbitration agreement which was received by it on the 26th November, 1975.

AGREEMENT

Under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947,

BETWEEN

Names of the Parties

Representing employers : Shri H.K. Seth, Asstt. Engineer (Elect.) Division No.

Representing workman : Shri T.C. Sethi, Hony. General Secretary, All India Central Public Works Department (Electrical, Mechanical , Civil) Labour Union, Delhi.

It is here by agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H.H. Quaraishy, Regional Labour Commissioner (Central) 7/201, Swaroop Nagar, Kanpur (U.P.)

(i) Specific Matters in dispute :	Whether the action of the Executive Engineer, Electrical Public Works Department, Electrical Division No. 1, Delhi Administration in Promoting Shri Prem Lal Stoker as Assistant Boilerman after he had qualified at the test/interview for the post of Boilerman is legal and justified. If not to what relief is the said workman entitled.
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.	(1) Executive Engineer (Electrical) Public Works Department, Electrical Division No. 1, Delhi Administration, Sunlight, Asaf Ali Road, New Delhi. (2) Hony. General Secretary, All India Central Public Works Department (Electrical, Mechanical, Civil), Labour Union 13/4429, Pahari Dhiraj, Delhi-6.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union if any representing the workman or workmen in question.	All India, Central Public works Department (Electrical, Mechanical, Civil), Labour Union, 13/4429, Pahari Dhiraj Delhi-6.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected.	300
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.	One.

We further agree that the decision of the arbitrator shall be binding on us.

The arbitrator shall make his award within a period of six months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Witnesses :

1. Sd/(illigible)	1. Hari Krishan Sethi.
2. Sd/-(illigible)	2. T.C. Sethi.

[No. L-42012(24)/75-D.II(B)]

HARBANS BAHADUR, Section Officer (Spl.)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110027
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1975.